

वैश्विक महामारी से उबरने के साथ-साथ वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिर से गति पकड़ी, हालांकि घातक संक्रमण वाली दूसरी लहर और अपेक्षाकृत कम हानिकारक तीसरी लहर ने इसके समक्ष समय-समय पर बाधाएँ खड़ी कीं। वर्ष के दौरान आपूर्ति को लगने वाले बार-बार के आघातों से हेडलाइन मुद्रास्फीति में उछाल आया हालांकि, जैसे-जैसे आघातों का असर कम हुआ, लक्ष्यों में प्रतिगमन भी स्पष्ट रूप से देखने को मिला। मौद्रिक और ऋण परिदृश्य भी निभावकारी मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप ही विकसित हुआ यद्यपि, वर्ष के आखिरी चरण में वैश्विक स्पिलओवर के प्रभावों के कारण वित्तीय स्थितियों में थोड़ी सख्ती देखने को मिली और इसने वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ा दी। वर्ष 2022 के प्रारंभ में भू-राजनीतिक जोखिम के तीव्र होने और उससे जुड़ी घटनाएँ वैश्विक परिदृश्य पर हावी रहीं और ईएमई, जिसमें भारत भी शामिल है, पर इसका खतरा सबसे अधिक महसूस किया गया। कर से प्राप्त राजस्व में आयी मजबूत बहाली ने सकल राजकोषीय घाटे को बजट में निर्धारित लक्ष्य के आस-पास सीमित रखने में सहायता की। निर्यात क्षेत्र में लगातार जारी मजबूती और आवक विप्रेषणों में आयी जान ने भुगतान शेष को व्यवहार्य बनाए रखने में आधार का काम किया और साथ ही, निवल पूंजीप्रवाह ने भी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि भंडार को बढ़ाने में योगदान किया।

II.1 वास्तविक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था¹

II.1.1 वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षाधीन अवधि के समष्टि आर्थिक और वित्तीय परिदृश्य को ओमिक्रॉन, बढ़ती खाद्य कीमतों और जड़ मुद्रास्फीति, यूएस फेड के बहुप्रतीक्षित लिफ्ट-ऑफ और वर्ष के अंत में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से वर्ष 2022 की शुरुआत में गहराते टकराव के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। वर्ष 2021 की पहली छमाही में, असमान और अलग-अलग समुत्थान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को पिछले वर्ष में महामारी द्वारा लगाए गए गहरे संकुचन से बाहर निकाल दिया। अप्रैल 2022 के अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, पिछले वर्ष में 3.1 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले वर्ष 2021 में विश्व जीडीपी में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021 के प्रारंभिक चरण में कोरोना वायरस के खतरनाक डेल्टा वैरिएंट के कारण एक तेज झटके के बाद, वैश्विक सुधार ने कुछ गति हासिल कर ली थी, भले ही विकास के रास्ते मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रोत्साहनों के

आकार और स्थायित्व तथा टीकों तक पहुँच के दृष्टिकोण से व्यापक रूप से भिन्न थे। वैश्विक विकास ने वर्ष की दूसरी छमाही में कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक लेकिन कम घातक संस्करण – ओमिक्रॉन के कारण अपनी गति खो दी। इन लहरों के द्वारा वैश्विक आपूर्ति शृंखला और रसद आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधानों के बावजूद, वैश्विक व्यापार वर्ष की दूसरी छमाही में ठीक हो गया और इसमें वर्ष 2021 में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तेजी को रेखांकित करते हुए, वैश्विक विनिर्माण वर्ष 2020 के 4.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021 में 9.4 प्रतिशत हो गया²।

II.1.2 यहां तक कि पेंट-अप खर्च के पुनः आरंभ से सकल मांग को मजबूत किया, आपूर्ति में लगातार व्यवधानों ने अमेरिका, यूरो क्षेत्र और कई उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मुद्रास्फीति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया। पण्य की कीमतें वर्ष 2021 में एक साल पहले के निचले स्तर से तेजी से बढ़ीं क्योंकि मांग में बढ़ोतरी का टकराव आपूर्ति बाधाओं से हुआ। जबकि राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां काफी हद तक निभावकारी बनी रहीं, लक्ष्यों से ऊपर चलती

¹ कीमतों, वित्तीय बाजारों, राजकोषीय और बाहरी क्षेत्रों से संबंधित वैश्विक विकास को भी इस अध्याय के संबंधित खंडों में शामिल किया गया है।

² संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ)।

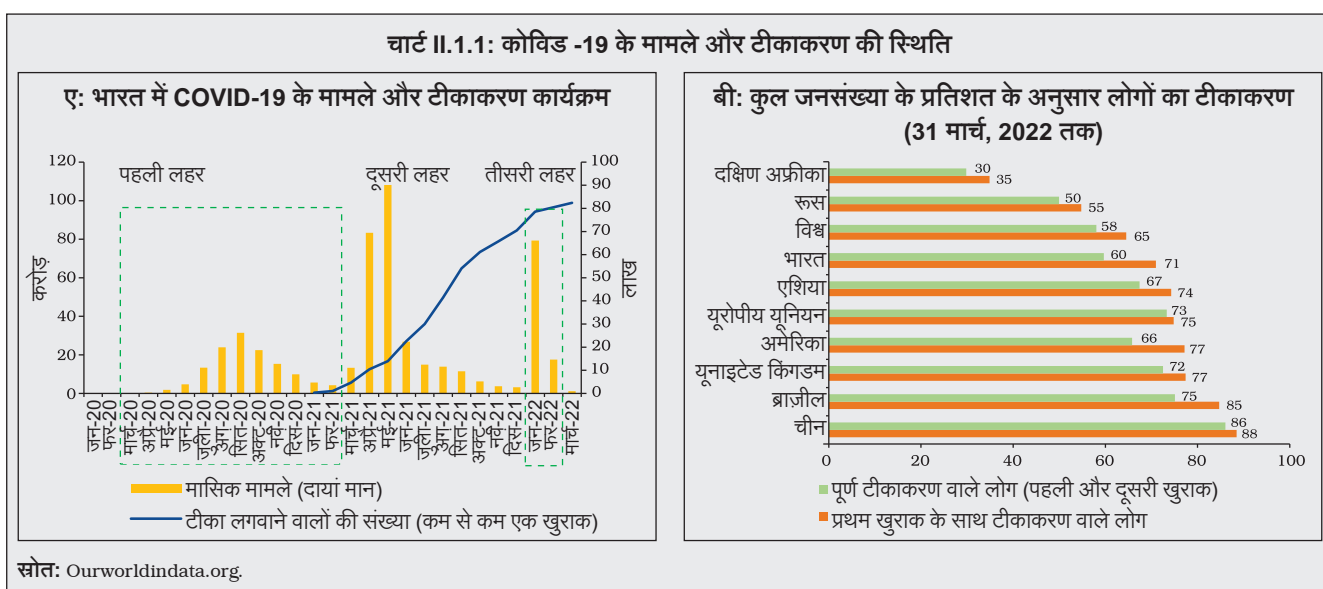
मुद्रास्फीति ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के केंद्रीय बैंकों तथा कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को कठोर मौद्रिक नीति अपनाने के लिए मजबूर किया। महामारी से प्रेरित चलनिधि का टेपर, वित्तीय स्थितियों को बाधित किए बिना किया जा सकता है। वित्तीय बाजारों में, जोखिम-रहित भावना ने इक्विटी बाजारों को सुधार की ओर अग्रसर किया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के मंद सरकारी बांड बाजार के वास्तविक प्रतिफल में बढ़ोत्तरी हुई। जैसे ही अल्पकालिक प्रतिफल ने मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव को प्रतिबिंबित करना शुरू किया, प्रतिफल वक्र के परिणामी गिरावट ने वैश्विक विकास गति को वर्ष 2021 के अंत और वर्ष 2022 की शुरुआत में कम होने की ओर इशारा किया। भू-राजनीतिक संघर्ष के साथ जोखिम से बचने के कारण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनः मूल्य निर्धारण हुआ। नतीजतन, सोने की कीमतों में उछाल आया है, यह स्टैगफ्लेशन की चिंताओं और दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण भी सीमित है। निवेशकों को एक बहुत ही अलग गतिशीलता का सामना करना पड़ता है क्योंकि राजकोषीय और मौद्रिक नीति सहायता ईई और ईएमई में समान रूप से

उच्च और निरंतर मुद्रास्फीति दबाव के साथ सार्वजनिक ऋण³ के ऊंचे स्तर के सामने फीकी पड़ जाती है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

II.1.3 वर्ष 2021-22 में, भारत ने आर्थिक बहाली के साथ अपने प्रयास को नवीनीकृत किया, जो वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में पहली लहर की समाप्ति के साथ शुरू हुआ था। दूसरी लहर गंभीर थी और देश को यकीनन अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकट में धकेल दिया (चार्ट II.1.1)। कुछ अपरंपरागत उपायों सहित, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक, विनियामक और चलनिधि उपायों द्वारा तथा लगातार जारी राजकोषीय उपायों और अनुकूल वित्तीय स्थितियों के समर्थन से वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी में उछाल आया और वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही की तुलना में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के महामारी पूर्व के स्तर से 6.2 प्रतिशत आगे बढ़ने के साथ रिकवरी और तेज हो गयी। चौथी तिमाही में, हालांकि, ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा संचालित महामारी की तीसरी लहर और हाल ही में, भू-राजनीतिक संघर्ष ने रिकवरी की गति को धीमा किया है और परिदृश्य को गंभीर बना दिया है।

चार्ट II.1.1: कोविड -19 के मामले और टीकाकरण की स्थिति



³ अध्याय I के फुटनोट 6 का संदर्भ लें।

II.1.4 पहली लहर के विपरीत, महामारी की दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव लॉकडाउन की स्थानीय प्रकृति और महामारी प्रोटोकॉल के लिए बेहतर अनुकूलन क्षमता के कारण नियंत्रित था। जून 2021 से दूसरी लहर के कम होने से वृद्धि संवेग में पुनः तेजी को टीकाकरण की गति और पैमाने से मजबूती मिली⁴।

II.1.5 वित्तीय स्थितियों की ओर मुड़ते हुए, मुद्रा बाजार में प्रचुर मात्रा में चलनिधि थी, जिसमें अल्पावधि ब्याज दरें रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के न्यूनतम स्तर के अनुरूप थीं, हालांकि नीलामी के लिए चलनिधि के पुनर्संतुलन और फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो से दूरी, द्वितीयक बाजार आस्ति खरीद के माध्यम से बड़े चलनिधि अंतर्वेशन की समाप्ति और नियत तारीखों पर कुछ असाधारण उपायों की समाप्ति के परिणामस्वरूप वे वर्ष की दूसरी छमाही में मजबूती से बने रहे। कर्ज बाजारों में, प्रतिफल वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक हो गए और स्प्रेड बढ़ गए क्योंकि बाजार का रुख सरकारों (केंद्र और राज्यों) द्वारा बड़े पैमाने पर जारी करने और वैश्विक स्पिलओवर की आवर्ती घटनाओं के रूप में दुनिया भर में मौद्रिक नीति के रुख के रूप में बदल गई। भारतीय रुपए (आईएनआर) ने वैश्विक गतिविधियों से अस्थिरता के हर मुकाबले के बाद मजबूत माध्य प्रत्यावर्तन प्रदर्शित करते हुए, सीमाबद्ध कारोबार किया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में निरंतर पूंजी प्रवाह और आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ) के कारण पोर्टफोलियो प्रवाह से भी आईएनआर में तेजी आई। घरेलू इक्विटी सूचकांकों ने वर्ष 2021 में अपने समकक्ष देशों के सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। दो साल के बड़े लाभ के बाद, हालांकि, भारतीय इक्विटी का मूल्यांकन अधिकांश पारंपरिक मानदंडों द्वारा बढ़ाया गया था।

II.1.6 दिसंबर 2021 के अंत में ओमिक्रॉन जनित तीसरी लहर भारत में आई। हालांकि, यह अल्पकालिक साबित हो रही है। उच्च प्रसार वाले संक्रमणों में उछाल के बाद भारी गिरावट

आई - 20 जनवरी 2022 को दैनिक संक्रमण 3.47 लाख नए मामलों और कुल 20.1 लाख सक्रिय मामलों के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद कम होना शुरू हो गया। मृत्यु दर दूसरी लहर की तुलना में बहुत नीचे रही। आर्थिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर पहली दो लहरों की तुलना में तीसरी लहर का प्रभाव संभवतः कम होगा।

II.1.7 इस पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित उप-खंड में सकल मांग का विश्लेषण किया गया है और उसके बाद सकल आपूर्ति की स्थिति का आकलन किया गया है। उप-खंड 4 रोजगार और श्रम बाजार के विकास में एक ड्रिल-डाउन प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष उप-खंड में कुछ नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं।

2. सकल मांग

II.1.8 28 फरवरी, 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों (एसएई) ने संकेत दिया कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापी गई कुल मांग ने वर्ष 2021-22 में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछले वर्ष के 6.6 प्रतिशत संकुचन से ऊपर है (सारणी II.1.1 और परिशिष्ट सारणी 1)। परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद का स्तर वर्ष 2019-20 के महामारी-पूर्व स्तर से 1.8 प्रतिशत अधिक हो गया।

II.1.9 वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, वास्तविक जीडीपी ने दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की जो आधार प्रभावों के क्रमिक रूप से घटने के कारण दूसरी छमाही में कम हो गई। हालांकि, अंतर्निहित गति मजबूत बनी रही, जैसा कि वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक विकास दर (एसएएआर) में तीव्र उछाल से स्पष्ट है, जो बाद की तिमाहियों में अविरत बनी हुई प्रतीत होती है (चार्ट II.1.2 और परिशिष्ट सारणी 2)।

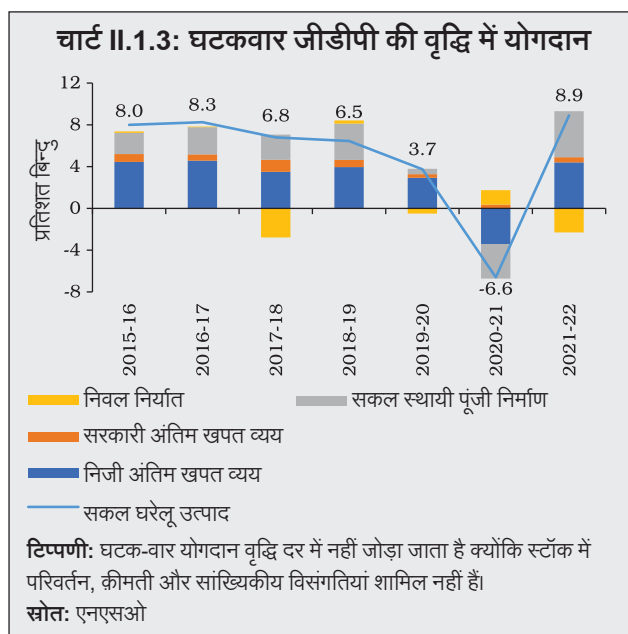
⁴ अध्याय I के फुटनोट 2 का संदर्भ लें

सारणी II.1.1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि

घटक	वृद्धि प्रतिशत				
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
I. कुल खपत व्यय	7.1	7.0	4.9	-4.5	7.2
निजी	6.2	7.1	5.2	-6.0	7.6
सरकारी	11.9	6.7	3.4	3.6	4.8
II. सकल पूंजी विनिर्माण	14.5	6.2	-5.2	-13.8	21.5
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	7.8	11.2	1.6	-10.4	14.6
स्टॉक में परिवर्तन	68.3	27.3	-58.8	-110.7	-1,723.9
मूल्यवान वस्तुएं	40.2	-9.7	-14.2	26.4	63.0
III. शुद्ध निर्यात					
निर्यात	4.6	11.9	-3.4	-9.2	21.1
आयात	17.4	8.8	-0.8	-13.8	29.9
IV. जीडीपी	6.8	6.5	3.7	-6.6	8.9

स्रोत: एनएसओ

II.1.10 वर्ष के दौरान इस बदलाव के भीतर, कुल मांग के घटकों के बीच एक संरचनागत बदलाव आया (चार्ट II.1.3)। निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) ऐतिहासिक मानकों के

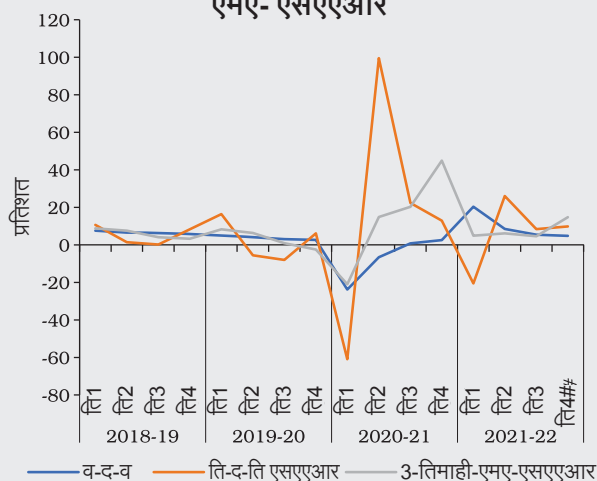


सापेक्ष कमजोर रहा, हालांकि यह अपने महामारी- पूर्व के स्तर को 1.2 प्रतिशत से अधिक करने में सफल रहा। गहन-संपर्क गतिविधि का अभी तक पूरी तरह से सामान्य होना बाकी है और विवेकाधीन खपत खर्च में कर्षण की कमी रही। वर्ष 2021-22 में सरकारी खपत व्यय में तेजी आई, जिससे सकल मांग में वृद्धि हुई। सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में तीव्र उछाल आया, जिसे सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के कारण मुख्य रूप से सार्वजनिक निवेश में आधार मिला। प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय वातावरण के बावजूद निर्यात में मजबूती से सुधार हुआ और वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से इसने सकारात्मक विकास क्षेत्र में प्रवेश किया। आयात मांग बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से प्रेरित होकर चालू खाता वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में अधिशेष से मामूली घाटे में बदल गया।

खपत

II.1.11 निजी खपत, जो भारत में कुल मांग का मुख्य आधार है, ने आंशिक रूप से वापसी की क्योंकि गतिशीलता पर प्रतिबंधों में क्रमिक छूट और टीकाकरण की त्वरित गति के साथ, दोनों ही ने उपभोक्ता विश्वास की बहाली को सक्षम किया। कंज्यूमर

चार्ट II.1.2: जीडीपी वृद्धि : वर्ष-दर-वर्ष तथा 3- तिमाही एमए- एसएएआर



ड्यूरेबल्स पर खर्च में वर्ष-दर-वर्ष सुधार हुआ और विवेकाधीन व्यय ने मुख्य रूप से बदला खर्च का रूप ले लिया। कारकों का एक संयोजन, जैसे, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मजबूत वृद्धि, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के रूप में सरकार से समर्थन, और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं को जारी रखने से आत्मविश्वास बढ़ाने और खपत को बढ़ावा देने में मदद मिली।

II.1.12 दूसरी लहर की तीव्रता के साथ, निजी खपत वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में अपने महामारी-पूर्व स्तर से नीचे गिर गई और उपभोक्ता विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। मई 2021 के महीने में लहर अपने चरम पर थी और उसके बाद, स्थितियों में सुधार होना प्रारंभ होने लगा। बाद के दौरों में, रिजर्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण ने वर्तमान स्थिति और भविष्य की अपेक्षाओं दोनों से संबंधित उपभोक्ता धारणाओं में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया, सिवाय जनवरी 2022 के दौर में कोविड -19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रभाव के चरम पर आयी गिरावट को छोड़कर। पीएफसीई ने वर्ष 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में, वर्ष-दर-वर्ष और साथ ही क्रमिक आधार पर (स्तर के संदर्भ में) सुधार किया। एक उत्साहित त्योहारी मौसम की भावना के साथ युग्मित मांग की रिलीज आंशिक रूप से कोयले, बिजली और विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति की कमी के रूप में आपूर्ति-पक्ष के व्यवधानों से ऑफसेट थी। यह वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान यात्री वाहनों, मोटरसाइकिलों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि में दिखाई दिया। दूसरी ओर, एक उत्साहजनक विकास बैंक ऋण में क्रमिक वृद्धि थी, विशेष रूप से व्यक्तिगत ऋण खंड में। कृषि, एमएसएमई और चुनिंदा सेवाओं के संबंध में ऋण वृद्धि में भी तीव्रता आई।

II.1.13 वर्ष की पहली छमाही के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों में आघात सहनीयता होने के बावजूद, शहरी मांग की तुलना में ग्रामीण मांग के संकेतकों से शिथिलता का पता चलता है। इसके अलावा, प्रचुर मानसून, मिट्टी की पर्याप्त नमी

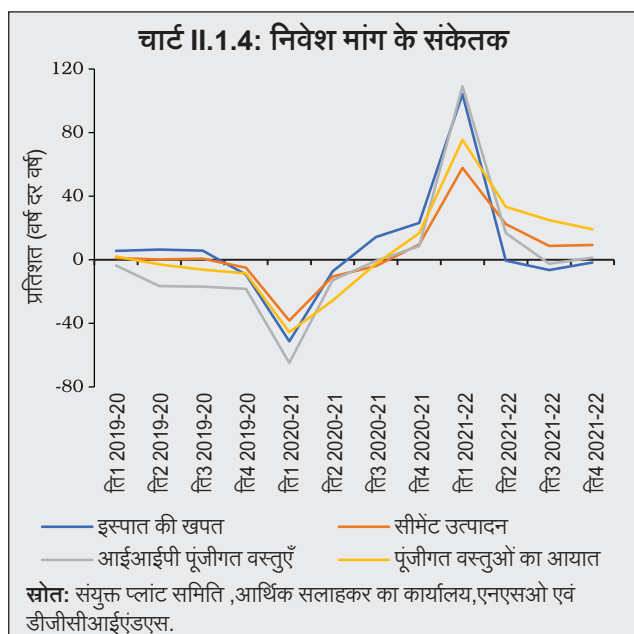
और फिर से भरे हुए जलाशय के स्तर ने शेष वर्ष के लिए इसकी संभावनाओं को उज्ज्वल कर दिया। हालांकि, पिछली तिमाही में मांग में कमी के संकेत दिखाई दिए क्योंकि फर्मों ने लागत दबावों को तेजी से अंतिम उपभोग करने वाले ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया।

निवेश और बचत

II.1.14 भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू निवेश की दर, सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) और मौजूदा कीमतों पर जीडीपी के अनुपात द्वारा मापी गई, जो गत वर्ष के 30.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2020-21 में 27.3 प्रतिशत हो गई। यद्यपि कि वर्ष 2021-22 के लिए जीसीएफ पर आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इसके घटकों में गतिशीलता बुनियादी ढांचे में खर्च द्वारा सरकारी खर्च में वृद्धि का संकेत देती है। वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीएफसीएफ और जीडीपी का अनुपात वर्ष 2020-21 के 30.5 प्रतिशत से बढ़कर 32.0 प्रतिशत हो गया, जो निवेश रुझानों की बहाली को दर्शाता है। अनुकूल आधार प्रभाव के बल पर जीएफसीएफ ने वर्ष 2021-22 में 14.6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की।

II.1.15 जीएफसीएफ के घटकों के बीच, निर्माण क्षेत्र में बहाली को केंद्र सरकार के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के अलावा, अनुकूल ब्याज दरों और डेवलपर्स द्वारा आकर्षक प्रस्तावों से आवास खंड में हुई वृद्धि से सहायता मिली। यह पुनरुत्थान इसके निकटवर्ती सहवर्तिता संकेतक-सीमेंट उत्पादन में स्पष्ट है (चार्ट II.1.4)। इसी तरह की बहाली मशीनरी और उपकरणों में निवेश में दिखाई दी। इसके दोनों निकटवर्ती सहवर्तिता संकेतक - पूंजीगत सामानों के आयात और उत्पादन - ने वर्ष 2021-22 में तीव्र विस्तार दर्ज किया।

II.1.16 रिजर्व बैंक के बही और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के अनुसार, कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 60.0 प्रतिशत तक की गिरावट के बाद दूसरी तिमाही



में 68.3 प्रतिशत तक रिकवर हुआ और यह वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में 72.4 प्रतिशत तक हो गया। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में बिक्री अनुपात की सूची में वृद्धि हुई, जो उन नियंत्रण उपायों को दर्शाती है जिसके तहत अर्थव्यवस्था परिचालित हो रही थी। बिक्री में बाद में सुधार और निर्माण कंपनियों द्वारा बनाए गए इन्वेंट्री के स्थिर स्तर के साथ, इन्वेंट्री टू

सेल्स अनुपात में वर्ष 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमिक रूप से गिरावट आई। औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के 97 वें दौर के उत्तरदाताओं ने आकलन किया कि वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में उत्पादन, क्रयादेश पुस्तक और रोजगार की स्थिति के संदर्भ में मांग की स्थिति में सुधार हुआ, यद्यपि कि यह सुधार वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही की तुलना में धीमी गति से हुआ। वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में क्षमता उपयोग और समग्र वित्तीय स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है, जबकि व्यावसायिक उम्मीदें उच्च बनी हुई हैं, हालांकि आशावाद पिछली तिमाही से कम हुआ है। उत्तरदाताओं ने बिक्री कीमतों में वृद्धि के लिए उच्च आशावाद व्यक्त किया, जो कि वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में इनपुट लागत दबावों के साथ अधिक मूल्य निर्धारण शक्ति का संकेत देता है।

II.1.17 सामान्य सरकारी क्षेत्र की बचत और गैर-वित्तीय निगमों की बचत में गिरावट के कारण सकल घरेलू बचत की दर वर्ष 2020-21 में गिरकर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) का 27.8 प्रतिशत रही जो कि एक साल पहले 29.4 थी। वर्ष 2020-21 में घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत, जो कि निधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है- 3.6 प्रतिशत अंक बढ़कर जीएनडीआई का

सारणी II.1.2: घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई प्रतिशत)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ए. सकल वित्तीय बचत जिसमें:	10.5	10.4	9.9	10.7	10.4	11.9	11.8	11.7	15.5
1. मुद्रा	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.1	2.8	1.4	1.4	1.9
2. जमाएं	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	3.0	4.2	4.2	6.3
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	0.4	0.4	0.5
4. सरकार पर दावे	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6
5. बीमा नीधि	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	2.0	2.0	1.8	2.6
6. भविष्य निधि एवं पेंशन फंड	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5
बी. वित्तीय देयताएं	3.2	3.1	3.0	2.7	3.0	4.3	4.0	3.9	4.0
सी. निवल वित्तीय बचत (ए-बी)	7.2	7.2	6.9	7.9	7.3	7.5	7.8	7.9	11.5

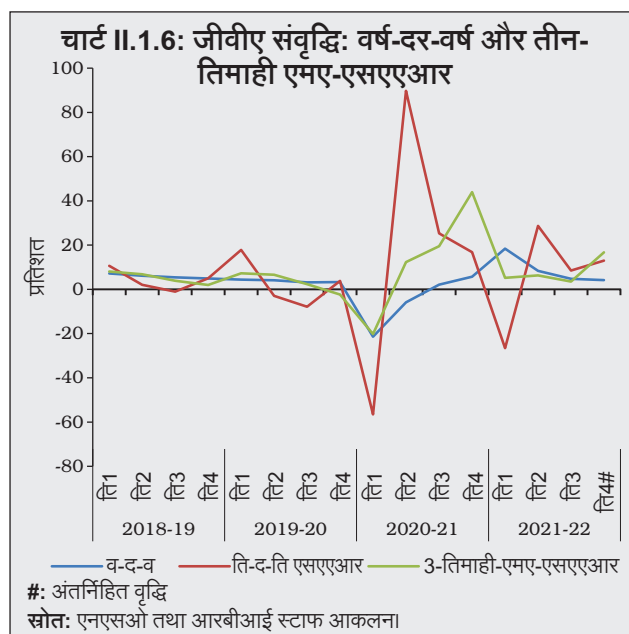
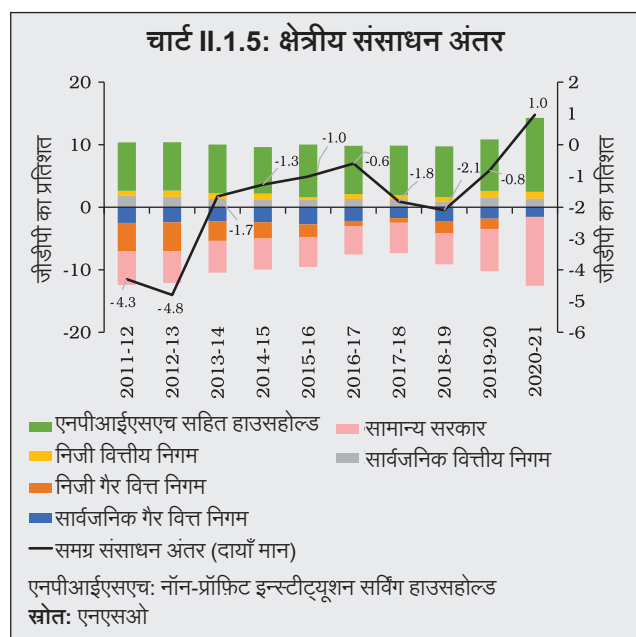
जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय निपटान आय

टिप्पणी: राजडिंग ऑफ के कारण आंकड़े कुल देय की जोड़ के जितने नहीं हो सकते हैं।

स्रोत: एनएसओ

11.5 प्रतिशत हो गई, जो दो दशकों में सबसे अधिक है (सारणी II.1.2 और परिशिष्ट सारणी 3)। महामारी और सहयुक्त बाध्य बचत के बीच विवेकाधीन खर्च में कमी के साथ-साथ परिवारों द्वारा निकट अवधि में आय प्रवाह से संबंधित चिंताओं पर एहतियाती बचत में वृद्धि करने से परिवारों द्वारा बचत को बल मिला।

II.1.18 वर्ष 2020-21 में वर्ष 2004-05 के बाद पहली बार बचत निवेश से अधिक हुई। वर्ष 2020-21 में घरेलू क्षेत्र से अधिशेष सकल घरेलू उत्पाद का 11.8 प्रतिशत था। महामारी के बीच निवेश में कमी के कारण, वर्ष 2020-21 में निजी गैर-वित्तीय निगमों का संसाधन अंतर बंद हो गया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए खर्च में की गई वृद्धि के कारण सामान्य सरकारी क्षेत्र द्वारा बचत पर कमी बढ़ गई (चार्ट II.1.5)।



3. सकल आपूर्ति

II.1.19 मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) द्वारा मापी गई कुल आपूर्ति, वर्ष 2020-21 में 4.8 प्रतिशत के संकुचन को दर्ज करने के बाद वर्ष 2021-22 में 8.3 प्रतिशत तक विस्तारित हुई। महामारी से संबंधित प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे टूटने के साथ, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक विकास दर (एमए-एसएएआर) की तीन-तिमाही चल औसत ने वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में एक सुधार प्रदर्शित किया और वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में आघात-सह बना रहा (चार्ट II.1.6)।

II.1.20 जीवीए वृद्धि में तेजी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में निरंतर सुधार द्वारा सुगम हुई, यद्यपि इसके लिए अनुकूल आधार की आवश्यकता पड़ी। कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के लिए एक आरामदायक सहारा प्रदान किया, जो पूरे वर्ष आघात-सह रहा (सारणी II.1.3)।

सारणी II.1.3: वास्तविक जीवीए संवृद्धि

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021- 22
1	2	3	4	5	6
I. कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना	6.6	2.1	5.5	3.3	3.3
II. उद्योग	6.1	4.9	-2.2	-1.8	10.4
II.1 खनन और उत्खनन	-5.6	-0.8	-1.5	-8.6	12.6
II.2 विनिर्माण	7.5	5.4	-2.9	-0.6	10.5
II.3 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	10.6	7.9	2.2	-3.6	7.8
III. सेवाएँ	6.2	7.1	5.7	-7.8	8.8
III.1 निर्माण	5.2	6.5	1.2	-7.3	10.0
III.2 व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबन्धित सेवाएँ	10.3	7.2	5.9	-20.2	11.6
III.3 वित्तीय, रियल इस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएँ	1.8	7.0	6.7	2.2	4.3
III.4 लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	8.3	7.5	6.3	-5.5	12.5
IV. आधार कीमतों पर जीवीए	6.2	5.8	3.8	-4.8	8.3

स्रोत: एनएसओ

II.1.21 वैश्विक स्तर पर, कोविड-19 प्रेरित शटडाउन के कारण विनिर्माण क्षेत्र और समग्र जीडीपी में उत्पादन हानि हुई। भारत के मामले में, कड़े राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2020-21

के पहली तिमाही में तीव्र संकुचन के बाद कॉर्पोरेट गैर-वित्तीय क्षेत्र के मुनाफे में एक वापसी उछाल आया(बॉक्स II.1.1)।

बॉक्स II.1.1

महामारी के दौरान कॉर्पोरेट का प्रदर्शन: कॉर्पोरेट कर के दर में कटौती की भूमिका

व्यवसाय के संचालन को युक्तिसंगत बनाकर लागत-बचत पर ध्यान केंद्रित करने और सितंबर 2019⁵ (आरबीआई, 2021) में कॉर्पोरेट कर की दर में हुई कटौती ने भारतीय कॉर्पोरेट्स को महामारी सुरक्षित रखा। यह कर कटौती अन्य देशों के साथ लीग में थी जैसा कि आर्थिक सहयोग

और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों में देखा गया था, औसत कॉर्पोरेट आयकर दर 2000 में 32.5 प्रतिशत से घटकर 2018 में 23.9 प्रतिशत हो गई, और इसी तरह के उपाय यूएस और यूके में किए गए (कोप्प व अन्य, 2019)। कर की दर में कटौती से पहले, विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रभावी दर 27.8 प्रतिशत थी, जबकि गैर-विनिर्माण क्षेत्र के लिए, यह औसतन 30.5 प्रतिशत थी, जो भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती थी (सारणी 1ए और 1बी)।

सारणी 1ए: विनिर्माण के लिए प्रभावी कर दर

उद्योग समूह	औद्योगिक जीवीए में हिस्सेदारी*	कर कटौती से पहले प्रभावी कर दर	कर लाभ (प्रतिशत अंक)
1	2	3	4
खाद्य पेय और तम्बाकू	11.1	32.8	7.6
वस्त्र	7.0	27.7	2.5
धातु उत्पाद	15.4	27.4	2.2
मशीनरी और उपकरण	28.1	26.8	1.7
परिवहन उपकरण	13.6	30.9	5.8
परिष्कृत पेट्रोलियम	6.7	21.6	0.0
फार्मास्यूटिकल्स	7.4	25.4	0.2
रबर और प्लास्टिक	4.6	29.5	4.3

*: जीवीए में शेयर्स की गणना राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2021 से 2019-20 के वार्षिक आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज।

सारणी 1बी: गैर-विनिर्माण के लिए प्रभावी कर दर

क्षेत्र	सेवा जीवीए में हिस्सा	कर कटौती से पहले प्रभावी कर दर	कर लाभ (प्रतिशत अंक)
1	2	3	4
थोक और खुदरा व्यापार	20.0	31.4	6.2
परिवहन और लॉजिस्टिक्स	7.7	29.5	4.3
रियल एस्टेट	1.2	26.8	1.6
वित्तीय सेवाएँ	9.5	37.0	11.8
आईटी और संबन्धित सेवाएँ	8.5	29.0	3.9

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज।

(जारी)

⁵ केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट कर की दरों में 30 फीसदी से 22 फीसदी की तीव्र कटौती की घोषणा की। सभी अधिभारों और उपकरों को शामिल करते हुए, प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर (ईटीआर) घटकर 25.2 प्रतिशत हो गई है, बशर्ते कंपनियां किसी अन्य कर प्रोत्साहन या लाभ का लाभ न उठाएं। इसके अलावा, नई निर्माण कंपनियों के लिए, प्रभावी कर की दर 17.0 प्रतिशत होगी, जिससे नए निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

कर की दर में कटौती के अंतर प्रभाव का आकलन करने के लिए एक डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) पैनेल रिग्रेशन इस परिकल्पना का परीक्षण करने का प्रयास करता है कि कम प्रभावी कॉर्पोरेट कर दर (ईटीआर) के संदर्भ में कर की दर में कटौती से लाभान्वित क्षेत्रों के फर्म ने कर-पूर्व कटौती अवधि की तुलना में कर-पश्चात कटौती अवधि के दौरान उच्च निवल लाभ मार्जिन (एनपीएम)⁶ दर्ज किया। कॉर्पोरेट टैक्स की दर में कमी से कर के बाद लाभ (पीएटी) में वृद्धि होगी, मूल्यहास से पहले लाभ, ब्याज और कर (पीबीडीआईटी) अपरिवर्तित रहेगा। चूंकि एक फर्म स्तर पर ईटीआर सीधे उपलब्ध नहीं है, इसकी प्रत्येक फर्म के लिए कुल कर योग्य आय में भुगतान किए गए कॉर्पोरेट कर के अनुपात के रूप में गणना की जाती है (गुहा, 2007)। पूर्व-कर कटौती अवधि औसत की तुलना में कम से कम पांच प्रतिशत अंक की कमी का लाभ लेने वाली फर्म ट्रीटमेंट समूह का गठन करती हैं और शेष नियंत्रण समूह बनाती हैं। इसकी अवधि 2018-19 की पहली तिमाही से 2020-21 चौथी तिमाही तक है। कर-पूर्व कटौती की अवधि 2018-19 की पहली तिमाही से 2019-20 की पहली तिमाही अवधि को कवर करती है, जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही से 2020-21 की चौथी तिमाही की अवधि कर-पश्चात कटौती अवधि का प्रतिनिधित्व करती है।⁷

विनिर्माण और गैर-विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में ट्रीटमेंट समूह में फर्मों के लिए निवल लाभ मार्जिन काफी अधिक हो गया है। कर-पश्चात कटौती अवधि में शुद्ध लाभ मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार हुआ (सारणी 2)। इसके अलावा, लाभप्रदता पर कर की दर में कटौती का प्रभाव विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिक मजबूत है।

संदर्भ:

1. गुहा, अतुलन (2007), 'कंपनी साइज एंड इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्टडी ऑन इंडियन प्राइवेट मैनुफैक्चरिंग कंपनीज', इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल. 42, इश्यू 20, पेज 1869-1874।

सारणी 2: अनुभवजन्य परिणाम

निर्भर चर	एनपीएम विनिर्माण (कर से पहले)	एनपीएम विनिर्माण (कर के बाद)	एनपीएम गैर विनिर्माण (कर से पहले)	एनपीएम गैर विनिर्माण (कर के बाद)
1	2	3	4	5
अवरोधन	26.69* (11.43)	6.4648*** (0.3125)	27.13* (11.29)	15.8048*** (0.4786)
समय (τ)	-13.58 (22.28)	2.3482*** (0.5951)	-13.81 (22.05)	2.1562** (0.9299)
ट्रीटमेंट (θ)	37.45** (13.92)	2.4190*** (0.3830)	36.69** (13.75)	3.8319*** (0.5813)
इंटरैक्शन (δ)	26.12 (27.09)	0.5631 (0.7262)	25.66 (26.77)	0.7052 (1.1268)
टिप्पणियों की संख्या	8269	8269	5934	5934
एफ	27.64	2.764	2.716	20.04
प्रोब>एफ	0.0000	0.04044	0.04315	0.0000

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। ** : 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।
*: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

2. कोप्प, ई, एल. डेनियल, एम. सुसन्ना (2019), 'यू. एस. इनवेस्टमेंट सिंस द टैक्स कट्स एंड जॉब एक्ट ऑफ 2017', वर्किंग पेपर न. 19/120, इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड, वाशिंगटन, डी.सी.।
3. आरबीआई (2021), 'कंट्रोल ऑफ इकनॉमिक रिकवरी', इनआजुरल एंड्रेस बाई श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट 8वीं एसबीआई बैंकिंग एंड इकनॉमिक कॉन्फ्लेव, नवंबर 16, मुंबई।

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

11.1.22 यद्यपि महामारी की दूसरी लहर ने पहली लहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, फिर भी कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने वर्ष 2021-22 में सुदृढ़ प्रदर्शन किया। वर्ष 2021-22 में खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ इस क्षेत्र ने 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। सितंबर 2021 के महीने में दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) और खरीफ की

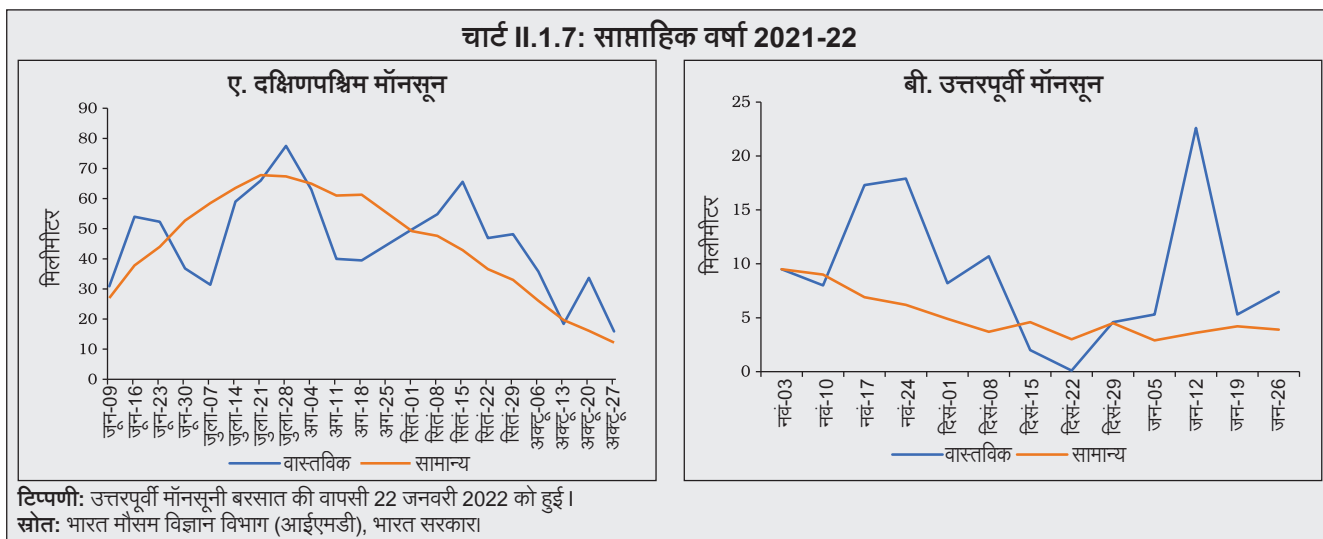
बुवाई में तेज वृद्धि से मजबूत विकास को सहायता मिली। गेहूं और चावल के अतिरिक्त रबी उत्पादन की संभावनाएं मजबूत बुवाई के साथ, पर्याप्त मिट्टी की नमी और फिर से भरे जलाशय के स्तर के साथ उज्ज्वल हुईं। कृषि क्षेत्र में उछाल ट्रैक्टरों और उर्वरकों की बिक्री में दिखाई दिया, जिसने वर्ष 2021-22 के प्रमुख भाग के लिए लगातार महामारी-पूर्व के स्तर को पीछे छोड़ दिया।

⁶ निवल लाभ मार्जिन की गणना निवल बिक्री से निवल लाभ के अनुपात के रूप में की जाती है। कर पूर्व लाभ के मामले में, पीबीडीआईटी के निवल बिक्री के अनुपात का उपयोग किया गया है। लाभप्रदता संकेतकों की गणना के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र(सीएमआईडी) के कौशल आईक्यू डेटाबेस से फर्म स्तर पर कॉर्पोरेट डेटा प्राप्त किया जाता है।

⁷ अनुमानित मॉडल इस प्रकार तैयार किया गया है: $\pi_{ijt} = \gamma_t + \tau \times 1_{t=p} + \theta \times 1_{(i=T)} + \delta \times 1_{(t=p)} \times 1_{(i=T)} + \epsilon_{ijt}$

जहां, π_{ijt} उद्योग में i^{th} फर्म के लिए t^{th} तिमाही में लाभप्रदता संकेतक है। τ समय चर के लिए गुणांक है जिसका मान यदि अवलोकन कर-कटौती अवधि के बाद है तो 1 माना जाता है, अन्यथा 0। ईटीआर में कमी के लिए गुणांक θ है जिसका मान यदि अवलोकन ट्रीटमेंट समूह में आता है तो 1 है अन्यथा 0। δ इंटरैक्शन टर्म के लिए गुणांक को दर्शाता है।

चार्ट II.1.7: साप्ताहिक वर्षा 2021-22



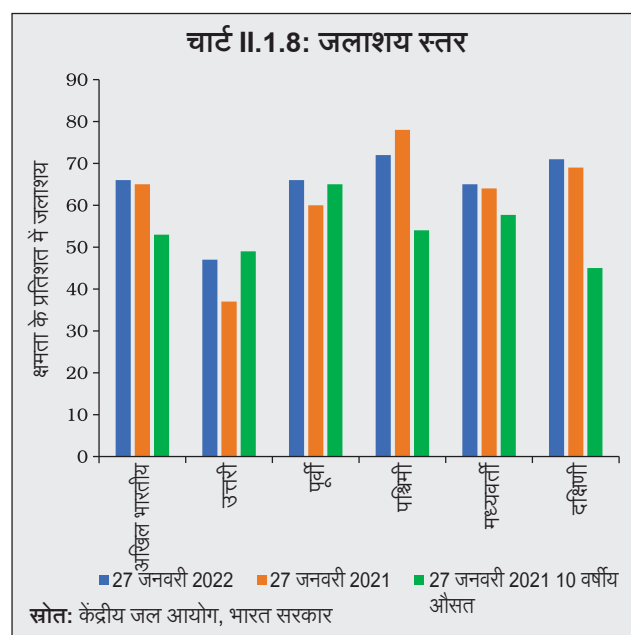
II.1.23 वर्ष 2021 में, 3 जून को एसडब्ल्यूएम ने दस्तक दी, लेकिन जून के अंत से जुलाई के मध्य और फिर अगस्त में राज्यों में वर्षा के असमान वितरण के साथ गति खो दी (चार्ट II.1.7ए)। जुलाई और अगस्त के महत्वपूर्ण बुवाई महीनों के दौरान वर्षा के इन दो कमजोर दौरों के बावजूद, वर्षा बाद में फिर से शुरू हुई और मौसम के लिए 30 सितंबर 2021 तक एक सकारात्मक नोट यानी, 'सामान्य', लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 1 प्रतिशत की कमी के साथ समाप्त हुई। खरीफ की बुवाई जो जुलाई और अगस्त में रुकी हुई थी, बाद में रफ्तार पकड़ी और 30 सितंबर 2021 को पिछले वर्ष के बुवाई के स्तर में 0.2 प्रतिशत और 5 साल के औसत स्तर से 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

II.1.24 इसके बाद, 25 अक्टूबर, 2021 को एसडब्ल्यूएम की देरी से वापसी और पूर्वोत्तर मानसून (एनईएम) के साथ-साथ शुरू होने से अनुकूल मिट्टी की नमी की स्थिति पैदा हुई और जलाशय के स्तर में वृद्धि हुई (चार्ट II.1.7बी)। 27 जनवरी 2022 तक, जलाशय का स्तर 53 प्रतिशत के दशकीय औसत की तुलना में पूर्ण जलाशय क्षमता का 66 प्रतिशत था (चार्ट II.1.8)।

II.1.25 इस वर्ष रबी रकबे में उछाल मुख्य रूप से तिलहन, विशेष रूप से सरसों और रेपसीड, और चना और मसूर की

अधिक बुवाई से प्रेरित था, जिससे गेहूं की कम बुवाई हुई नतीजतन, वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन तीसरे अग्रिम अनुमान (तीसरे एई) में 3,145.1 लाख टन रखा गया है, जो वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमान (एफई) से 1.2 प्रतिशत अधिक है [सारणी II.1.4]। अद्योगामी संशोधन में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 0.5 प्रतिशत (तीसरे एई की तुलना में

चार्ट II.1.8: जलाशय स्तर



सारणी II.1.4: कृषि उत्पादन 2021-22

(लाख टन)

फसल	मौसम	2020-21		2021-22		2021-22 (तीसरी एई) घट बढ़ (प्रतिशत)		
		तीसरी एई	अंतिम	लक्ष्य	तीसरी एई	2020-21 की तुलना में		2021-22 की तुलना में
						तीसरी एई	एफई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अन्न	खरीफ	1,483.6	1,505.8	1,514.3	1,549.3	4.4	2.9	2.3
	रबी	1,570.8	1,601.7	1,558.8	1,595.9	1.6	-0.4	2.4
	कुल	3,054.4	3,107.4	3,073.1	3,145.1	3.0	1.2	2.3
चावल	खरीफ	1,043.0	1,052.1	1,043.0	1,110.4	6.5	5.5	6.5
	रबी	171.6	191.6	168.0	186.2	8.5	-2.8	10.8
	कुल	1,214.6	1,243.7	1,211.0	1,296.6	6.8	4.3	7.1
गेहूं	रबी	1,087.5	1,095.9	1,100.0	1,064.1	-2.2	-2.9	-3.3
मोटे अनाज	खरीफ	355.7	367.5	373.1	356.4	0.2	-3.0	-4.5
	रबी	140.9	145.7	139.0	150.6	6.9	3.4	8.3
	कुल	496.6	513.2	512.1	507.0	2.1	-1.2	-1.0
दालें	खरीफ	84.9	86.2	98.2	82.5	-2.8	-4.3	-16.0
	रबी	170.9	168.4	151.8	195.0	14.1	15.8	28.5
	कुल	255.8	254.6	250.0	277.5	8.5	9.0	11.0
तिलहन (कुल)	खरीफ	245.5	237.2	260.0	247.1	0.6	4.1	-5.0
	रबी	120.1	122.2	124	137.9	14.8	12.8	11.2
	कुल	365.7	359.5	384.01	385.0	5.3	7.1	0.3
गन्ना	कुल	3,928.0	4,054.0	3,970.0	4,305.0	9.6	6.2	8.4
कपास #	कुल	364.9	352.5	370.0	315.4	-13.6	-10.5	-14.7
जूट और मेस्ता ##	कुल	96.2	93.5	106.0	102.2	6.3	9.3	-3.6

#: हरेक 170 किलोग्राम की लाख गाँठें

##: हरेक 180 किलोग्राम की लाख गाँठें

एई: अग्रिम अनुमान

एफई: अंतिम अनुमान

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

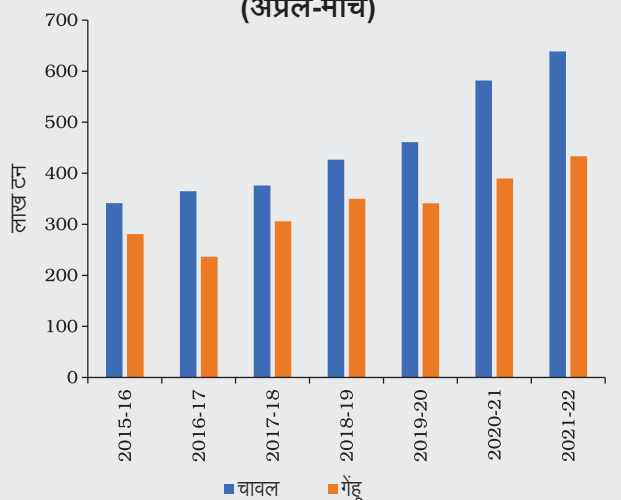
दूसरा एई) रखा गया है जो मुख्यतः वर्ष 2022(मार्च और अप्रैल) में निरंतर गर्म हवाओं से गेहूं की पैदवार कम होने के कारण है। बागवानी फसलों ने वर्ष 2021-22 के दौरान 3,332.5 लाख टन (पहला एई) उत्पादन दर्ज किया, जो टमाटर, अन्य सब्जियों, मसालों, फूलों, सुगंधित और औषधीय पौधों के कम उत्पादन के कारण वर्ष 2020-21 एफई से 0.4 प्रतिशत कम है, जबकि कुल फल और प्याज के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है।

II.1.26 हाल के वर्षों में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप, रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए वर्ष 2021-22 में घोषित

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ने उत्पादन लागत⁸ पर 50 प्रतिशत की न्यूनतम वापसी सुनिश्चित किया। सभी फसलों के दाम 1.1-8.6 फीसदी के दायरे में बढ़ाए गए। वर्ष 2021-22 के खरीफ विपणन सत्र के दौरान 31 मार्च 2022 तक चावल के लिए 503.42 लाख टन की खरीद का स्तर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.2 प्रतिशत अधिक था (चार्ट II.1.9)। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार अनाज का स्टॉक चावल और गेहूं के लिए तिमाही बफर मानदंडों के क्रमशः 7.2 और 1.4 गुना पर संतोषजनक रहा (चार्ट II.1.10)।

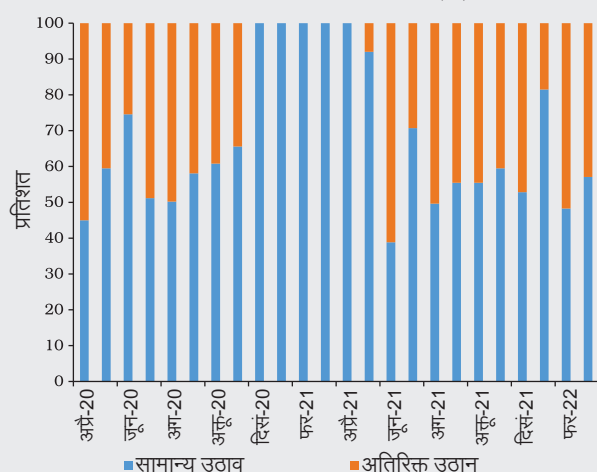
⁸ वास्तविक भुगतान की गई लागत और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य (A2 + FL)

चार्ट II.1.9: चावल और गेहूं की वार्षिक खरीद (अप्रैल-मार्च)



स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट II.1.11: खाद्यान्न का वितरण

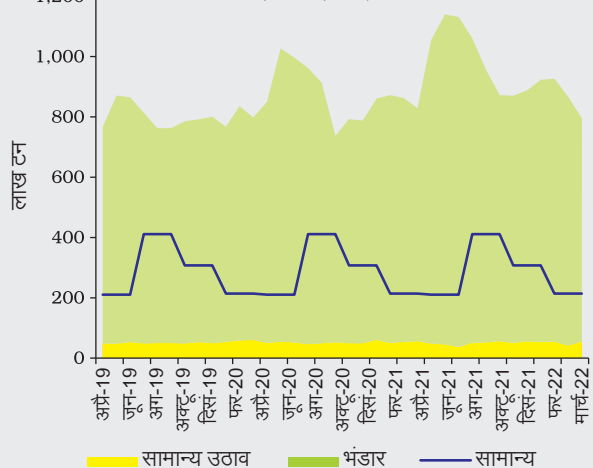


टिप्पणी: नोट: अतिरिक्त उठाव में पीएम-जीकेएवाई, आत्म निर्भर भारत पैकेज (प्रवासी) और गैर-एनएफएसए (कोविड-19) शामिल हैं।

स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

II.1.27 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत सभी

चार्ट II.1.10: अनाज स्टॉक और बफर मानक की मासिक स्थिति



स्रोत: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

एनएफएसए लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के 5 किलोग्राम/व्यक्ति/माह के सामान्य खाद्यान्न के अतिरिक्त मुफ्त वितरण के बावजूद अनाज का स्टॉक स्तर बनाए रखा गया (चार्ट II.1.11)।

II.1.28 हाल के वर्षों में, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वर्षा की अस्थिर तीव्रता, चरम घटनाओं में वृद्धि और बढ़ते तापमान के रूप में कृषि के परिदृश्य और अंततः, समग्र आर्थिक प्रदर्शन के लिए निहितार्थ हैं। इस संबंध में, केंद्रीय बैंकों को व्यापार चक्रों और मौद्रिक नीति के लिए चरम मौसम के प्रभावों के कारण जलवायु जोखिम प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है। वित्तीय क्षेत्र के लिए भौतिक और संक्रमण जोखिमों ने केंद्रीय बैंकों के बीच वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है (बॉक्स II.1.2)।

बॉक्स II.1.2

जलवायु परिवर्तन में केंद्रीय बैंकों की भूमिका

दुनिया भर के केंद्रीय बैंक समष्टि अर्थशास्त्र और वित्तीय स्थिरता के लिए जलवायु जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं (इशिंग, 2021; आरबीआई, 2021; एनजीएफएस, 2020), [सारणी 1]।

दो प्रकार की कार्यप्रणालियों द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस (आईआईएएसए) (मॉडलिंग मुख्य रूप से संक्रमण जोखिम) की स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल (आईएम) और एनजीएफएस-क्लाइमेट एनालिटिक्स (सीए) (मॉडलिंग मुख्य रूप से भौतिक जोखिम) द्वारा, भारत की मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित परिदृश्यों के तहत मूल्यांकन किया जाता है (ए) नेट जीरो 2050 (2050 के आसपास नेट जीरो CO₂ उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य); (बी) भूमण्डलीय ऊष्मीकरण को 2° से. से नीचे सीमित करना (हालांकि अनुमान बताते हैं कि नेट जीरो लक्ष्य के लिए 1.5° से. के लक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है); (सी) अलग-अलग नेट जीरो (उपरोक्त के रूप में नेट जीरो प्राप्त करना, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नीतियों के साथ, जैसे कि तेल के उपयोग के तेजी से चरण के साथ उच्च लागत में प्रवेश करना); (डी) विलंबित संक्रमण (ऐसी नीतियां जो 2° से. लक्ष्य के अनुरूप हैं लेकिन जिसके तहत समायोजन बैकलोड हैं जिसके परिणामस्वरूप 2030 तक वार्षिक उत्सर्जन में कमी नहीं होती है); (ई) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) (जिसके तहत नीतियों को राष्ट्रों द्वारा गिरवी रखा जाता है, भले ही उन्हें लागू न किया गया हो); और (एफ) वर्तमान नीतियां (केवल वर्तमान में प्रतिबद्ध नीतियां लागू की जाती हैं, जिससे कम से कम उत्सर्जन कटौती और उच्च भौतिक जोखिम होते हैं)।

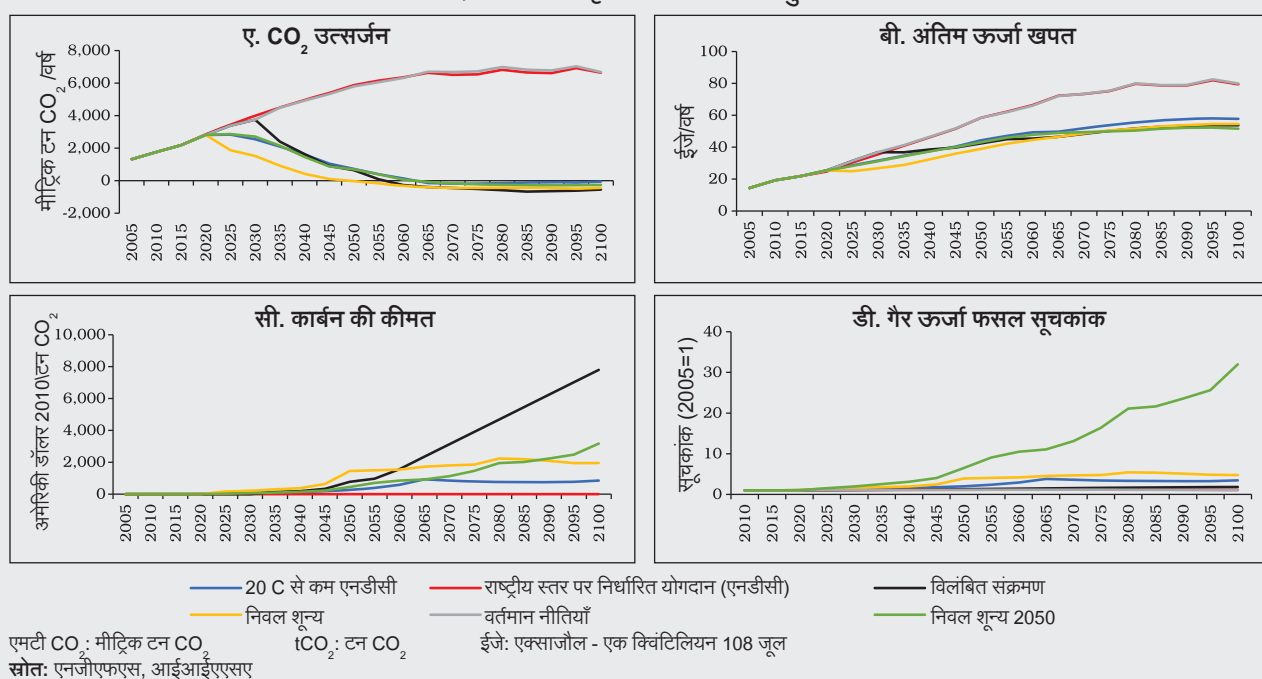
सारणी 1: जलवायु परिवर्तन पर चुनिंदा केंद्रीय बैंकों की प्रतिबद्धताएं

केंद्रीय बैंक	सुनिश्चित प्रतिबद्धता
यूरोपीय सेंट्रल बैंक	"जलवायु परिवर्तन कीमतों की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, हम इससे निपटने के लिए अपने जनादेश के तहत अपनी भूमिका निभाएंगे।"
बैंक ऑफ इंग्लैंड	"हम यहां जलवायु परिवर्तन को "हल" करने या संक्रमण को परिचालित करने के लिए नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय बैंकों की भूमिका तो है, और उस पर एक महत्वपूर्ण भूमिका है।"
फेडरल रिजर्व बोर्ड, यूएसए	"जबकि जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं निर्वाचित अधिकारियों की है, फेडरल रिजर्व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण को संबोधित करने और व्यापक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए हमारे मौजूदा जनादेश और प्राधिकरणों के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)	"... रिजर्व बैंक, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, प्राथमिकताओं और हमारी वित्तीय प्रणाली की जटिलता को ध्यान में रखते हुए (ए) इस बात का अनुसंधान करने कि रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं के तुलन पर, व्यवसाय मॉडल की सुभेद्यता की पहचान करने और उनकी क्षमताओं की कमियों को मापने तथा जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए जलवायु परिदृश्य अभ्यासों का उपयोग कैसे किया जा सकता है; (बी) वित्तीय स्थिरता निगरानी में जलवायु संबंधी जोखिमों को एकीकृत करने; और (सी) विनियमित वित्तीय संस्थानों के बीच जलवायु संबंधी जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों और तदनुसार उनसे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

स्रोत: केंद्रीय बैंकों की वेबसाइटें और आरबीआई (2021)

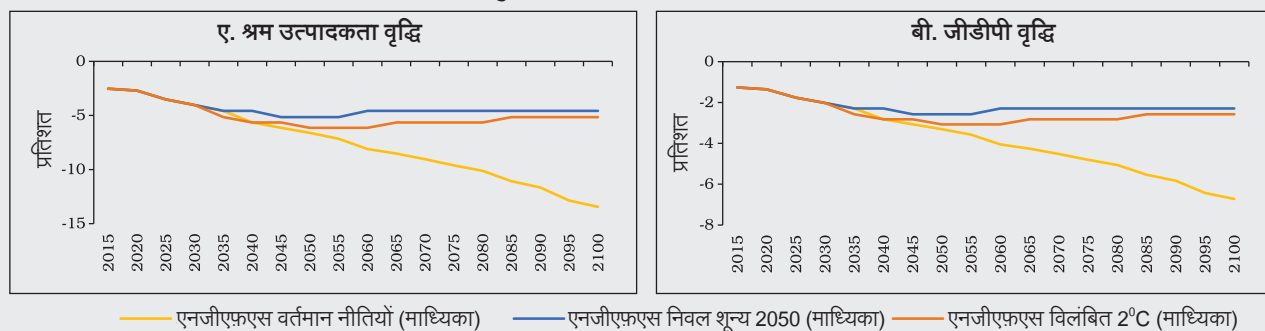
तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक समन्वय से जुड़े परिदृश्यों के तहत ऊर्जा खपत और CO₂ उत्सर्जन में काफी कमी आई है (चार्ट 1)।

चार्ट 1: भारत के लिए विभिन्न परिदृश्यों के तहत जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ



(जारी)

चार्ट 2: जलवायु परिवर्तन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव



स्रोत: एनजीएफएस सीए, केएलईएमएस डेटाबेस (पूजी (के), श्रम (एल), ऊर्जा (ई), सामग्री (एम) और सेवाएं (एस)), और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

हालांकि, वे पण्य और कार्बन की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि से जुड़े हैं। उच्च इनपुट लागत के बाद उच्च कार्बन की कीमतें मुद्रास्फीति में फ्रीड कर सकती हैं। इसके विपरीत, 'एनडीसी' और 'वर्तमान नीतियों' परिदृश्य मुद्रास्फीतिकारी नहीं हैं, लेकिन वे लंबे समय तक चलने वाले भौतिक जोखिम के साथ आ सकते हैं।

एनजीएफएस-सीए मॉडल का उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि भौतिक जोखिम भारत के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि उत्सर्जन में कमी के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं, हालांकि मुद्रास्फीति, 'वर्तमान नीतियों' के परिदृश्य की तुलना में उत्पादन वृद्धि में सीमित नुकसान का कारण हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ उत्पादन और उत्पादकता में काफी नुकसान हो सकता है (चार्ट 2)।

संक्षेप में, 'वर्तमान नीतियों' के परिदृश्य में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से या एक साथ भौतिक और संक्रमण जोखिम अधिक हो सकते हैं। भारत

के लिए उत्सर्जन में कमी के सफल कार्यान्वयन में मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वक तैयार की गई संक्रमण योजनाओं के माध्यम से प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। संक्रमण से जुड़े आउटपुट नुकसान सीमित हो सकते हैं।

संदर्भ:

1. इशिंग, ओ. (2021), 'सेंट्रल बैंक्स-इंडिपेंडेंट ऑर ऑलमाइटी?' सेफ पॉलिसी लेटर, न. 92।
2. एनजीएफएस (2020), 'गाइड फॉर सुपरवाइजर्स इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट-रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल रिस्कस इंटू प्रूडेंशियल सुपरवीजन'।
3. आरबीआई (2021), 'स्टेटमेंट ऑफ कामिटमेंट टू सपोर्ट ग्रीनिंग इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम- एनजीएफएस', रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।

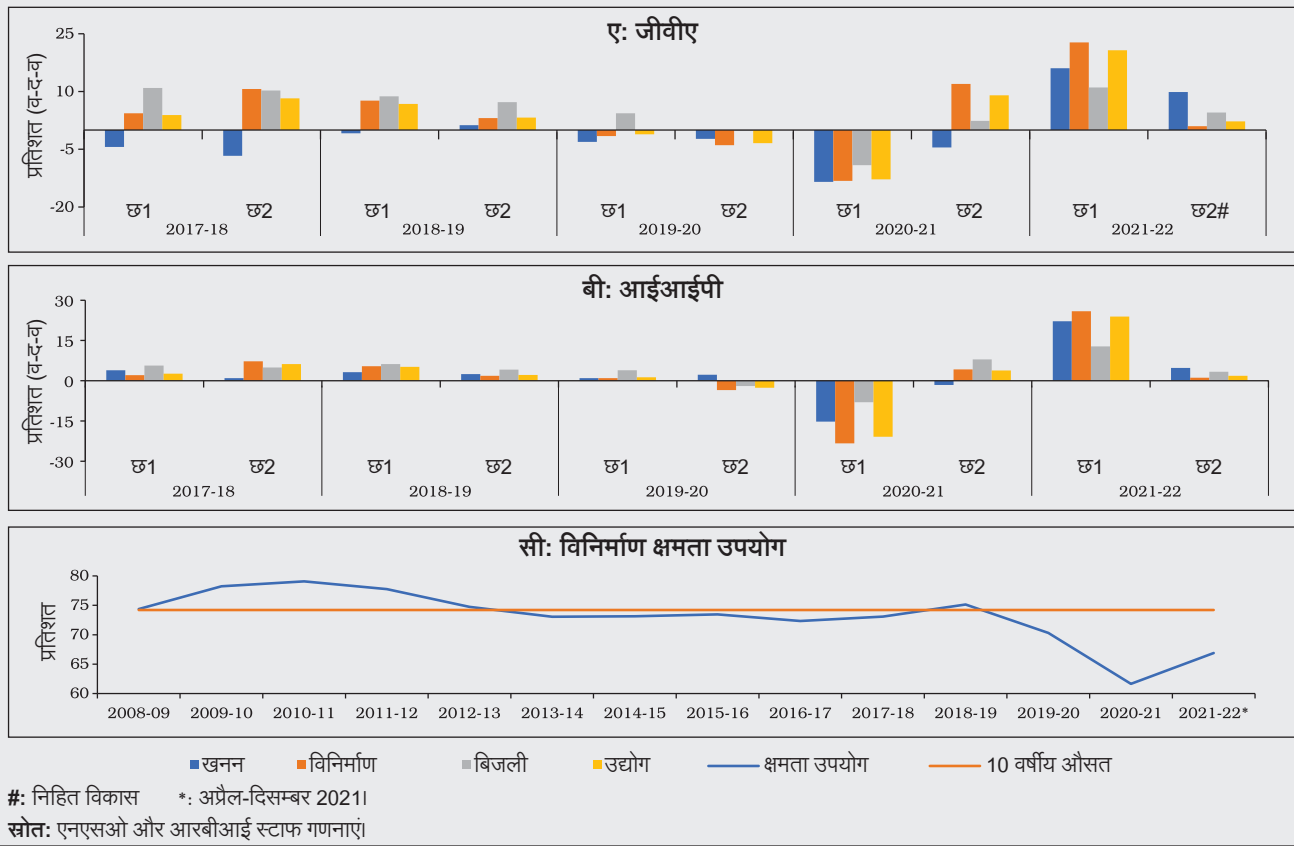
औद्योगिक क्षेत्र

II.1.29 औद्योगिक क्षेत्र, जो महामारी की पहली लहर से बुरी तरह प्रभावित था, वर्ष 2021-22 में गतिशीलता प्रतिबंधों में ढील के साथ ठीक हो गया। महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के परिणामस्वरूप बहाली की गति में कुछ कमी आई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष के 8.4 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.1.12ए और II.1.12 बी)। हालांकि, विनिर्माण क्षमता उपयोग

में गिरावट जारी है (चार्ट II.1.12सी)।

II.1.30 विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव के कम होने के कारण, दूसरी छमाही में रिकवरी में तेजी आई। संचयी रूप से, वर्ष 2021-22 में, 23 उद्योग समूहों में से आठ ने वर्ष 2019-20 के इसी स्तर पर विस्तार दर्ज किया। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, बुनियादी ढांचे की वस्तुओं ने सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की क्योंकि निर्माण क्षेत्र की गतिविधि ने तेज रिकवरी की। अर्धनिर्मित और प्राथमिक वस्तुओं की अन्य श्रेणियों में भी सुधार हुआ, भले ही निवेश परिदृश्य शांत रहा और

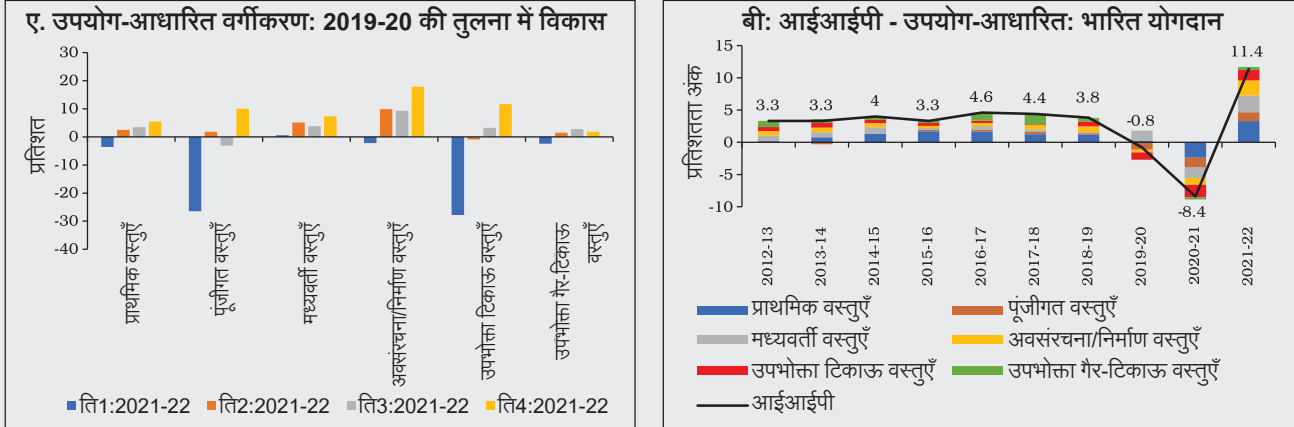
चार्ट II.1.12: औद्योगिक उत्पादन में संवृद्धि



उपभोक्ता मांग अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, जैसा कि महामारी- पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं और

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में संकुचन से झलकता है (चार्ट II.1.13)।

चार्ट II.1.13: औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

II.1.31 भारत में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), जो कुल योजित सकल मूल्य (जीवीए) का लगभग एक तिहाई

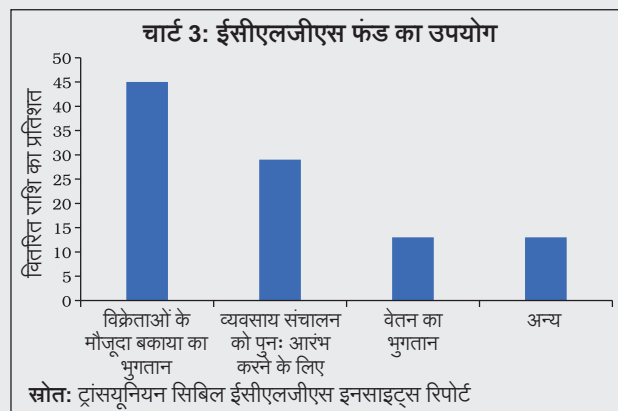
योगदान करता है और लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ (बॉक्स II.1.3)।

बॉक्स II.1.3

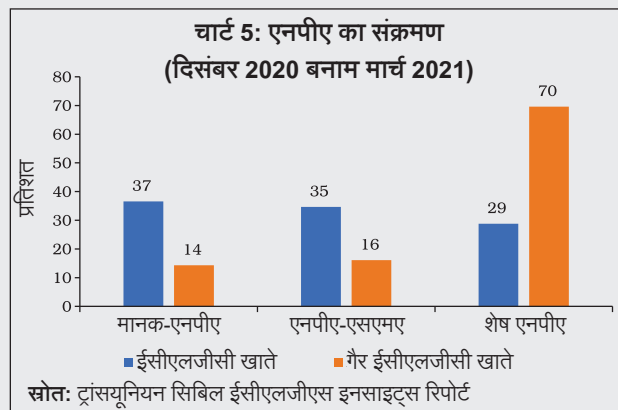
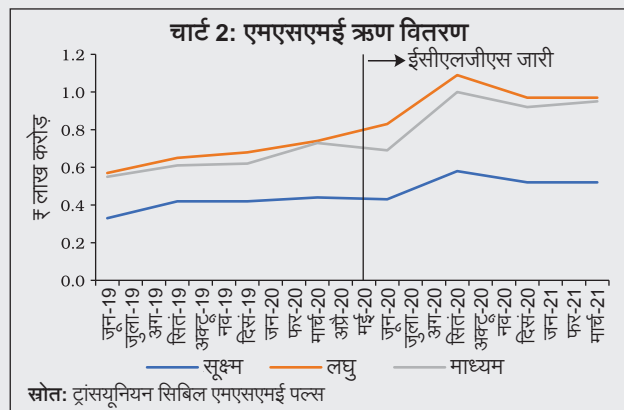
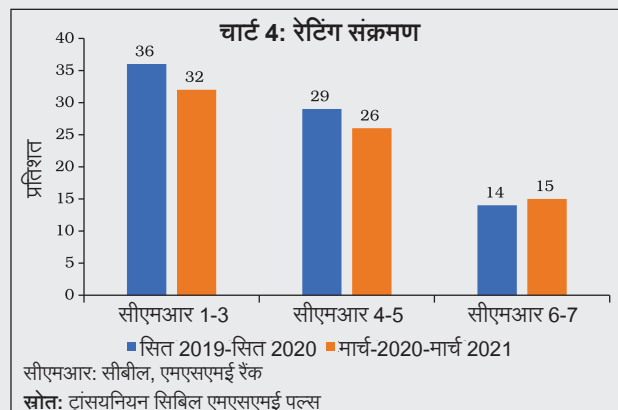
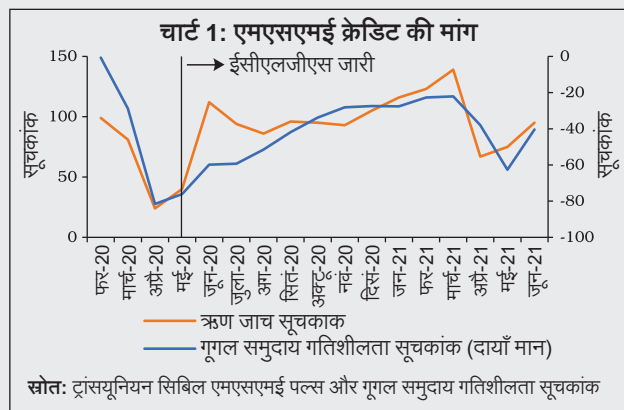
लघु व्यवसाय वित्तपोषण पर कोविड -19 के राहत उपायों का प्रभाव

भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई उपाय किए (आरबीआई, 2021ए, 2021बी)। मई 2020 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना⁹ (ईसीएलजीएस) की घोषणा के बाद, एमएसएमई ऋण, विशेष रूप से छोटे उद्यमों के लिए ऋण संवितरण, जिनका ऋण आकार 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान ₹10 लाख से कम है, की मांग में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट 1 और 2)। इन ऋणों में से लगभग आधे का उपयोग कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले विक्रेताओं की बकाया राशि को चुकाने के लिए किया गया; एक तिहाई का उपयोग व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए किया गया था, और शेष राशि का उपयोग वेतन के भुगतान और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया था (चार्ट 3)।

लगभग 15 लाख ईसीएलजीएस खातों में से 88 प्रतिशत मानक आस्तियां हैं, 10 प्रतिशत विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) हैं, और 2 प्रतिशत अनर्जक आस्तियां (एनपीए) (सीआईबीआईएल, 2021ए) हैं। कुल एनपीए में से, 2021-22 के दौरान समान उधारकर्ताओं के गैर-

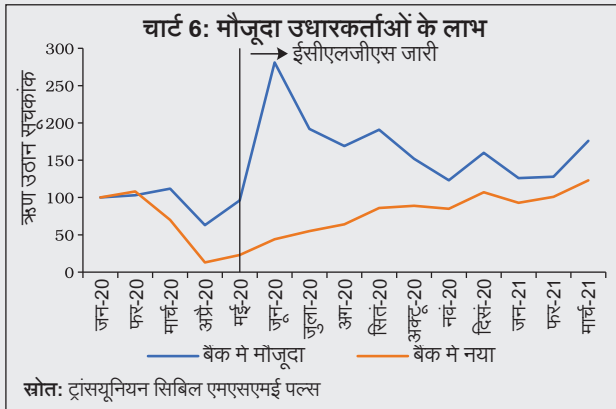


ईसीएलजीएस खातों की तुलना में ईसीएलजीएस खातों में एनपीए से मानक परिसंपत्तियों में संक्रमण काफी अधिक था (चार्ट 4 और 5)।



(जारी)

⁹ भारत सरकार(2020), 'एमजैसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम'. <https://www.ecigs.com/>

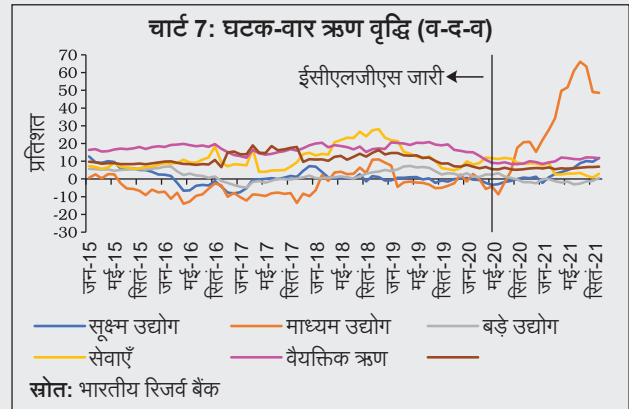


हालांकि, इस योजना से उन फर्मों को लाभ हुआ, जिनका पहले से ही नए उधारकर्ताओं के बजाय बैंक के साथ संबंध था (सीआईबीआईएल, 2021बी)। फरवरी 2021 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) रखरखाव से एमएसएमई क्षेत्र में नए उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण की कटौती की घोषणा की। इस उपाय ने नए एमएसएमई क्षेत्र के उधारकर्ताओं के लिए ऋण योग्य निधियों की उपलब्धता में वृद्धि की, क्योंकि नए उधारकर्ताओं को ऋण लगभग उसी गति से बढ़े जैसे मौजूदा उधारकर्ताओं के लिए (चार्ट 6)। मध्यम आकार के उद्योगों में ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) ईसीएलजीएस योजना की घोषणा के बाद तेज हुई (चार्ट 7)।

मार्च 2016 से अक्तूबर 2021 के मासिक आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट वृद्धि पर ईसीएलजीएस योजना के कारण प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) विश्लेषण से पता चलता है कि कई नीतिगत उपाय मध्यम पैमाने के उद्योग और संयुक्त रूप से सूक्ष्म और मध्यम उद्योग में क्रमशः ईसीएलजीएस ने लगभग 35 प्रतिशत और 23 प्रतिशत ऋण वृद्धि में योगदान दिया (सारणी 1)।

संदर्भ :

1. सीआईबीआईएल, टी. (2021ए), 'ईसीएलजीएस इनसाइट्स रिपोर्ट', ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल, दिसंबर।
2. सीआईबीआईएल, टी. (2021बी), 'एमएसएमई पल्स', ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल, जून।



सारणी 1: एमएसएमई ऋण वृद्धि पर नीतिगत उपायों के प्रभाव का अनुभवजन्य परिणाम

	ऋण वृद्धि की वार्षिक दर (प्रतिशत)		
	सूक्ष्म	मध्यम	सूक्ष्म और मध्यम
ओईसीडी इंडिया कम्पोजिट अग्रणी संकेतक	0.27 *** (0.10)	0.27 *** (0.09)	0.27 *** (0.09)
सेक्टर डमी*ईसीएलजीएस डमी	-4.47 (3.44)	35.29 *** (2.86)	23.12 *** (2.66)
R ²	0.20	0.45	0.36

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। **: 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। *: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

टिप्पणी: 1. विश्लेषण में, ईसीएलजीएस डमी मई 2020 के बाद मान 1 लेता है, और अन्यथा 0। सेक्टर डमी मान 1 लेता है, यदि क्षेत्र सूक्ष्म, मध्यम, सूक्ष्म और मध्यम है, अन्यथा, यह मान 0 लेता है। उपर्युक्त तीन श्रेणियों के लिए तीन क्षेत्रीय डमी हैं। डमी की रिपोर्ट की गई बातचीत की अवधि के साथ, अलग-अलग डमी को स्वतंत्र रूप से माना जाता है और 2015 के दौरान की गई उधार दर और परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा के लिए नियंत्रित किया जाता है, हालांकि, जगह की कमी के कारण परिणाम नहीं दिये गए हैं।

2. कोष्ठक में आंकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

3. आरबीआई (2021ए), 'क्रेडिट टूएमएसएमई ऑटोरप्रेन्योर्स', नोटिफिकेशन, 5 मई।
4. आरबीआई (2021बी), 'स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेग्युलेटरी पॉलिसीज', प्रेस रिलीज, 7 अप्रैल।

II.1.32 खनन क्षेत्र ने वर्ष-दर-वर्ष और महामारी-पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान, दोनों में ही वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष 2021-22 में आघात-सहनीयता दर्ज की। हाइड्रो और परमाणु बिजली उत्पादन में संकुचन होने के बाद भी, तदनु रूप एक साल पहले थर्मल बिजली उत्पादन में दोहरे अंकों के विस्तार के कारण, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में बिजली उत्पादन का भी विस्तार हुआ। नवीकरणीय ऊर्जा, जो कुल उत्पादन का लगभग 11

प्रतिशत है, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में महामारी-पूर्व के स्तर पर दोहरे अंकों का विस्तार दर्ज किया। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में, बेमौसम बारिश और कोयले की कमी के परिणामस्वरूप आपूर्ति में बाधा के कारण तीसरी तिमाही में कम तापीय बिजली उत्पादन के कारण बिजली उत्पादन में कमी आई। वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में नवीकरणीय ऊर्जा ने तीव्र वृद्धि दर्ज की जबकि एक साल पहले की इसी अवधि की

तुलना में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करते हुए परमाणु और जलविद्युत उत्पादन में सुधार हुआ।

II.1.33 संघीय बजट वर्ष 2022-23 ने उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन किया है। पूंजीगत माल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और रत्न व आभूषणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उपायों की भी घोषणा की गई। उत्पादन के लिए अन्य प्रोत्साहनों में एक वर्ष के लिए

रियायती कर व्यवस्था का विस्तार और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की इकाइयों में व्यापार की सुगमता के उपाय शामिल हैं। उद्योग के मोर्चे पर, स्टार्टअप्स के लिए कर प्रोत्साहन एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

II.1.34 कोविड-19 महामारी ने विश्व स्तर पर आपूर्ति शृंखला में व्यवधान उत्पन्न किया। ये व्यवधान कम लागत वाले श्रम, बंद बंदरगाहों, सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी, कंटेनरों और जहाजों, और अन्य पण्यों तक कम पहुंच के रूप में दिखाई दिए (बॉक्स II.1.4)।

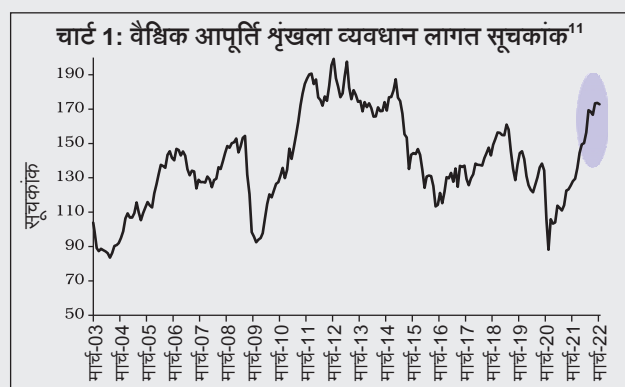
बॉक्स II.1.4

कोविड-19 आघात के बीच जीडीपी वृद्धि और श्रम बाजार पर आपूर्ति शृंखला व्यवधान का प्रभाव

भारत की जीडीपी वृद्धि पर वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, जीएससीडीसीआई (वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान लागत सूचकांक) का अनुमान गतिशील कारक (डीएफ) दृष्टिकोण का उपयोग करके चार चरों¹⁰ में एक अंतर्निहित सामान्य कारक को निकालकर लगाया जाता है (चार्ट 1)। जीएससीडीसीआई में वृद्धि इंगित करती है कि आपूर्ति पक्ष की बाधाएं सरल हैं, और ये संभावित रूप

से समग्र जीडीपी की वृद्धि के लिए एक नकारात्मक जोखिम का कारण बन सकती हैं।

जीडीपी वृद्धि के एआर(1) मॉडल का एक समूह, उच्च आवृत्ति के 9-संकेतक और 15-संकेतकों के गतिशील कारकों द्वारा संवर्धित, जो आर्थिक गतिविधि को ट्रैक करते हैं, जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान के लिए एक आधारभूत अनुमान प्राप्त करने के लिए नियोजित हैं और संक्षेप सारणी



सारणी 1: जीडीपी पर जीएससीडीसीआई के प्रभाव का आकलन

	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित	जीडीपी वर्ष दर वर्ष मौसमी रूप से समायोजित
खुद का अंतराल	0.1 (0.07)	0.14** (0.07)	0.11* (0.07)	0.14** (0.07)
डीएफ9	7.26*** (0.58)	7.81*** (0.56)		
डीएफ15			7.40*** (0.56)	7.57*** (0.56)
जीएससीडीसीआई(-1)		-0.53*** (0.15)		-0.26* (0.15)
लगातार	2.33*** (0.50)	1.83*** (0.49)	1.80*** (0.49)	1.56*** (0.50)
एन	70	70	70	70
एडीजेन ¹²	0.77	0.80	0.79	0.79

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण **: 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण *: 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण

टिप्पणी: 1. 9-संकेतक और 15-संकेतक बेसलाइन ब्रिज समीकरण जीएससीडीसीआई शॉक के साथ संवर्धित हैं।

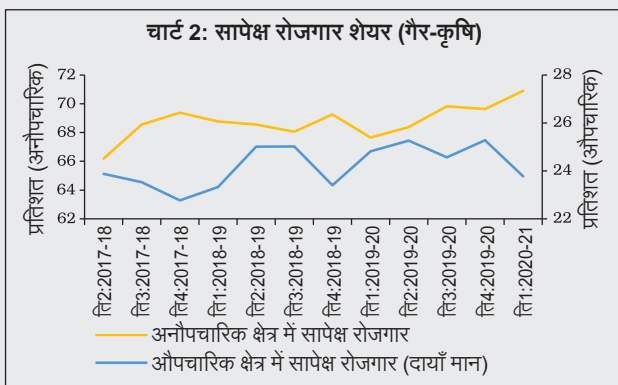
2. कोष्ठक में दिए गए आकड़े मानक त्रुटियों को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ आकलन

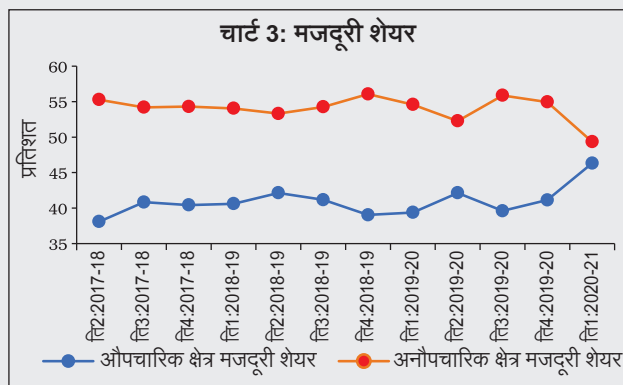
(जारी)

¹⁰ मंथली बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स, आईएमएफ फ्यूल इंडेक्स और सेमी-कंडक्टर इक्विपमेंट बिलिंग।

¹¹ मासिक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बाल्टिक एक्सचेंज (लंदन) द्वारा बनाया गया, एक शिपिंग और व्यापार सूचकांक, सूखे थोक कच्चे माल जैसे कोयला, लोहा, स्टील, आदि के परिवहन की लागत को मापता है। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स भौतिक पण्यों (6 क्षेत्रों को कवर करने वाले 23 पण्यों) की फ्यूचर्स संविदा की कीमतों को ट्रैक करता है। आईएमएफ ईंधन सूचकांक कच्चे तेल (पेट्रोलियम), प्राकृतिक गैस, कोयला और प्रोपेन सहित पण्यों के सबसे बड़े निर्यातक द्वारा निर्धारित की जाने वाला एक बेचमार्क सूचकांक है। अंत में, विश्व सेमी-कंडक्टर उपकरण बिलिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए) से प्राप्त, सेमी-कंडक्टर उपकरणों के 3 महीने के औसत बिक्री मूल्य को कवर करती है जो टिकाऊ वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण इनपुट हैं। 2011-12 = 100 पर आधारित इन सभी सूचकांकों से पता चलता है कि 2021 तक लागत का दबाव बढ़ गया था, जिससे आयात की लागत प्रभावित हुई और इसलिए समग्र जीडीपी प्रभावित हुई।



स्रोत: पीएलएफएस



1 में दिए गए हैं (भादुरी व अन्य, 2021)। जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमानों पर जीएससीडीसीआई के प्रभाव को मापने के लिए, बेसलाइन मॉडल के समान सेट का पुनः अनुमान लगाया जाता है, जो वर्तमान अवधि जीएससीडीसीआई द्वारा संवर्धित है। मॉडल के निष्कर्ष बताते हैं कि जीएससीडीसीआई (या आपूर्ति की कमी) में 1 यूनिट (वर्ष-दर- वर्ष) सख्त होने से 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि 26 आधार अंकों (बीपीएस) कम हो सकती है। यदि वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधान 2021-22 के समान स्तर पर बना रहता है, तो यह आधारभूत विकास अनुमान के लिए संघयी नकारात्मक जोखिम ला सकता है, क्योंकि संघयी प्रभाव दो तिमाहियों में होता है।

एनएसओ द्वारा तिमाही प्रकाशित व्यक्तिगत स्तर पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़े का उपयोग भारत के अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों पर महामारी के आघात के प्रभाव की दिशा और परिमाण का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के उपभोक्ता पिरामिड (सीपी) डेटा का भी उपयोग किया जाता है। पीएलएफएस के आंकड़े बताते हैं कि भारत में, अनौपचारिक क्षेत्र 65 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, और अनौपचारिक क्षेत्र की सापेक्ष रोजगार हिस्सेदारी हमेशा औपचारिक क्षेत्र से अधिक रहती है (चार्ट 2)।¹² आम राय के विपरीत, रोजगार के मामले में अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान महामारी की पहली लहर के दौरान औपचारिक क्षेत्र से बड़ा था। हालांकि, कुल वेतन बिल में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान नाटकीय रूप से गिर गई।

कोविड-19 की पहली लहर के दौरान, अर्थव्यवस्था का कुल योजित सकल मूल्य (जीवीए) कम हो गया। मजदूरी के हिस्से पर विषम प्रभाव के साथ कुल वेतन बिल भी कम हुए। पीएलएफएस के आंकड़ों से पता चलता है कि मजदूरी में अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्र के शेयर आमतौर पर एक ऐसी घटना को बदल देते हैं जो महामारी की पहली लहर से उलट गई थी (चार्ट 3)। इस प्रकार, कुल रोजगार में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि के बावजूद पहली लहर के दौरान जीवीए में औपचारिक क्षेत्र का अपने वेतन हिस्से के मामले में अधिक योगदान था। जो उद्योग अनौपचारिक क्षेत्र की मजदूरी हिस्सेदारी में गिरावट का शिकार पहले हुए, वे हैं- थोक, और खुदरा व्यापार एवं विनिर्माण।¹³

कोविड-19 की पहली लहर के बाद के पीएलएफएस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, सीएमआईई उपभोक्ता पिरामिड (सीपी) आंकड़ों को पीएलएफएस के साथ उचित रूप से मैप करने के बाद, औपचारिक क्षेत्र के वेतन हिस्से की शृंखला को बहिर्वेशित किया जाता है। यह हाइब्रिड-डेटा शृंखला इंगित करती है कि पहली लहर के दौरान कुल मजदूरी में औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि दूसरी लहर के किसी भी दृश्य प्रभाव के बिना क्षणिक प्रतीत होती है।

संदर्भ :

1. भादुरी , एस., एस. घोष , और पी कुमार (2021), ' कन्स्ट्रक्टिंग ए कोइन्सिडेंट इकॉनॉमिक इंडिकेटर फॉर इंडिया: हाउ वेल डज इट ट्रैक ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट?' आशियन डेवेलपमेंट रिव्यू, 38 (02), पी. 237-277
2. रे, डी. और एस. सुब्रमण्यम (2020), 'इंडियाज लॉकडाउन: एन इंटरिम रिपोर्ट', इंडियन इकॉनॉमिक रिव्यू, 55(1), पी.31-79।

¹² पीएलएफएस रिपोर्ट में एनएसओ द्वारा दी गई अनौपचारिक क्षेत्र की परिभाषा का पालन किया गया है। अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार के सबसे बड़े हिस्से वाले उद्योगों में थोक और खुदरा व्यापार, आवास और खाद्य सेवाएं, अचल संपत्ति और निर्माण शामिल हैं।

¹³ थोक और खुदरा व्यापार में अनौपचारिक क्षेत्र की मजदूरी हिस्सेदारी में गिरावट सबसे बड़ी, 8 प्रतिशत अंक थी, जबकि विनिर्माण के मामले में, यह पीएलएफएस के 2019-20 दौर के आंकड़ों के अनुसार 5.7 प्रतिशत अंक थी।

सेवा क्षेत्र

II.1.35 सेवा क्षेत्र, जिसे वर्ष 2020-21 में एक अभूतपूर्व संकुचन का सामना करना पड़ा था, उसने वर्ष 2021-22 में नुकसान की कुछ भरपाई की। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान संक्रामक दूसरी लहर के बावजूद, सेवा क्षेत्र की सुधार व्यापक आधार वाला था क्योंकि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी उप-खंडों ने अपने महामारी-पूर्व के स्तर (वर्ष 2019-20) को पार कर लिया था।

II.1.36 रिहायशी आवासीय क्षेत्र ने वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सुधार दर्ज किया, बिक्री और लॉन्च में क्रमिक रूप से सुधार हुआ, और फंसी हुई इन्वेंट्री गिरकर आठ तिमाहियों के सबसे निचले स्तर पर आ गई। इस क्षेत्र में आशावाद लॉन्च की गई इकाइयों की संख्या में दिखाई दिया, जो 15 तिमाहियों में सबसे अधिक है। आवास क्षेत्र में गतिविधि के साथ-साथ बुनियादी ढांचे पर सरकार द्वारा जोर देने से निर्माण क्षेत्र को लाभ हुआ। 48,000 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ प्रधान मंत्री आवास योजना द्वारा, अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ-साथ निर्माण क्षेत्र में विकास के समर्थन करने की उम्मीद है। वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने अपने महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर लिया। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का प्रदर्शन आतिथ्य और विमानन क्षेत्रों में उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर रहा है। वित्तीय क्षेत्र में, यद्यपि वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक ऋण में सुधार हुआ, कुल जमाराशियों में एहतियाती बचत में कमी आई। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं (पीएडीओ) ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खर्च में मजबूत वृद्धि के कारण 12.5 प्रतिशत की दो अंकों की वृद्धि दर्ज करने के लिए एक

प्रभावशाली बदलाव देखा। रेल और माल ढुलाई में भी तेजी से बहाली हुई।

II.1.37 सेमी-कंडक्टर चिप्स में वैश्विक आपूर्ति पक्ष के व्यवधान ऑटोमोबाइल क्षेत्र में फैल गया, जहां उत्पादन में गिरावट और डिलीवरी के समय में वृद्धि ने पंजीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला (सारणी II.1.5)। यात्री कारों की बिक्री में संकुचन दर्ज किया गया। दूसरी छमाही में दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी गिरावट आई और मांग में गिरावट के कारण ट्रैक्टर की बिक्री प्रभावित हुई। निम्न आधार ने टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और हवाई यात्री यातायात के संकेतकों में वृद्धि को आगे बढ़ाया, भले ही वे महामारी-पूर्व की तुलना में शांत रहे। पोर्ट कार्गो खंड, जिसने महामारी के दौरान आघात-सहनियता प्रदर्शित किया, तीसरी तिमाही में वैश्विक कंटेनर की कमी से प्रभावित हुआ। उच्च आधार के बावजूद मजबूत बने रहने वाले संकेतकों में रेलवे भाड़ा, जीएसटी ई-वे बिल और जीएसटी राजस्व शामिल हैं।

II.1.38 रिज़र्व बैंक का सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक (एसएससीआई)¹⁴, जो निर्माण, व्यापार, परिवहन और वित्त में गतिविधि को ट्रैक करता है और पीएडीओ को छोड़कर सेवाओं में जीवीए वृद्धि का एक सहवर्तिता संकेतक है, पिछली दो लगातार तिमाहियों में गिरावट के बाद, वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में तीसरी तिमाही के लगभग समान स्तर पर रहा (चार्ट II.1.14)।

4. रोज़गार

II.1.39 वार्षिक पीएलएफ़एस डेटा वर्ष 2019-20 तक उपलब्ध है और शहरी क्षेत्रों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी तिमाही पीएलएफ़एस डेटा दिसंबर 2021 तक उपलब्ध है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में अपेक्षाकृत कम था। (चार्ट II.1.15)। पहली लहर (अप्रैल-जून 2020) के दौरान,

¹⁴ एसएससीआई का आकलन उच्च आवृत्ति संकेतकों, जैसे इस्पात उपभोग, सीमेंट उत्पादन, प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई, वाणिज्यिक वाहनों का बिक्री/उत्पादन, रेलवे माल यातायात, हवाई यात्री/माल ढुलाई, पर्यटक आगमन, गैर-तेल आयात, बैंक क्रेडिट और जमा से एकत्र जानकारी को उपयुक्त रूप से निकालने और संयोजन करके किया जाता है।

सारणी II.1.5: उच्च आवृत्ति संकेतक: विकास दर

(प्रतिशत, वर्ष-दर-वर्ष)

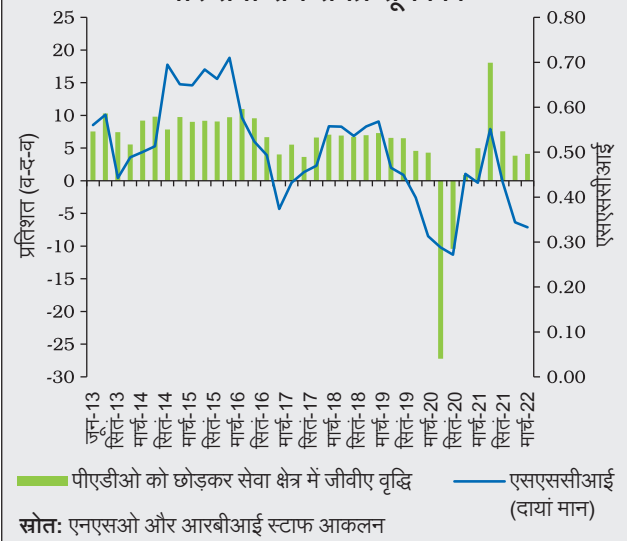
संकेतक	अप्रै-21	मई-21	जून-21	जुला-21	अग-21	सितं-21	अक्टू-21	नव-21	दिसं-21	जन-22	फर-22	मार्च-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
शहरी मांग												
ऑटोमोबाइल बिक्री	-	40.0	14.7	4.0	-11.4	-19.7	-24.7	-31.8	-10.7	-18.8	-23.5	-17.8
यात्री वाहन	-	162.5	119.3	44.7	7.6	-41.2	-27.1	-18.6	-13.3	-8.1	-6.5	-3.9
कृषि / ग्रामीण मांग												
ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री	436.2	-8.0	18.9	3.3	-17.0	-14.8	0.4	-22.5	-27.5	-32.6	-31.3	-14.3
दुपहिया वाहनों की बिक्री	-	26.1	4.0	-2.1	-14.6	-17.4	-24.9	-34.4	-10.8	-21.1	-27.3	-20.9
तिपहिया वाहनों की बिक्री	59,587.0	-48.7	-8.8	40.5	59.7	53.8	19.1	-6.6	27.0	-8.5	-1.1	0.5
यातायात												
कुल वाहन पंजीकरण	215.5	158.6	22.5	34.0	14.6	-5.3	-5.3	-2.7	-16.0	-10.7	-9.0	-2.9
घरेलू हवाई यात्री यातायात	1,05,896.5	608.7	53.8	136.4	132.6	76.5	68.7	65.5	53.3	-16.2	-1.0	37.7
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	2,575.0	343.3	31.2	45.9	119.2	155.9	162.9	140.2	121.7	67.5	66.6	105.7
घरेलू एयर कार्गो	1,117.7	285.7	43.0	41.3	35.7	10.1	6.7	-1.7	2.0	-6.1	-6.3	-1.0
इंटरनेशनल एयर कार्गो	312.5	116.8	46.9	31.7	25.8	18.1	23.8	11.7	10.5	5.2	-0.4	1.1
माल यातायात शुद्ध टन किलो मी	86.9	55.7	27.1	21.4	20.0	9.0	20.6	14.3	8.4	11.5	11.0	11.2
फ्रेट ट्रैफिक फ्रेट उत्पात्ति	70.7	39.1	20.5	18.4	16.9	3.6	8.4	6.1	7.2	7.7	6.6	6.7
पोर्ट कार्गो	29.5	31.5	19.5	6.7	11.4	0.1	6.5	-0.2	-0.4	-2.9	0.0	0.7
घरेलू व्यापार												
जीएसटी ई-वे बिल	582.5	56.8	25.9	32.7	33.3	18.3	14.5	5.9	11.6	9.5	8.3	9.7
जीएसटी ई-वे बिल इंटर-स्टेट	480.3	47.1	24.3	31.6	30.8	15.6	14.1	7.3	13.4	11.4	10.3	11.8
जीएसटी ई-वे बिल अंतरराज्यीय	840.6	76.5	28.8	34.4	37.2	22.3	15.1	3.9	8.9	6.6	5.3	6.6
जीएसटी राजस्व	339.5	65.3	2.1	33.1	29.6	22.5	23.7	25.3	12.7	15.5	17.6	14.7
निर्माण												
स्टील की खपत	721.5	64.3	28.3	4.2	-2.2	-3.2	-3.8	-7.1	-8.3	0.5	-5.3	-0.5
सीमेंट उत्पादन	582.7	8.3	7.5	21.7	36.3	11.3	14.5	-3.6	14.2	14.3	5.0	8.8

■ फैलाव

■ संकुचन

-: उपलब्ध नहीं
स्रोत: सीईआईसी.

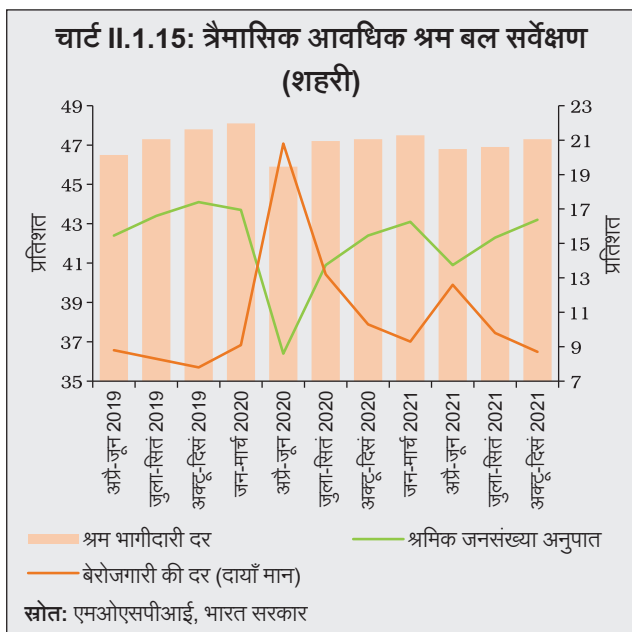
चार्ट II.1.14: सेवा क्षेत्र में वृद्धि (पीएडीओ को छोड़कर) और सेवा क्षेत्र समग्र सूचकांक



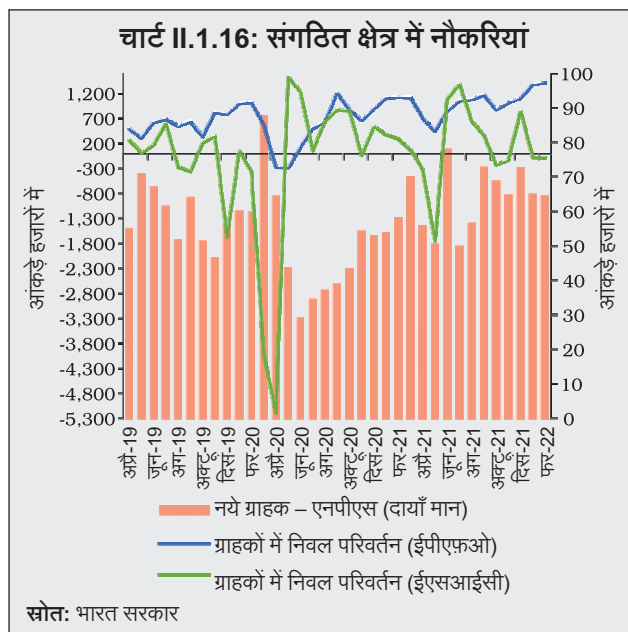
श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) गिरकर 45.9 प्रतिशत हो गई, लेकिन दूसरी लहर (अप्रैल-जून 2021) के दौरान, एलएफपीआर गिरकर 46.8 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, दूसरी लहर के दौरान पहली की तुलना में कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में कम संकुचन हुआ। जहां पहली लहर के दौरान बेरोजगारी दर बढ़कर 20.8 प्रतिशत हो गई, वहीं दूसरी लहर के दौरान वे अपेक्षाकृत कम बढ़कर 9.8 प्रतिशत हो गईं। लेकिन श्रम बाजार में रिकवरी दिसंबर 2021 तक पूरी नहीं हुई थी, एलएफपीआर और डब्ल्यूपीआर, दोनों महामारी-पूर्व तिमाही (जनवरी-मार्च 2020) की तुलना में कम हैं।

II.1.40 वेतन पंजी आंकड़ों द्वारा मापा गया संगठित क्षेत्र का रोजगार, वर्ष 2021-22 में अब तक रोजगार सृजन में मजबूत

चार्ट II.1.15: त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (शहरी)



चार्ट II.1.16: संगठित क्षेत्र में नौकरियां



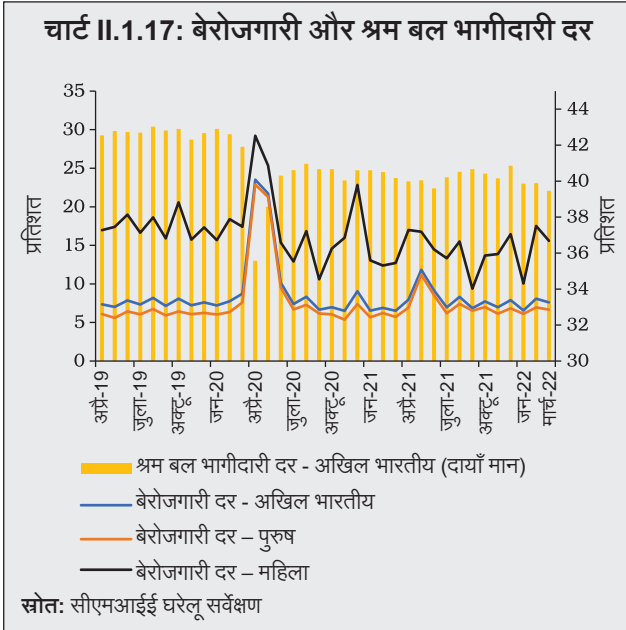
सुधार की तस्वीर प्रस्तुत करता है। संचयी आधार पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रति माह जोड़े गए निवल अभिदाता अप्रैल-फरवरी 2021-22 में पिछले वर्ष की समान अवधि के 6.0 लाख से बढ़कर 10.1 लाख हो गए। दूसरी ओर, कर्मचारियों के राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में अपने योगदान का भुगतान करने वाले सदस्यों की औसत संख्या अप्रैल-फरवरी 2020-21 के दौरान प्रति माह 1.0 लाख से बढ़कर अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान 1.6 लाख प्रति माह हो गई। इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के नए अभिदाताओं में भी वृद्धि हुई (चार्ट II.1.16)।

II.1.41 सीएमआईई घरेलू सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग करते हुए रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का आकलन दूसरी लहर के दौरान अपेक्षाकृत आघात-सह श्रम बाजार की स्थिति को इंगित करता है। प्रतिबंधों की स्थानीय प्रकृति और गतिशीलता के लिए रुक-रुक कर दी जाने वाली छूट ने सुनिश्चित किया कि रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। वर्ष 2021-22 के दौरान, औसत मासिक श्रम शक्ति भागीदारी दर वर्ष 2020-21 में 39.9 प्रतिशत की तुलना में 40 प्रतिशत से

ऊपर रही। इसके अलावा, दो लहरों के बीच चरम बेरोजगारी दर अप्रैल 2020 में 23.5 प्रतिशत से घटकर मई 2021 में 11.8 प्रतिशत लगभग आधी हो गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, बेरोजगारी दर ने समान पैटर्न का पालन किया। श्रम बाजार में लिंग अंतराल के संदर्भ में, महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर में सुस्त सुधार दर्ज किया गया। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर मई 2021 में दूसरी लहर के चरम पर 11.2 प्रतिशत से, मार्च 2022 में 6.7 प्रतिशत तक कम हो गई, लेकिन मई 2021 में महिलाओं के लिए यह 16.8 प्रतिशत से कम होकर मार्च में 15.6 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.1.17)।

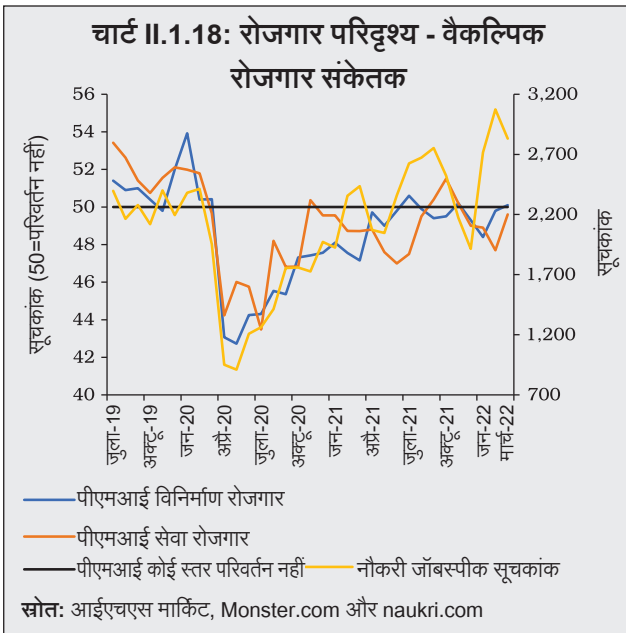
II.1.42 समग्र क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के रोजगार उप-सूचकांक जैसे रोजगार पर जानकारी को कवर करने वाले अन्य सर्वेक्षणों ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद विनिर्माण और सेवाओं में भर्ती में मामूली संकुचन दर्ज किया। पहली लहर की तुलना में, दूसरी लहर के दौरान सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र के मुकाबले अपेक्षाकृत गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। हालांकि, वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान सेवा क्षेत्र के रोजगार में तेज गति से विस्तार हुआ। इसी तरह,

चार्ट II.1.17: बेरोजगारी और श्रम बल भागीदारी दर



नौकरी जॉब्सपीक इंडेक्स से पता चलता है कि वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में निजी क्षेत्र की भर्ती में तेजी आई (चार्ट II.1.18)।

चार्ट II.1.18: रोजगार परिदृश्य - वैकल्पिक रोजगार संकेतक



5. निष्कर्ष

II.1.43 महामारी की गंभीरता से उबरते हुए भारत का आर्थिक सुधार वर्ष 2021-22 में जारी रहा है और इस गति के वर्ष 2022-23 में भू-राजनीतिक झटके और इसके स्पिलओवर से अधोगामी जोखिम के साथ भी व्यापक रूप से जारी रहने की उम्मीद है। इन जोखिमों के बावजूद, रिकवरी गहरी और व्यापक हो रही है। संघीय बजट वर्ष 2022-23 ने मांग पक्ष उपायों पर ध्यान देने के साथ '100 पर भारत' के रोडमैप की कल्पना की। सरकारी पूंजीगत कैपेक्स परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि निजी निवेश में बढ़ोत्तरी कर सकती है और एक सुचक्र को आगे बढ़ा सकती है, जिससे कुल मांग में सुधार होगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसंरचना योजना (एनआईपी) की राशि ₹100 लाख करोड़ और राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी) जिसमें ₹6 लाख करोड़ शामिल हैं - दोनों को वर्ष 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य है, से भी बुनियादी ढांचे के खर्च पर एक बड़े जोर देने की उम्मीद है। 'प्रक्रिया सुधारों' के माध्यम से आपूर्ति पक्ष प्रबंधन¹⁵ पर, कुछ क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को सुगम और सरल बनाने पर जहां एक सुविधाकर्ता या नियामक के रूप में सरकार की उपस्थिति आवश्यक है, पर केंद्रित ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था की आघात-सहनशीलता में सुधार करने में मदद करेगा। सार्वजनिक खरीद और दूरसंचार जैसे प्रक्रिया सुधारों से कई क्षेत्रों को लाभ हुआ है। स्थायी कृषि विकास और कृषि आय में वृद्धि के लिए एक मार्ग निर्धारित करते हुए, संघीय बजट वर्ष 2022-23 में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, तिलहन और बाजरा के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एग्री-टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने वाली कई पहलों की घोषणा की गई है। प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के सात इंजनों द्वारा संचालित रोडमैप तैयार किया। एमएसएमई क्षेत्र के लिए, ईसीएलजीएस

¹⁵ इसमें क्षेत्रों का अविनियमन, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निजीकरण, आस्ति मुद्राकरण और उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22) शामिल हैं।

को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें गारंटी कवर को ₹50,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 लाख करोड़ करके कुल कवर का विस्तार किया गया है, अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित की गई है।

II.1.44 टीकाकरण की त्वरित गति और आर्थिक गतिविधियों की बेहतर संभावनाओं के कारण तीसरी लहर के बावजूद कुल मिलाकर उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास आघात-सह बना हुआ है। हालांकि, कुल मांग में पूर्ण सुधार निजी निवेश में बदलाव पर निर्भर है। आपूर्ति पक्ष पर, खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में पुनरुत्थान हो रहा है। सेवा क्षेत्र, जिसने महामारी के दुष्परिणाम झेले, वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के बाद से व्यापक रूप से सुधार करता दिखाई रहा है।

II.1.45 विकास के लिए आगे का रास्ता, आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करके तथा मौद्रिक और राजकोषीय नीति समर्थन को समग्र मांग और संरचनात्मक सुधारों के साथ कैलिब्रेट करके निर्धारित किया जाएगा। श्रम बाजार में इस तरह के सुधारों की भी आवश्यकता है ताकि कामगारों को फिर से तैयार करके महामारी के अनुकूल बनाया जा सके। महामारी, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और उत्पादकता वृद्धि को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है।

II.2 कीमतों की स्थिति

II.2.1 वर्ष 2021 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी, जो महामारी से संबंधित आपूर्ति और रसद व्यवधानों, वैश्विक पण्य कीमतों में फिर से उछाल और रुकी हुई मांग को दर्शाती है। मूल्य दबावों की तीव्रता विभिन्न देशों में भिन्न थी, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने उदीयमान बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मुद्रास्फीति में तेज

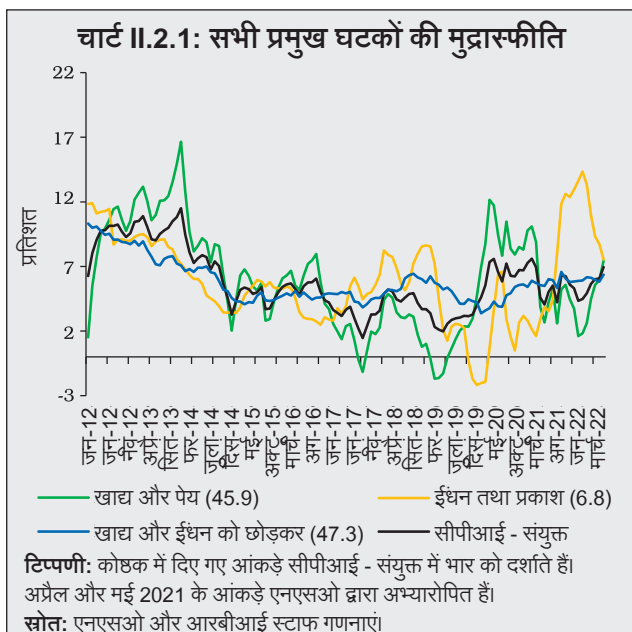
वृद्धि दर्ज की, जबकि उदीयमान बाजारों को घरेलू मुद्रास्फीति में विनिमय दर को मूल्यहास के पारित होने का भी सामना करना पड़ा।

II.2.2 वर्ष 2021 के दौरान, विश्व बैंक ऊर्जा मूल्य सूचकांक, वर्ष 2020 की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक था, जबकि 'धातु और खनिज' तथा कृषि वस्तु मूल्य सूचकांक क्रमशः 47.1 प्रतिशत और 24.2 प्रतिशत ऊपर थे। ऊर्जा कीमतें, जो नवंबर-दिसंबर 2021 के दौरान आपूर्ति की स्थिति में सुधार के रूप में गिर गई थीं, वर्ष 2022 की पहली तिमाही में भू-राजनीतिक संघर्ष और उसके बाद आर्थिक प्रतिबंधों के कारण तेजी से बढ़ीं। मार्च 2022 में ब्रेंट क्रूड की कीमतें दिसंबर 2021 के स्तर की तुलना में 55.6 प्रतिशत बढ़ीं। अन्य प्रमुख प्राथमिक वस्तुओं ने भी महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि दर्ज की है- दिसंबर 2021 की तुलना में मार्च 2022 में धातुओं और खनिजों में 21 प्रतिशत और खाद्य में 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पण्य कीमतों में इस व्यापक-आधारित वृद्धि ने अत्यधिक मुद्रास्फीति जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के शीघ्र सामान्यीकरण की संभावना को जोखिम में डाल दिया है और मुद्रास्फीति की उम्मीदों के अस्थिर होने का खतरा सामने ला दिया है।

II.2.3 भारत में, हेडलाइन मुद्रास्फीति¹⁶, मई-जून 2021 के दौरान मुद्रास्फीति लक्ष्य के ऊपरी सहन स्तर को पार कर गई, जो सभी तीन प्रमुख समूहों - खाद्य, ईंधन और खाद्य व ईंधन को छोड़कर (कोर), में स्थानीय लॉकडाउन से आपूर्ति बाधित होने के कारण मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि से प्रेरित थी (चार्ट II.2.1)। इसके बाद, जब बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, तो मुख्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रही, जो इनपुट लागत दबावों के पास-श्रू को दर्शाती है। इसके विपरीत, खरीफ फसल की बुवाई में प्रगति के साथ खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई, जब तक कि अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान अधिक / बेमौसम बारिश ने खड़ी फसलों (विशेष रूप से सब्जियों) को

¹⁶ हेडलाइन मुद्रास्फीति को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आधार वर्ष: 2012=100 के साथ अखिल भारतीय सीपीआई-संयुक्त (ग्रामीण + शहरी) में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापा जाता है।

चार्ट II.2.1: सभी प्रमुख घटकों की मुद्रास्फीति



नुकसान नहीं पहुंचाया और जिसके कारण कीमतों के दबाव में वृद्धि हुई जिसे आंशिक रूप से अनुकूल आधारभूत प्रभावों से सहायता प्राप्त हुई। परिणामस्वरूप, हेडलाइन मुद्रास्फीति, जो सितंबर 2021 तक मुद्रास्फीति कम होकर लक्ष्य के करीब आ गई थी, अक्टूबर 2021 से फिर से बढ़ी और जनवरी-मार्च 2022 के दौरान 6 प्रतिशत के ऊपरी सहन स्तर को पार कर गई। वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यह वृद्धि रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण घरेलू खाद्य कीमतों में थोड़ी कमी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति बाधाओं के कारण हुई थी।

II.2.4 औसत मुद्रास्फीति और साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के मानक विचलन द्वारा मापी गई अस्थिरता एक साल पहले की तुलना में वर्ष 2021-22 में कम थी (सारणी II.2.1)। मुद्रास्फीति का अंतर-वर्ष वितरण भी अधिक संतुलित था, जैसा कि एक छोटे नकारात्मक तिरछा में परिलक्षित होता है।

II.2.5 इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, उप-खंड 2 वैश्विक पण्य कीमतों में विकास का आकलन करता है। उप-खंड 3 भारत में प्रमुख पड़ावों के साथ-साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति की गतिविधियों पर चर्चा करता है, इसके बाद उप-खंड 4 में इसके प्राथमिक घटकों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कीमतों और लागतों के अन्य संकेतकों का विश्लेषण उप-खंड 5 में किया गया है, जिसके बाद समापन टिप्पणियों का जिक्र हुआ है।

2. वैश्विक मुद्रास्फीति गतिविधियां

II.2.6 वैश्विक पण्य कीमतों में वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा कीमतों के कारण हुई (चार्ट II.2.2)। आपूर्ति की कमी और बिजली की मांग में वृद्धि के बीच प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं क्योंकि वैश्विक आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हुई। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें वर्ष के दौरान अस्थिर रहीं और वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यूक्रेन में संघर्ष के कारण तेजी से बढ़ीं। जुलाई 2021 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) और उनके सहयोगियों (ओपेक +) के संगठन

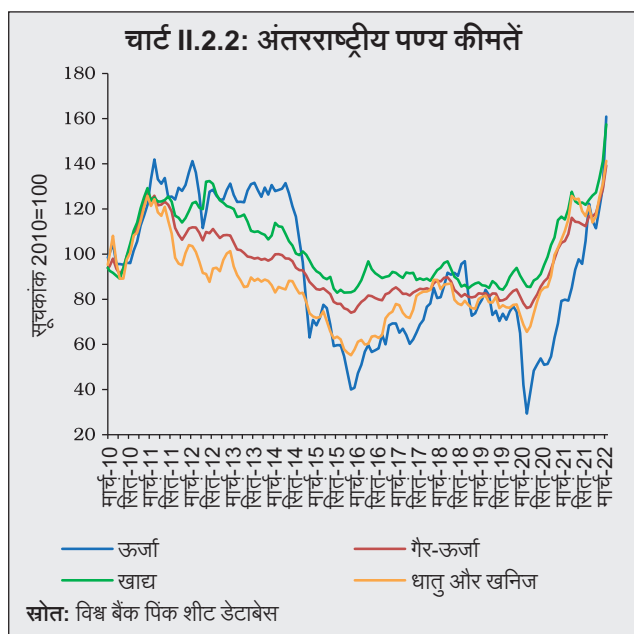
सारणी II.2.1: हेडलाइन मुद्रास्फीति - प्रमुख सांख्यिकी सारांश

(प्रतिशत)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
माध्य	10.0	9.4	5.8	4.9	4.5	3.6	3.4	4.8	6.2	5.5
मानक विचलन	0.5	1.3	1.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.8	1.1	0.9
स्क्युनेस	0.2	-0.2	-0.1	-0.9	0.2	-0.2	0.1	0.5	-0.7	-0.1
कर्टोसिस	-0.2	-0.5	-1.0	-0.1	-1.6	-1.0	-1.5	-1.4	-0.7	-1.0
माध्यिका	10.1	9.5	5.5	5.0	4.3	3.4	3.5	4.3	6.5	5.6
अधिकतम	10.9	11.5	7.9	5.7	6.1	5.2	4.9	7.6	7.6	7.0
न्यूनतम	9.3	7.3	3.3	3.7	3.2	1.5	2.0	3.0	4.1	4.2

टिप्पणी: स्क्युनेस एण्ड कर्टोसिस की कोई इकाई नहीं होती। वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष के दौरान मासिक मुद्रास्फीति दर का औसत है और इसलिए यह वर्ष के लिए औसत सूचकांक से गणना किए गए वार्षिक मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील है।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।



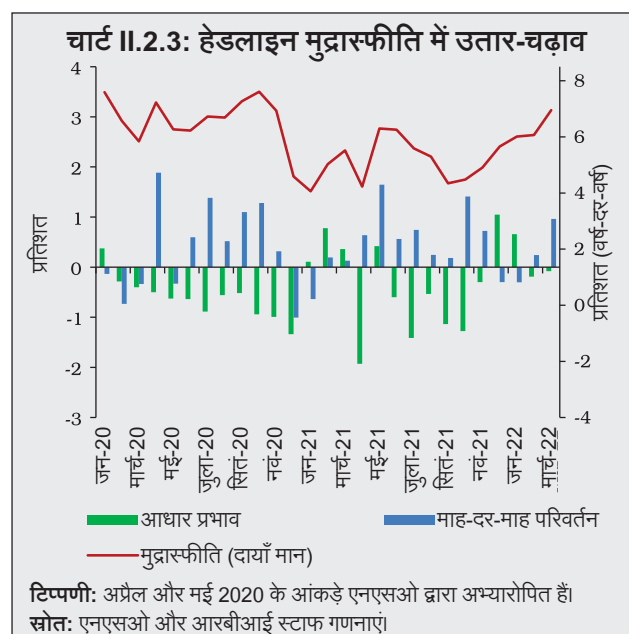
द्वारा अप्रैल 2020 में घोषित बड़े उत्पादन कटौती की भरपाई करने के लिए, अगस्त 2021 से मासिक आधार पर केवल धीरे-धीरे 0.4 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय के लिए बनाया गया था और इसमें यूएस शेल सहित नए तेल उत्पादन में निवेश में सुस्त गति के साथ कीमतों का समर्थन किया। परिणामस्वरूप, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें मार्च 2022 में बढ़कर 112 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जो दिसंबर 2020 में 49 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थीं। ऊर्जा की कमी और लॉकडाउन के कारण उत्पादन बाधित होने के बावजूद धातुओं की मांग में वृद्धि जारी रही। वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतें भी ऊंची बनी रहीं और खाद्य सूचकांक (विश्व बैंक पिक शीट) मार्च 2022 में एक सर्वकालिक उच्च (जनवरी 1960 के बाद से) पर पहुंच गया जो कि मुख्य रूप से खाद्य तेलों (ताड़ का तेल; सूरजमुखी तेल; रेपसीड तेल और सोयाबीन तेल) और अनाज की कीमतों, कई उत्पादक देशों (दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया) में प्रतिकूल मौसम से तंग आपूर्ति की स्थितियों, रूस-यूक्रेन संघर्ष और पशु चारा (मक्का और सोयाबीन) की उच्च मांग द्वारा चालित था। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस और कोयले की उच्च कीमतों ने उर्वरक उत्पादन को प्रभावित किया और उनकी कीमतों को बढ़ा दिया और इस तरह खाद्य फसलों

के लिए इनपुट लागत बढ़ गई। इन वैश्विक पण्य मूल्य विकासों को दर्शाते हुए, आई और ईएमडीई दोनों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ी।

3. भारत में मुद्रास्फीति

II.2.7 कोविड-19 की दूसरी लहर द्वारा आपूर्ति में व्यवधान और स्थानीय लॉकडाउन तथा वैश्विक पण्य कीमतों (कच्चे तेल और धातु) में वृद्धि के पास-थ्रू के कारण मई-जून 2021 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में तेज और व्यापक-आधारित वृद्धि होने से पहले, भारत में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति पर वापस आते हुए, अप्रैल 2021 में यह 4.2 प्रतिशत तक कम हो गया था (चार्ट II.2.3)। इसके बाद खाद्य कीमतों में गिरावट और प्रतिबंधों में ढील के कारण अनुकूल आधार प्रभावों के साथ मुद्रास्फीति में कमी आई। जैसा कि पहले बताया गया है, वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में ऊपरी सहन स्तर को पार करते हुए मुद्रास्फीति फिर से बढ़ने लगी।

II.2.8 खाद्य और पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति का प्राथमिक विक्रेय बनी रही, हालांकि वर्ष 2021-22 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान घटकर 35.9 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 54.8 प्रतिशत था। केंद्र



सरकार ने खाद्य तेलों और दालों में कीमतों के दबाव को दूर करने के लिए कई आपूर्ति पक्ष के कदम उठाए जिससे खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिली।

11.2.9 दूसरी ओर, ईंधन की कीमतों ने नई ऊंचाइयों को छुआ और अक्टूबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और मिट्टी के तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण मौजूदा मुद्रास्फीति शृंखला में 14.3 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।। इसके बाद, मुख्य रूप से कुछ राज्यों द्वारा घोषित बिजली की कीमतों में कमी और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण नवंबर 2021 - मार्च 2022 के दौरान ईंधन की कीमतों में कमी आई।

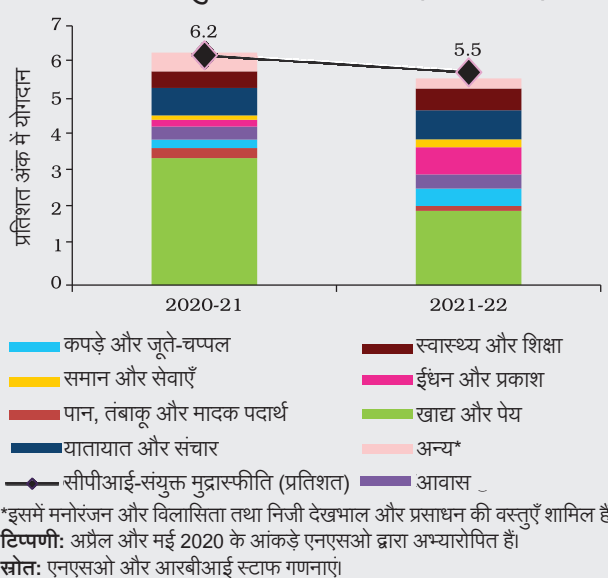
11.2.10 वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों और घरेलू मांग में कुछ सुधार के बीच इनपुट लागत दबावों को दर्शाते हुए खाद्य और ईंधन या कोर मुद्रास्फीति को छोड़कर मुद्रास्फीति पूरे वर्ष बनी रही। मुख्य योगदानकर्ता में परिवहन और संचार; स्वास्थ्य; घरेलू सामान और सेवाएं; खेलकूद और मनोरंजन; तथा कपड़े और जूते की कीमतें शामिल हैं।

11.2.11 वर्ष के लिए, वर्ष 2021-22 में मुद्रास्फीति औसतन 5.5 प्रतिशत तक कम हो गई, जो एक साल पहले की तुलना में 66 आधार अंक (बीपीएस) कम है (परिशिष्ट सारणी 4)। हेडलाइन मुद्रास्फीति में ढील के बावजूद, परिवारों की औसत मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं वर्ष 2021-22 के दौरान तीन महीने आगे 59 आधार अंक और एक वर्ष आगे 62 आधार अंक तक मजबूत हो गई, जो महामारी और छिटपुट आपूर्ति झटकों के रास्ते की अनिश्चितता को दर्शाती हैं।

4. सीपीआई मुद्रास्फीति के घटक

11.2.12 वर्ष 2021-22 के दौरान, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के चालकों ने खाद्य और पेय पदार्थों में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाए; ईंधन और प्रकाश; परिवहन और संचार; स्वास्थ्य; तथा कपड़े और जूते प्रमुख चालक बने रहे (चार्ट 11.2.4)।

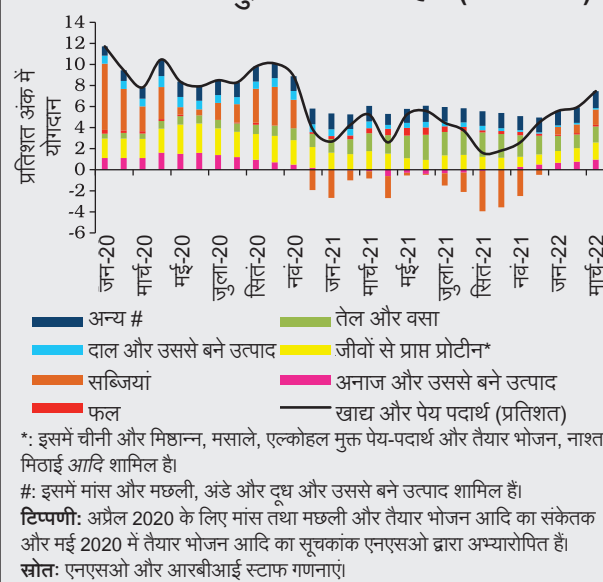
चार्ट 11.2.4: मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)

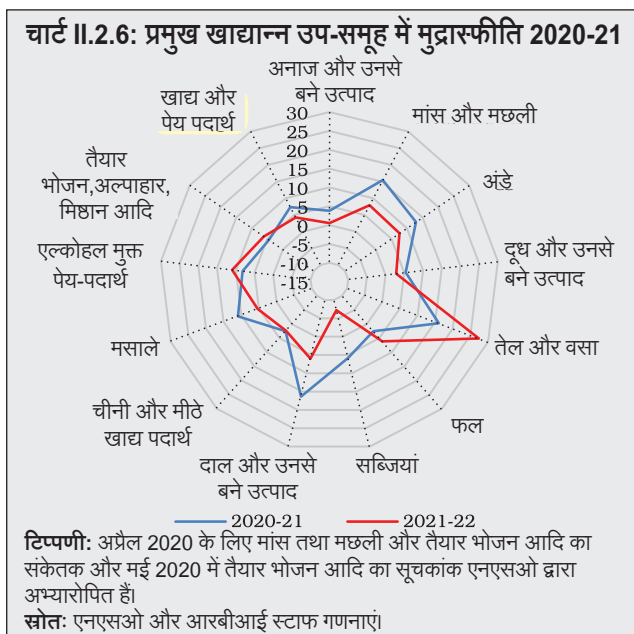


खाद्यान्न

11.2.13 वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में मुद्रास्फीति (भारांक: सीपीआई में 45.9 प्रतिशत) 1.6 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की एक विस्तृत शृंखला के भीतर बढ़ी, जो मुख्य रूप से सब्जियों एवं तेलों और वसा मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है (चार्ट 11.2.5)।

चार्ट 11.2.5: खाद्य मुद्रास्फीति के वाहक (वर्ष-दर-वर्ष)



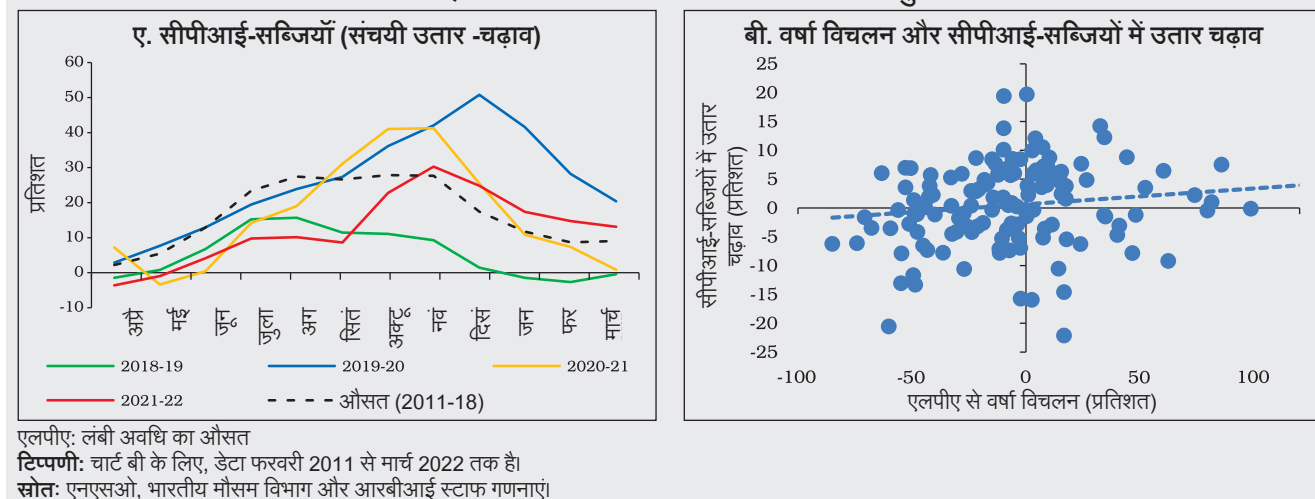


II.2.14 वर्ष 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 4.2 प्रतिशत रही, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 7.3 प्रतिशत थी। 12 उप-समूहों में से आठ में मुद्रास्फीति में कमी देखी गई (चार्ट II.2.6)। सब्जियों की कीमतें (भारांक: सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 13.2 प्रतिशत) वर्ष के एक बड़े हिस्से के दौरान अपस्फीति में रहीं, अनुकूल आधार प्रभावों पर (-) 7.2 प्रतिशत की औसत अपस्फीति दर्ज की गई और इसने वर्ष के दौरान समग्र खाद्य मुद्रास्फीति पर अधोगामी दबाव डाला।

II.2.15 सब्जियों को छोड़कर, खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 204 आधार अंक अधिक गई (चार्ट II.2.7ए)। जबकि अधिक उत्पादन के कारण आम तौर पर कीमतों में कमी होती है, अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान अतिरिक्त / बेमौसम बारिश ने सब्जियों की कीमतों को बढ़ा दिया (चार्ट II.2.7बी)।

II.2.16 जून-जुलाई 2021 के महीनों के दौरान प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई, जो ग्रीष्मकालीन मूल्य उछाल तथा महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवात ताउते के कारण संग्रहीत रबी प्याज को पहुंचे नुकसान को और फिर अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान भारी बारिश के कारण प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीफ फसलों को पहुंचे नुकसान को दर्शाती है। नीतिगत हस्तक्षेपों के रूप में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत 2 लाख मीट्रिक टन (एमटी) के कुल बफर स्टॉक से संग्रहीत प्याज को निर्मोचित किया गया। ताजे आमद से समर्थन मिला, जिसने फरवरी 2022 में अस्थायी वृद्धि को छोड़कर दिसंबर 2021-मार्च 2022 के दौरान कीमतों के दबाव को कम किया। टमाटर के मामले में, अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान कीमतों में वृद्धि देखी गई, जो सितंबर 2021 में उत्तर भारत के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में अनियमित बारिश को दर्शाती है, इसके बाद अक्तूबर 2021 में दक्षिण भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों में भारी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में व्यवधान और फसल

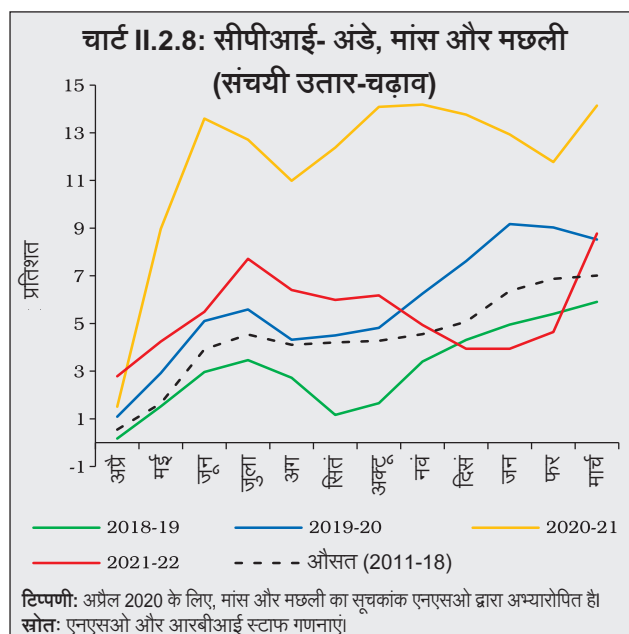
चार्ट II.2.7: सीपीआई- सब्जियों: कीमतों में मौसमी प्रभाव और मुद्रास्फीति के वाहक



को नुकसान हुआ। पिछले साल की आकर्षक कीमतों तथा प्रमुख उत्पादक राज्यों में उच्च भंडारण स्टॉक की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप आलू की कीमतें वर्ष 2021-22 के दौरान (फरवरी-मार्च 2022 को छोड़कर) उच्च उत्पादन [2019-20 के अंतिम अनुमानों (एफई) की तुलना में वर्ष 2020-21 की एफई में 15.7 प्रतिशत] पर होते हुए अवस्फीति पर थीं। हालांकि, अक्तूबर-नवंबर 2021 के दौरान बेमौसम बारिश और ताजा फसलों की आमद में देरी के कारण कीमतों में वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 में कम उत्पादन [वर्ष 2021-22 में (-) 4.6 प्रतिशत होने का अनुमान वर्ष 2020-21 एफई पर पहला उन्नत अनुमान (एई)] मार्च 2022 में मूल्य दबावों के फिर से उभरने का कारण बना।

11.2.17 अनाज और उत्पादों की कीमतों (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 21 प्रतिशत का भार) ने अक्तूबर 2021-मार्च 2022 के दौरान कुछ कीमतों में दबाव दर्ज करने से पहले, वर्ष की पहली छमाही के दौरान अपस्फीति दर्ज की। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत उच्च खरीद-उठाव, चावल के रिकॉर्ड उत्पादन (वर्ष 2020-21 एफई की तुलना में वर्ष 2021-22 की तीसरी एई के अनुसार 4.3 प्रतिशत) ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान कीमतों को कम रखा। हालांकि, उच्च निर्यात (वर्ष 2021-22 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 236 प्रतिशत) के कारण दूसरी छमाही के दौरान गेहूं की कीमत में दबाव दिखाई दिया।

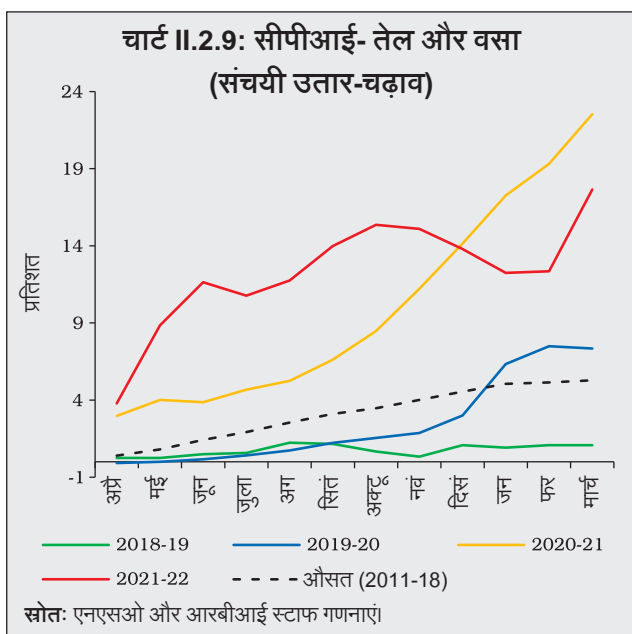
11.2.18 अप्रैल-जुलाई 2021 के दौरान, प्रोटीन युक्त वस्तुओं जैसे अंडे, मांस और मछली (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 8.8 प्रतिशत के भार) के मामले में, कीमत में दबाव देखा गया, जो आपूर्ति में व्यवधान और फीड और परिवहन लागत में वृद्धि से इनपुट कीमत के दबाव को दर्शाता है (चार्ट 11.2.8)। आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्रमिक सामान्यीकरण और आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया मील के 12 लाख टन के आयात के अनुरूप अगस्त 2021-जनवरी 2022 के दौरान कीमतों में कमी आई। हालांकि, फरवरी-मार्च 2022 के दौरान कीमतों का दबाव फिर से उभर आया, जो फीड लागत में और बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। दूध और उत्पादों के मामले में, जुलाई 2021 और मार्च 2022



में अमूल और मदर डेयरी जैसी प्रमुख दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा खुदरा कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कारण हुई वृद्धि तथा कुछ राज्य दूध सहकारी समितियों द्वारा इसी प्रकार के अनुसरण को छोड़कर, कीमतों में कमी बनी रही।

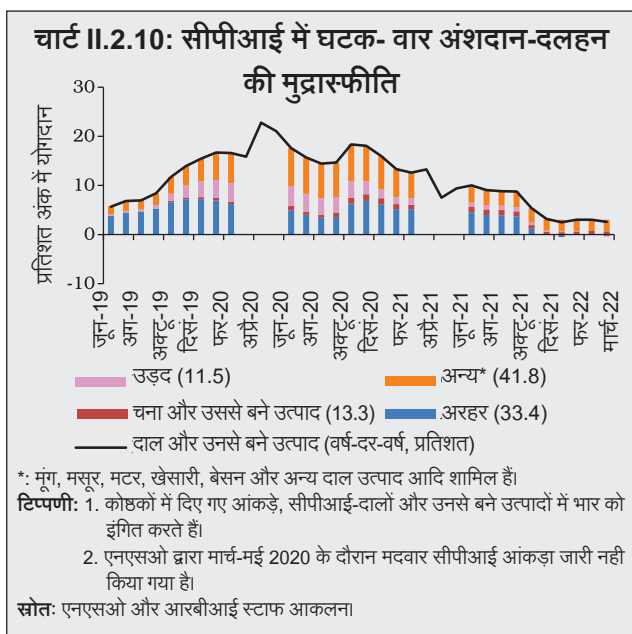
11.2.19 तेल और वसा (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 7.8 प्रतिशत का भार) ने जून 2021 में ऐतिहासिक रूप से 34.8 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति दर्ज की, जो बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों, विशेष रूप से पॉम तेल की बढ़ती आयात कीमतों के कारण हुई (चार्ट 11.2.9)। कीमतों के दबाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा कई उपाय किए गए - 31 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लागू करना; और पॉम के तेल (रिफाइंड और कच्चे पॉम तेल पर शुल्क को जून 2021 में 37.5 प्रतिशत और 32.5 प्रतिशत से कम कर फरवरी 2022 में क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत करना) सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क की कई बार कटौती करना। नवंबर 2021-जनवरी 2022 के दौरान इन उपायों के जवाब में और रबी तिलहन की बुवाई में तेज वृद्धि के बाद, खाद्य तेल की कीमतों में कमी दर्ज की गई। हालांकि, यूक्रेन (जो सूरजमुखी तेल का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है) में संघर्ष से फरवरी-मार्च 2022 के दौरान कीमतों के दबाव की वापसी हुई।

चार्ट II.2.9: सीपीआई- तेल और वसा (संचयी उतार-चढ़ाव)



II.2.20 2. सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष से संबंधित किए गए कई उपायों के कारण दालों की कीमतों में महंगाई (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 5.2 प्रतिशत का भार) में मई-जून 2021 में हुई वृद्धि के बाद से इसमें गिरावट होती रही (चार्ट II.2.10)। आपूर्ति उपायों में 15 मई, 2021 से अरहर, उड़द और मूंग के आयात को

चार्ट II.2.10: सीपीआई में घटक- वार अंशदान-दलहन की मुद्रास्फीति



प्रतिबंधित से 'मुक्त श्रेणी' में ले जाना; मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर 2021 तक स्टॉक सीमा लागू करना; 27 जुलाई, 2021 से मसूर पर आयात शुल्क को पूरी तरह समाप्त करना और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को घटाकर 10 प्रतिशत करना; बफर स्टॉक से मसूर को रियायती कीमतों पर जारी करना और उड़द और तूर की मुफ्त आयात नीति को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाना शामिल है। इन उपायों से मार्च 2022 तक मुद्रास्फीति कम होकर 2.6 प्रतिशत हो गई, जो जून 2021 में 10 प्रतिशत के अंतर-वर्ष का उच्चतम स्तर था।

II.2.21 फलों में मुद्रास्फीति (सीपीआई-खाद्य और पेय पदार्थों में 6.3 प्रतिशत का भार) मई/जून 2021 में 3 साल के उच्च स्तर 11.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसके बाद, हालांकि, सेब और अंगूर के उच्च उत्पादन के कारण कीमतों में कमी आई।

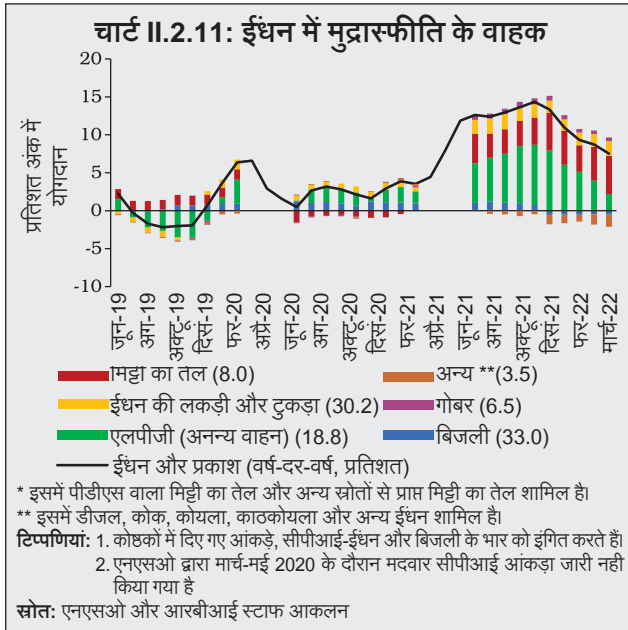
ईंधन

II.2.22 हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन समूह (सीपीआई में 6.8 प्रतिशत का भार) का योगदान पिछले वर्ष के 2.9 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2021-22 में बढ़कर 13.1 प्रतिशत हो गया। ईंधन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2021 में तेजी से 14.3 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिसका मुख्य कारण घरेलू एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतों का बढ़ना था, जिसने अंतरराष्ट्रीय कीमतों की गतिविधियों को ट्रैक किया (चार्ट II.2.11 और चार्ट II.2.12)। इसके बाद, मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखी गई और मार्च 2022 में मुख्य रूप से बिजली की कीमतों में कमी और अनुकूल आधार प्रभावों के कारण 7.5 प्रतिशत तक पहुंच गई।

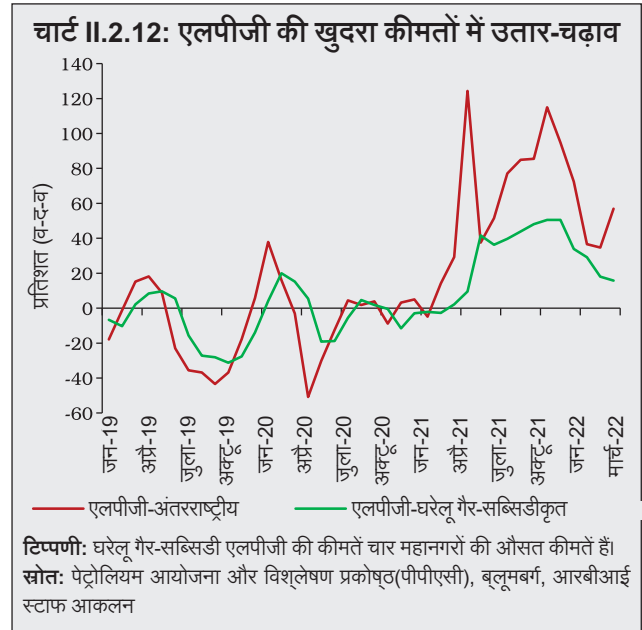
खाद्य तथा ईंधन को छोड़कर मुद्रास्फीति

II.2.23 खाद्य और ईंधन की अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति, अर्थात् कोर मुद्रास्फीति, वर्ष 2021-22 में औसतन 6.0 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो मई 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के शिखर पर होने पर 6.6 प्रतिशत के अंतर-वर्ष के सर्वोच्चतम स्तर पर थी (चार्ट II.2.13) [परिशिष्ट सारणी 4]। इसके बाद, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती (क्रमशः ₹5 प्रति लीटर और ₹10 प्रति लीटर) और इसके बाद

चार्ट II.2.11: ईंधन में मुद्रास्फीति के वाहक



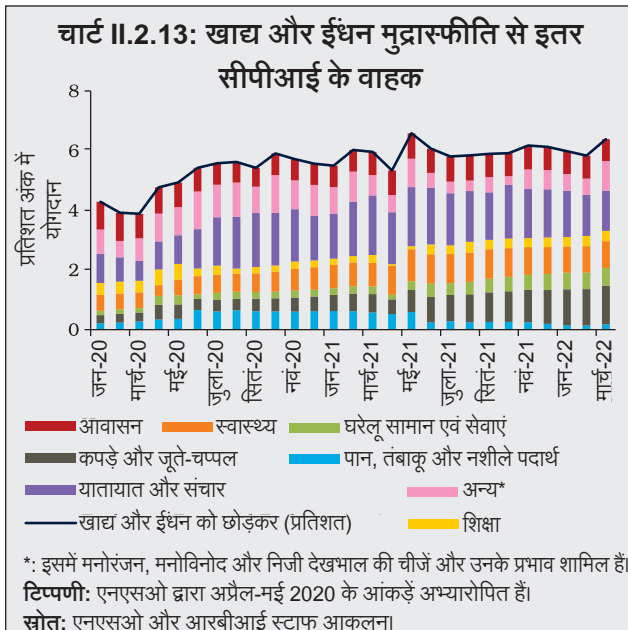
चार्ट II.2.12: एलपीजी की खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव



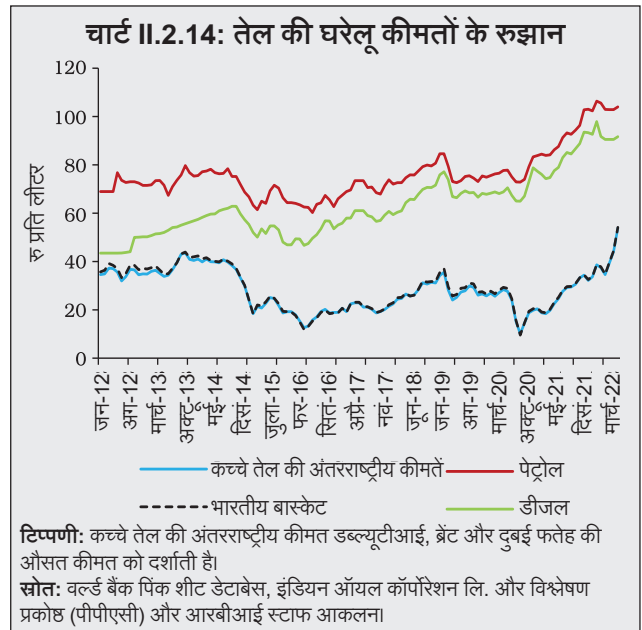
नवंबर 2021 की शुरुआत में अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा मूल्य वर्धित कर (वैट) में कमी के बावजूद नवंबर 2021-मार्च 2022 (फरवरी 2022 को छोड़कर) के दौरान फिर से 6 प्रतिशत को पार करने से पहले लॉकडाउन प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने के साथ मुद्रास्फीति कुछ हद तक कम हो गई।

II.2.24 प्रमुख घटकों में, परिवहन और संचार में दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में वृद्धि को दर्शाया (चार्ट II.2.14)। कच्चे माल की उच्च लागत, आपूर्ति बाधाओं और महामारी में मांग के कारण दवा की कीमतों तथा अस्पताल और नर्सिंग शुल्क में वृद्धि के कारण स्वास्थ्य उप-समूह में मुद्रास्फीति बढ़ी।

चार्ट II.2.13: खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति से इतर सीपीआई के वाहक



चार्ट II.2.14: तेल की घरेलू कीमतों के रुझान



परिवहन और संचार के भीतर, निजी परिवहन वाहनों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है जो प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा उच्च इनपुट लागत (विशेष रूप से धातु और माइक्रोचिप्स) के क्रमिक पास-थ्रू को दर्शाती है। निजी दूर संचार ऑपरेटरों ने जुलाई 2021 (आधार वर्गों के लिए लगभग 40 प्रतिशत) और नवंबर 2021 (20-25 प्रतिशत) में विभिन्न योजनाओं के लिए मोबाइल टैरिफ प्रभार में वृद्धि की। वर्ष 2021-22 के दौरान खुदरा कीमतों के लिए इनपुट लागत के पास-थ्रू के परिणामस्वरूप, मुख्य वस्तुओं के भीतर बड़ी संख्या में वस्तुओं ने मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई (चार्ट II.2.15)।

II.2.25 आवास मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 में 3.7 प्रतिशत (वर्ष 2020-21 में 3.3 प्रतिशत) पर मध्यम रही, जो कोविड-19 की कई लहरों के बीच हाइब्रिड कार्य संस्कृति के कारण किराये की मांग में कमी को दर्शाती है। वर्ष 2021-22 में आवास, खाद्य और ईंधन को छोड़कर, की निवल मुद्रास्फीति औसतन 6.6 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 6.2 प्रतिशत थी।

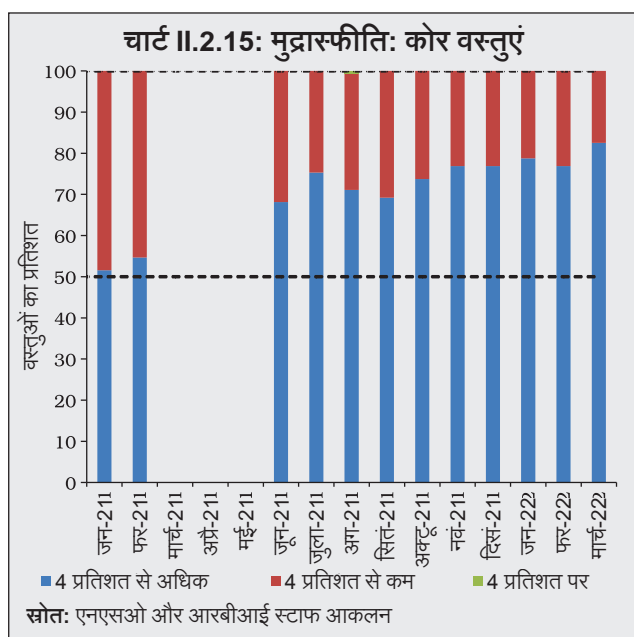
II.2.26 कपड़ों और जूतों की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई और वर्ष 2021-22 में 7.2 प्रतिशत के औसत से एक प्रमुख दबाव बिंदु बना रहा। यह अप्रैल 2021 में 3.5 प्रतिशत से

लगातार बढ़कर मार्च 2022 में 9.4 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से कम वैश्विक उत्पादन और स्वस्थ वैश्विक मांग के कारण कपास की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों (कॉटन ए इंडेक्स द्वारा मापा गया) से उत्पन्न इनपुट लागत दबाव को दर्शाती है।

5. मुद्रास्फीति के अन्य संकेतक

II.2.27 एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, बड़े पैमाने पर खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 के दौरान थोड़ा बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई, हालांकि जनवरी में 5.8 प्रतिशत तक पहुंचने से पहले सितंबर 2021 में यह 4.4 प्रतिशत तक कम थी। दूसरी ओर, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई (सीपीआई-आरएल) पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2021-22 में क्रमशः 4.0 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में अनुकूल आधार प्रभावों और मंद खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 5.5 प्रतिशत थी। हालांकि दोनों ने मार्च 2022 में 6 प्रतिशत के स्तर को पार कर लिया।

II.2.28 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 में 1.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 13.0 प्रतिशत हो गई, जो नवंबर 2021 में 14.9 प्रतिशत के अंतरा-वर्ष के शिखर पर थी (वर्तमान श्रृंखला के सर्वोच्चतम स्तर पर)। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2021 से बढ़ी और वर्ष के दौरान दोहरे अंकों में रही, जो सभी प्रमुख समूहों में कीमतों में तेज वृद्धि को दर्शाती है। प्राथमिक वस्तुओं के भीतर, गैर-खाद्य वस्तुओं (21.2 प्रतिशत), खनिज (19.4 प्रतिशत) और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (56.5 प्रतिशत) में मुद्रास्फीति दो अंकों में बनी रही, जो बढ़ती घरेलू मांग के बीच उच्च अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों को दर्शाती है। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति भी औसतन 32.8 प्रतिशत तक उछल गई, जो मुख्य रूप से खनिज तेलों की कीमतों में तेज वृद्धि से प्रेरित थी। मई 2021 से, इनपुट लागत में व्यापक आधार पर वृद्धि के साथ, विनिर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति भी दोहरे अंकों में पहुंच गई (बॉक्स II.2.1)। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में तेज



बॉक्स II.2.1

इनपुट लागत दबावों के प्रति भारत में मुद्रास्फीति की संवेदनशीलता

भारत में इनपुट लागत दबावों के लिए मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया को समझने के लिए दो दृष्टिकोणों का पालन किया जाता है: (i) वैश्विक कमोडिटी कीमतों का सीधे सीपीआई को पास-थ्रू, और (ii) परोक्ष रूप से डब्ल्यूपीआई के माध्यम से। वर्ष 1992 से 2021 की अवधि के लिए मासिक डेटा एक बहुपद वितरित अंतराल (पीडीएल) मॉडल (बैटन और थॉर्नटन, 1983) [समीकरण¹⁷ (1) और (2)] का उपयोग करते हुए एक साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) ढांचे में कार्यरत हैं:

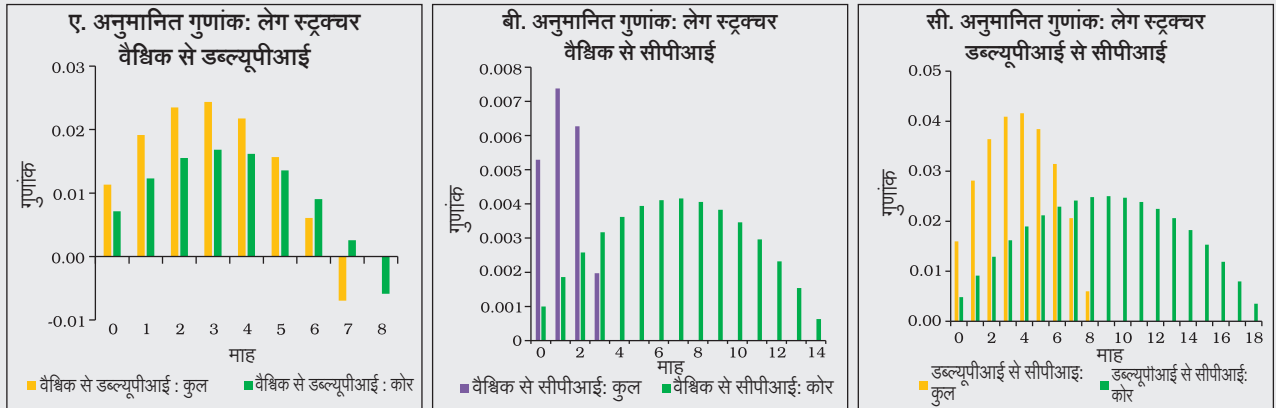
$$\begin{aligned} \text{dlog(Domestic Price Index)}_{t,i} = & c_1 + \sum_{i=1}^P \beta_i \text{dlog(Domestic Price Index)}_{t,i} \\ & + \sum_{i=0}^R \alpha_i \text{dlog(IMF Price)}_{t,i} + \sum_{i=0}^R \gamma_i \text{dlog(Ex Rate)}_{t,i} \\ & + \theta_1 \text{IIPGapDom}_{t,i} + \delta_1 \text{IIPGapOECD}_{t,k} \\ & + \phi_1 \text{Abs Rain Dev}_{t,i} + \varepsilon_t \quad \dots(1) \\ \text{dlog(CPI)}_{t,i} = & c_2 + \sum_{i=1}^S \phi_i \text{dlog(CPI)}_{t,i} + \sum_{i=0}^T \psi_i \text{dlog(WPI)}_{t,i} \\ & + \sum_{i=0}^R \gamma_i \text{dlog(Ex Rate)}_{t,i} + \eta_1 \text{IIPGapDom}_{t,v} \\ & + \lambda_1 \text{IIPGapOECD}_{t,w} + \omega_1 \text{Abs Rain Dev}_{t,x} + \upsilon_t \quad \dots(2) \end{aligned}$$

परिणाम बताते हैं कि वैश्विक पण्य कीमतों का सीपीआई को पास-थ्रू डब्ल्यूपीआई के मुकाबले कम है, गैर-खाद्य ईंधन (या कोर) के मामले में लंबे समय तक संचरण अंतराल के साथ। मूल मुद्रास्फीति (चार्ट 1) के मामले में भी प्रभाव लगातार बना हुआ है। वैश्विक पण्य समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) की कीमतों में एक प्रतिशत परिवर्तन से सीपीआई समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) मुद्रास्फीति में 0.02(0.04) प्रतिशत परिवर्तन होता है, और समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 0.11(0.09) प्रतिशत परिवर्तन होता है।

दूसरी ओर, थोक मूल्य सूचकांक समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) में एक प्रतिशत के परिवर्तन से समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) सीपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 0.26(0.33) प्रतिशत का परिवर्तन होता है। अप्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष अनुमानों की पुष्टि करते हैं, अर्थात्, वैश्विक पण्यों समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) की कीमतों में एक प्रतिशत की वृद्धि से समग्र (खाद्येत्तर और ईंधन से इतर) सीपीआई मुद्रास्फीति में लगभग 0.03 प्रतिशत परिवर्तन होता है।

संक्षेप में, वैश्विक पण्य कीमतों के सख्त होने से डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में सीपीआई मुद्रास्फीति पर अपेक्षाकृत मध्यम प्रभाव पड़ता है, लेकिन सीपीआई कोर पर प्रभाव अधिक स्थायी है।

चार्ट 1: अनुमानित परिणाम



टिप्पणी: गुणांक पास-थ्रू अनुमान हैं।

स्रोत: एनएसओ, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय भारत सरकार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

संदर्भ:

बैटन, डलास एस., और डेनियल एल. थॉर्नटन (1983), 'पॉलिनोमियल डिस्ट्रिब्यूटेड लैग्स एंड द एस्टीमेशन ऑफ द सेंट लुइस इक्वेशन' फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस, वॉल. 65(अप्रैल), पृष्ठ 13-25।

17 जहां घरेलू मूल्य सूचकांक सीपीआई और समग्र डब्ल्यूपीआई/खाद्येत्तर और ईंधन से इतर जैसा भी मामला हो, को संदर्भित करता है; आईएमएफ मूल्य समग्र/खाद्येत्तर और ईंधन से इतर प्राथमिक वस्तु मूल्य सूचकांक को संदर्भित करता है; एक्स रेट यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर को संदर्भित करता है; आईआईपी गैप डोम/आईआईपी गैप ओईसीडी आईआईपी गैप हैं जिनका उपयोग क्रमशः घरेलू और वैश्विक मांग की प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है, एक्स रेन देव, वास्तविक वर्षा के दीर्घावधि औसत से पूर्ण विचलन को संदर्भित करता है, ε और υ संबद्ध त्रुटि दर्शाते हैं और t समय को दर्शाता है। सभी डेटा श्रृंखलाओं को उनके प्राकृतिक लॉग फॉर्म में परिवर्तित कर दिया गया है और अनुमान से पूर्व फिर डी-सीज़नलाइज़ किया गया है।

बढ़ोत्तरी और सीपीआई मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी को दर्शाते हुए, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अपस्फीतिकारक मुद्रास्फीति भी दूसरे अग्रिम अनुमान वर्ष 2021-22 के अनुसार, वर्ष 2020-21 में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 9.6 प्रतिशत हो गई।

11.2.29 खरीफ और रबी की फसलों के लिए वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में कम वृद्धि हुई। एमएसपी की सीमा विभिन्न फसलों में बढ़ जाती है जैसे- मूंग और मक्का के मामले में 1.1 प्रतिशत से लेकर रेपसीड/सरसों के लिए 8.6 प्रतिशत तथा चावल और गेहूं के एमएसपी में क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

11.2.30 मई 2021-फरवरी 2022 के दौरान कृषि और गैर-कृषि मजदूरों की मजदूरी वृद्धि वर्ष के दौरान मंद रही, जो कम ग्रामीण मुद्रास्फीति के साथ सह-अस्तित्व की कमजोर मांग की स्थिति के कारण औसतन क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत थी। हालांकि, फरवरी 2022 में कृषि मजदूरी वृद्धि जून 2021 में 1.1 प्रतिशत के निचले स्तर से बढ़कर 6.0 प्रतिशत हो गई, जबकि गैर-कृषि मजदूरी वृद्धि फरवरी 2022 में बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गई, जो मई 2021 में 0.2 प्रतिशत थी, जो आंशिक रूप से प्रतिकूल आधार प्रभाव को दर्शाती है।

6. निष्कर्ष

11.2.31 संक्षेप में, हेडलाइन मुद्रास्फीति मई-जून 2021 में दूसरी लहर के दौरान ऊपरी वहनीयता स्तर और जनवरी-मार्च 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के साथ-साथ तीसरी लहर के कारण भी 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। अक्टूबर और नवंबर 2021 में भारी बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी दिसंबर 2021 में सर्दियों की फसल की आमद के साथ वापस कम होना शुरू हो गया, लेकिन सर्दियों में आई कीमतों में यह गिरावट सामान्य से कम थी। सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप से घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति के लिए अंतरराष्ट्रीय

खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के पास-श्रू को रोकना जारी है। उच्च औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों, परिवहन लागत, तथा वैश्विक रसद और आपूर्ति शृंखला बाधाओं से लागत-प्रेरित दबाव कोर मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालना जारी रखे हुए है। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि के बीच थोक और खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति के मध्य पर्याप्त अंतर, खुदरा मुद्रास्फीति के लिए इनपुट लागत दबावों के संभावित पास-श्रू का जोखिम पैदा करता है, हालांकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती पास-श्रू को स्थिर कर रही है। यूक्रेन में संघर्ष और इसके परिणामस्वरूप पण्य की कीमतों में वृद्धि ने शेष विश्व की तरह भारत में भी मुद्रास्फीति के लिए परिदृश्य को धूमिल कर दिया है।

11.3 मुद्रा एवं ऋण

11.3.1 रिजर्व बैंक के समायोजनकारी नीतिगत रुख से वर्ष भर मौद्रिक और क्रेडिट की स्थिति प्रायः समान रही। मौजूदा कठोर परिस्थितियों में अधिकतर वैश्विक स्पिलओवर के उपरांत समग्र वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनीं रहीं। आरक्षित मुद्रा (आरएम) में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)¹⁸ बढ़ोत्तरी के पहले दौर के प्रभावों के लिए समायोजित किए जाने के पश्चात नरमी देखी गई। वर्ष 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितता के चलते एहतियाती मुद्रा मांग में नरमी देखी गई। इसके साथ ही मुद्रा के वेग में बढ़त की गुंजाइश देखी गई जो वस्तुतः अर्थव्यवस्था उपभोक्ता मांग में सुधार की स्थिति को दर्शाती है। वर्ष के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम₃) वृद्धि की गति कम हुई जो अपने बड़े घटक-समग्र जमाओं के रुख को दर्शाती है। जबकि दूसरी तरफ बैंक क्रेडिट वृद्धि को, विशेष रूप से अगस्त 2021 से, गति मिली जो बनी रही।

11.3.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 में आरक्षित मुद्रा (आरएम) के अंतर्निहित गतिशील उतार-चढ़ाव पर और उससे रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र में हुए परिवर्तनों पर विचार किया गया है। उप-खंड

¹⁸ 27 मार्च 2021 से प्रभावी सीआरआर में 3.0 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत की वृद्धि, 22 मई 2021 से प्रभावी सीआरआर 4.0 प्रतिशत; और इसके अतिरिक्त 21 मई 2022 से प्रभावी सीआरआर 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

3 में मुद्रा आपूर्ति की गतिविधियों की इसके घटकों और स्रोतों के मद्देनजर जांच की गई है, जो बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देयताओं के उतार-चढ़ाव पर प्रकाश डालती है। वर्ष के दौरान बैंक ऋणों की मजबूती को उप-खंड 4 में दर्शाया गया है। इसके बाद समापक निष्कर्ष है।

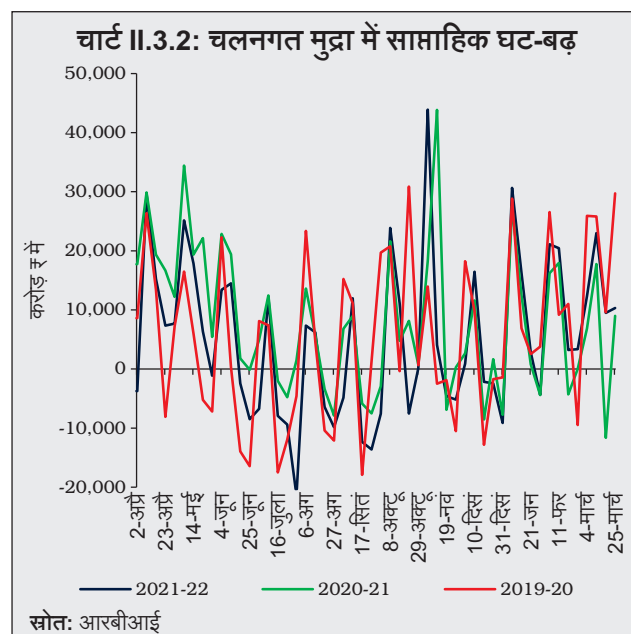
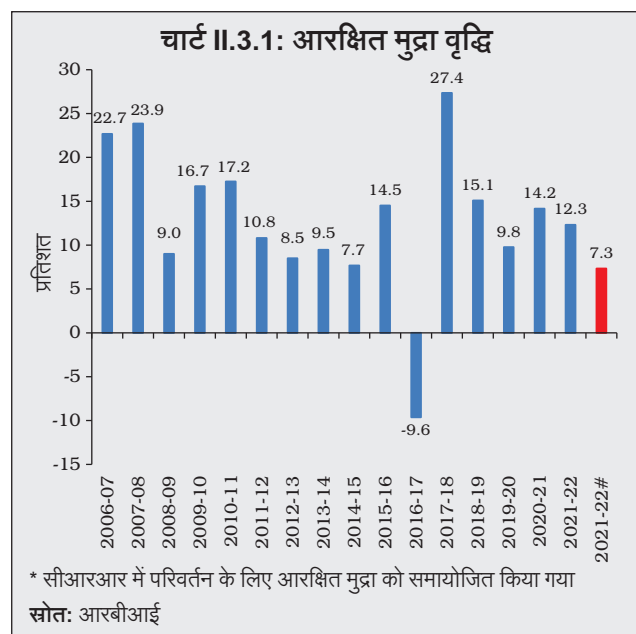
2. आरक्षित मुद्रा¹⁹

II.3.3 आरक्षित मुद्रा, जो अनिवार्य रूप से रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र का एक विश्लेषणात्मक और शोधपरक उद्घरण है, और इसकी मौद्रिक देयताओं पर ध्यान केंद्रित करती है, में संचलनगत मुद्रा, बैंकों की जमाशियों एवं रिजर्व बैंक में धारित अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। आरक्षित मुद्रा में 2021-22 में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पूर्व के 14.2 प्रतिशत से कम के साथ ही 10.6 प्रतिशत (2012-21) की दशकीय औसत से अधिक रही [चार्ट II.3.1; परिशिष्ट सारणी 4]। 27 मार्च 2021 से प्रभावी सीआरआर में 100 आधार अंकों

की बढ़ोत्तरी को समायोजित करने के पश्चात - आरक्षित मुद्रा में 2021-22 में पिछले वर्ष के 18.0 प्रतिशत की तुलना में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

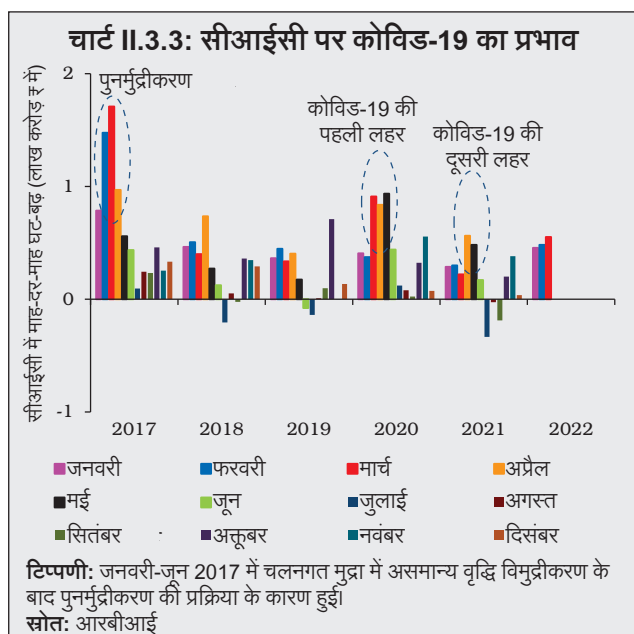
II.3.4 इसके घटकों में से, वर्ष 2021-22 में आरक्षित मुद्रा का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा चलनगत मुद्रा (सीआईसी) का था। हालांकि आरएम में समग्र विस्तार के निर्धारण में मुद्रा का योगदान जून 2021²⁰ में चरम पर रहा, फिर भी वर्ष के दौरान समग्र आरएम विस्तार में चलनगत मुद्रा का हिस्सा 88 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 89 प्रतिशत) रहा जो 108 प्रतिशत के दशकीय औसत (2012-21) से थोड़ा कम था।

II.3.5 सामान्यतः चलनगत मुद्रा की मांग में एक पूर्वानुमेय अंतर्मासिक ढंग देखा जाता है – परिवारों द्वारा किए गए लेनदेनों के कारण पहले पखवाड़े में मांग का विस्तार, उसके बाद परिवारों से बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा के विपरीत प्रवाह के कारण दूसरे पखवाड़े में कम मांग (चार्ट II.3.2)।



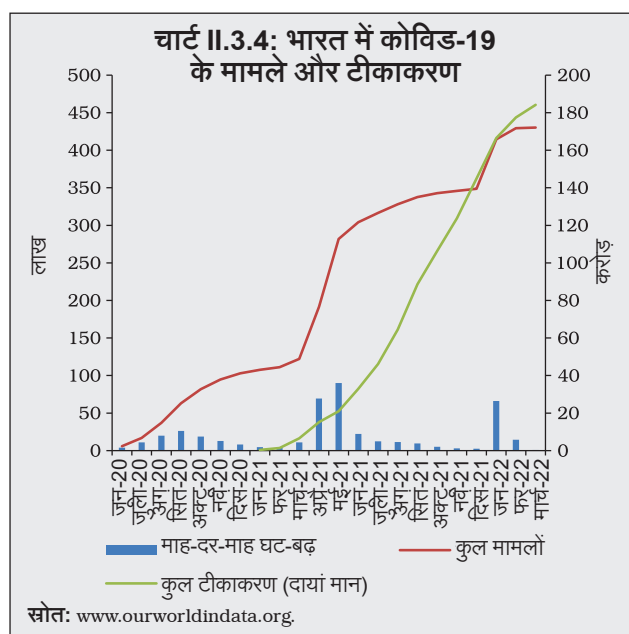
¹⁹ उप खंड 2 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात क्रमशः संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम शुक्रवार पर आधारित हैं।

²⁰ उस माह को छोड़कर जिसमें आरएम में संकुचन हुआ।

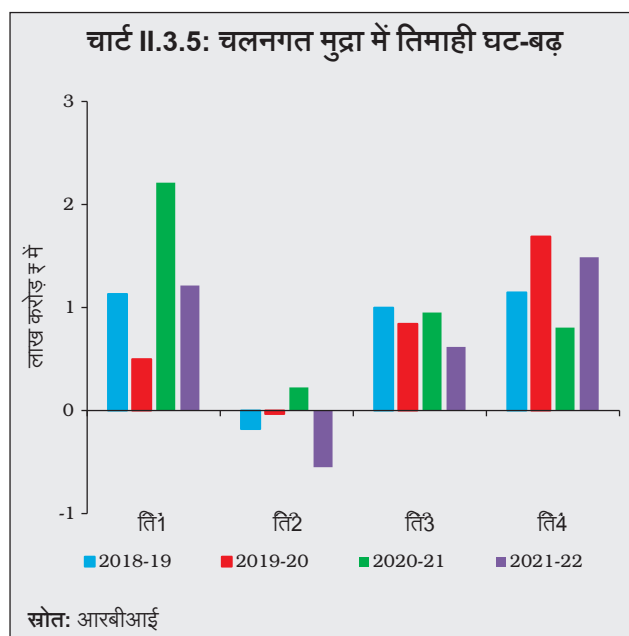


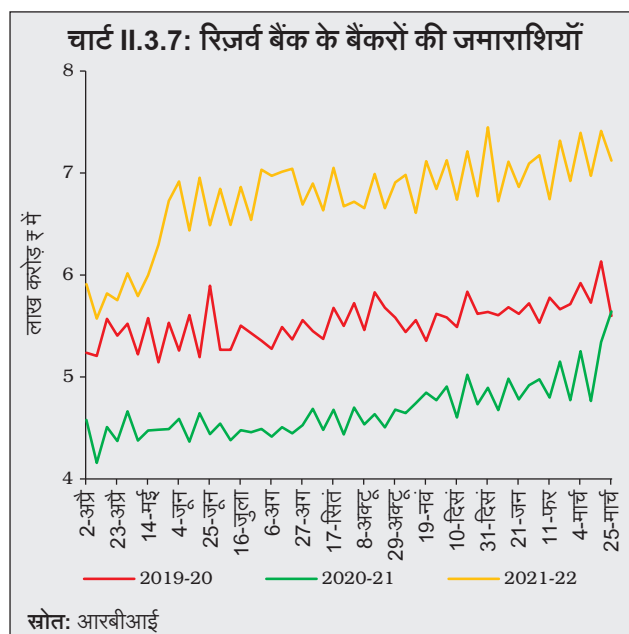
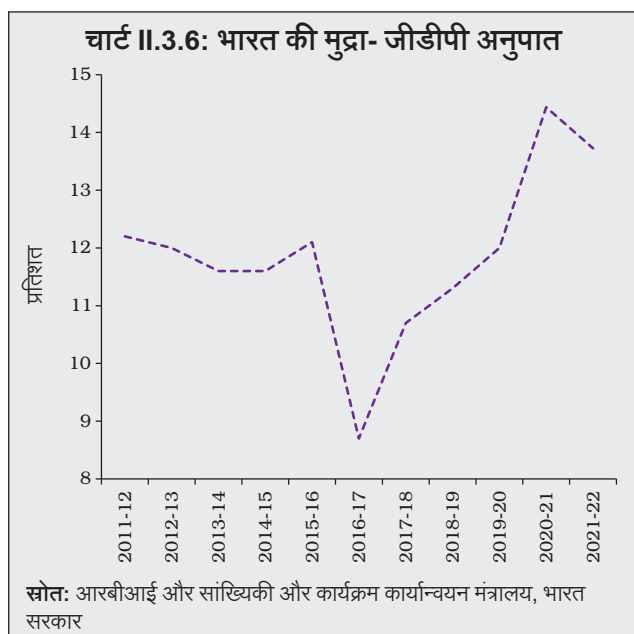
II.3.6 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण नकदी की अप्रत्याशित मांग से माह-दर-माह (एमओएम) सीआईसी विचरण में अप्रैल- मई 2021 में बढ़त हुई तथापि यह अप्रैल-जून 2020 की पहली लहर की तुलना में कुछ हद तक कम हुई जबकि इसमें महामारी पूर्व वर्षों की इसी अवधि की तुलना में बढ़त हुई (चार्ट II.3.3)। तत्पश्चात् जून 2021 से महामारी विज्ञान का वक्र (एपिडीमीअलाजिकल कर्व) अधोमुख होने से सीआईसी विचरण का निर्धारण अधिकतर मौसमी कारकों से किया गया (चार्ट II.3.4)।

II.3.7 अप्रैल-मई 2021 के दौरान महामारी की दूसरी लहर में मुद्रा की मांग में आई तेजी के बावजूद 2021- 22 में यह अपनी पूर्व मौसमी पैटर्न में आ गई। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जो रबी खरीद और खरीफ की बुआई से सम्बद्ध 2020-21 की पहली तिमाही और महामारी पूर्व वर्षों की तुलना से अपेक्षाकृत कम रही। इसके बाद वाली तिमाहियों में आर्थिक गतिविधि नकदी की प्रधानता वाले क्षेत्रों जैसे विनिर्माण एवं कृषि में मौसमी मंदी से सीआईसी में संकुचन हुआ। वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में सीआईसी का विस्तार हुआ जो कि त्योहारों और खरीफ की कटाई से मुद्रा की मांग को दर्शाता है। उसके बाद वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के दौरान रबी फसल की कटाई, विभिन्न



त्योहारों और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से सीआईसी का विस्तार सुस्पष्ट देखा गया (चार्ट II.3.5)। महामारी की तीव्रता में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में नकद-गहनता में सामान्यता वृद्धि होने पर वर्ष 2021- 22 में सीआईसी की कम वृद्धि 9.7 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 17.2 प्रतिशत) रही जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा-जीडीपी अनुपात गिरकर 13.7 प्रतिशत (2020-21 में 14.4 प्रतिशत) हो गया (चार्ट II.3.6)।



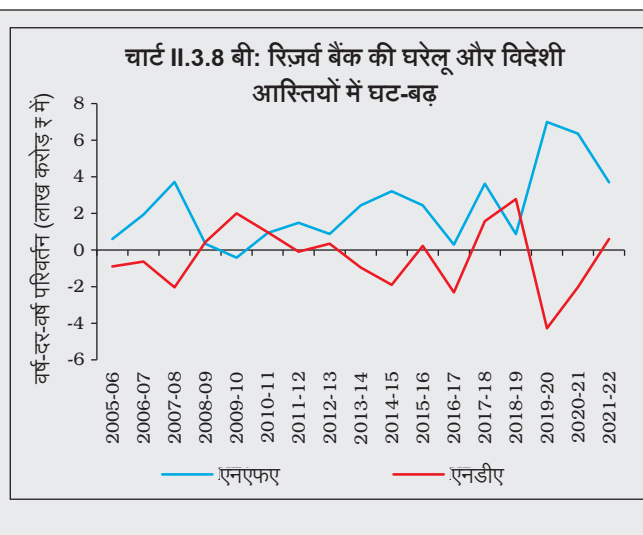
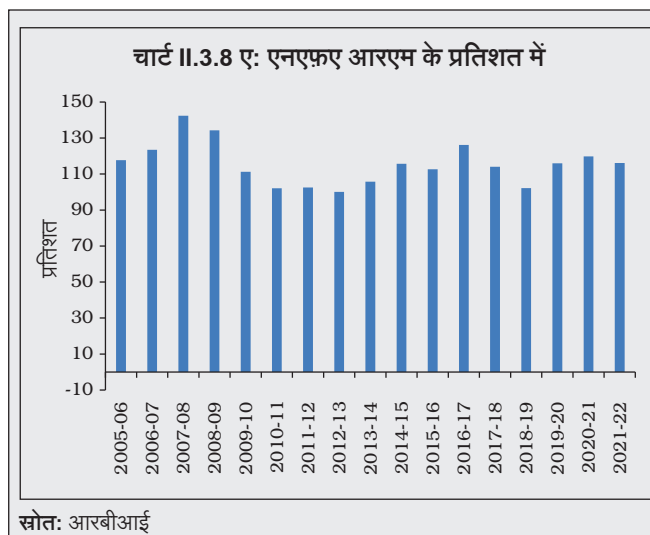


II.3.8 वर्ष 2021-22 में रिज़र्व बैंक में धारित बैंकरों की जमाराशियों में 25.3 प्रतिशत की बढ़त आई, जबकि पिछले वर्ष इसमें 0.8 प्रतिशत की मामूली बढ़त हुई थी। यह मुख्यतः सीआरआर में चरणबद्ध 100 आधार अंक बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत किए जाने से है (चार्ट II.3.7)।

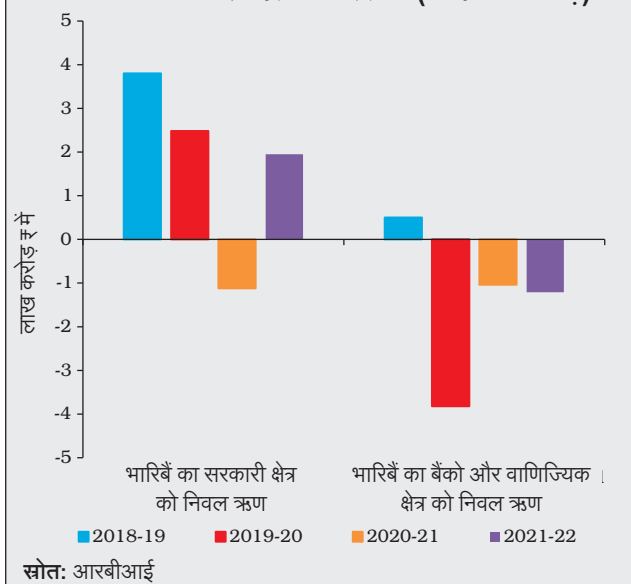
II.3.9 वर्ष 2021-22 के दौरान आरएम स्रोतों के अंतर्गत, आरएम वृद्धि की प्रमुख संचालक निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) थी, यद्यपि प्राधिकृत व्यापारियों से पिछले वर्ष ₹ 5.16

लाख करोड़ की तुलना में ₹2.07 लाख करोड़ कम की निवल खरीद की गई थी (चार्ट II.3.8ए और चार्ट II.3.8बी)। मौद्रिक नीति के उदार रुख के अनुरूप, चलनिधि प्रबंधन परिचालन ने रिज़र्व बैंक के निवल देशी आस्तियों (एनडीए) में वृद्धि की।

II.3.10 विशेष रूप से, हालांकि 2021-22 के दौरान निवल खुले बाजार से खरीद (जिसमें राज्य विकास ऋण में ओएमओ सहित विशेष ओएमओ की नीलामी जिसमें प्रतिफल वक्र में चलनिधि वितरण हेतु प्रतिभूति की एक साथ खरीद बिक्री की जाती है



चार्ट II.3.9: निवल देशी आस्तियां (व-द-व घट-बढ़)



शामिल है) कुल ₹2.14 लाख करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 में सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में ₹1.95 लाख करोड़ की बढ़त आई। दूसरी ओर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र (मुख्यतः पीडी) को निवल ऋण में कमी ने

प्राथमिक तौर पर निवल चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अवशोषण को परिलक्षित किया (चार्ट II.3.9)।

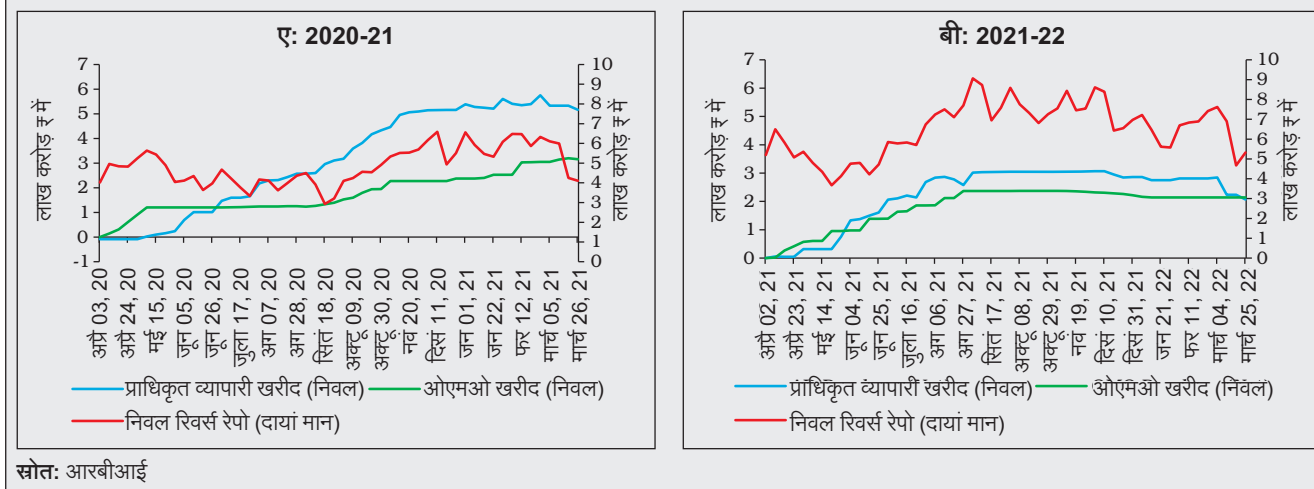
II.3.11 वर्ष 2021-22 के दौरान निवल एलएएफ की स्थिति रिवर्स रेपो अवस्था में थी, जो औसतन ₹6.7 लाख करोड़ थी और प्रणाली स्तर पर पर्याप्त चलनिधि को दर्शाता है (चार्ट II.3.10)।

3. मुद्रा आपूर्ति²¹

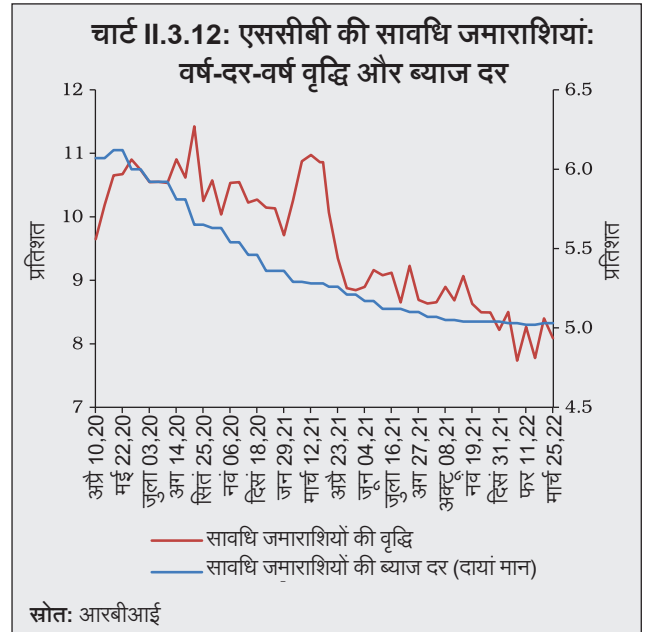
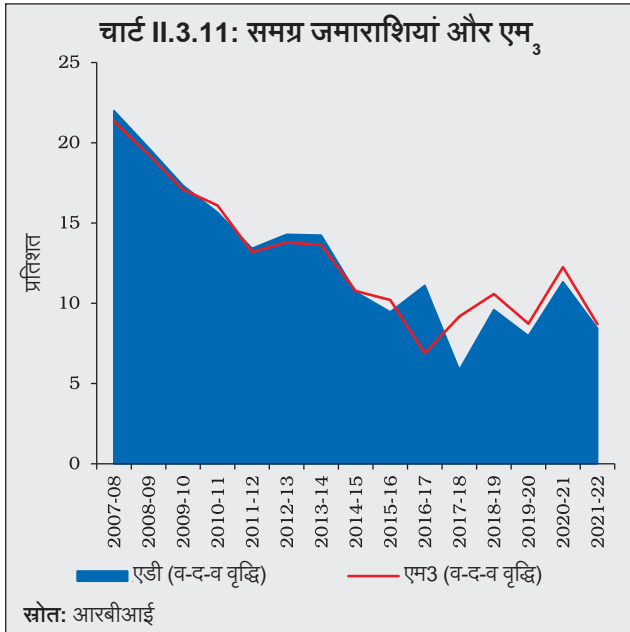
II.3.12 वर्ष 2016-17 तक लंबी गिरावट के उपरांत स्थिर, एम₃ जिसमें जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (सीडब्ल्यूपी), समग्र जमाराशियां (एडी) और रिजर्व बैंक में धारित अन्य जमाराशियां शामिल हैं- वर्ष 2021-22 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पूर्व 12.3 प्रतिशत) दर्ज की गई जो मीयादी जमाओं से संचालित थी (चार्ट II.3.11)।

II.3.13 घटकों की दृष्टि से, एम₃ का विस्तार समग्र जमाराशियों (एडी) से संचालित रहा, जो इसका सबसे बड़ा घटक (85 प्रतिशत भाग) था। वस्तुतः वर्ष के दौरान एम₃ में हुई वृद्धि में समग्र जमाराशियों (एडी) का 82 प्रतिशत योगदान रहा। इसके साथ ही ब्याज दरों में विचारणीय गिरावट के बावजूद मीयादी

चार्ट II.3.10: चलनिधि का अंतर्वेशन/अवशोषण

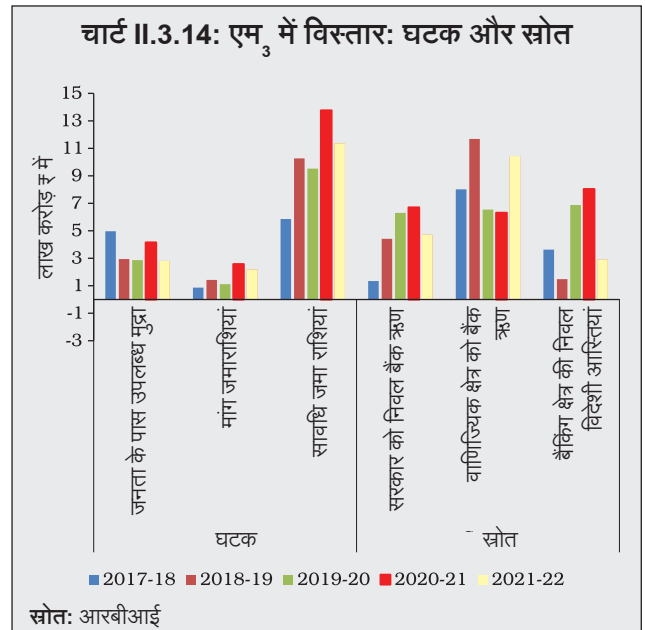
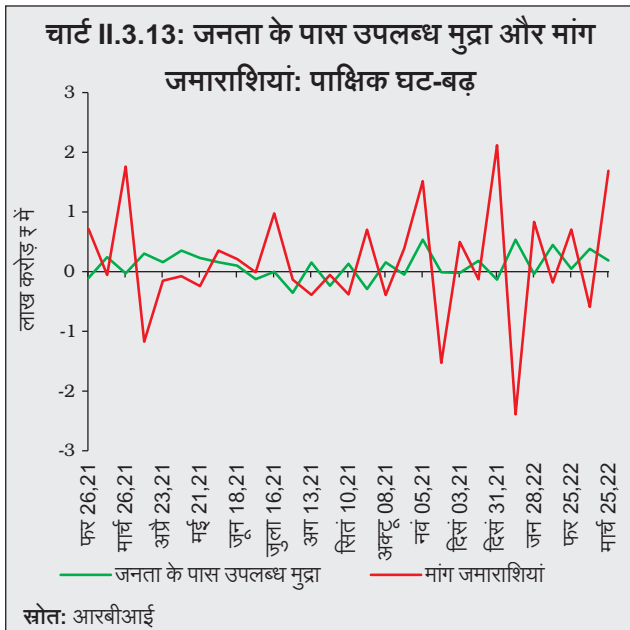


²¹ उप खंड 3 और 4 में, वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंत से संबंधित वृद्धि और अन्य अनुपात क्रमशः संबंधित वित्तीय वर्ष/तिमाही/माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार पर आधारित हैं।



जमाराशियों में 8.1 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 10.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई (चार्ट II.3.12)। हमेशा की तरह मांग जमाराशियों में अस्थिरता बनी रही जो कि पिछले वर्ष के 17.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह व्यापक रूप से जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में परिवर्तनों को परिलक्षित करती है (चार्ट II.3.13)।

II.3.14 वर्ष 2021-22 में स्रोत पक्ष से वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण के साथ सरकार को दिए गए निवल बैंक ऋण और बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों ने एम₃ के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई (चार्ट II.3.14)। इन स्रोतों में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण- स्रोत पक्ष से एम₃ के सबसे बड़े घटक में एक वर्ष पूर्व की तुलना में अधिक वृद्धि हुई।



सारणी II.3.1: मौद्रिक कुल राशियां

मद	25 मार्च 2022 के अनुसार बकाया (करोड़ ₹ में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर(प्रतिशत में)		
		2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
I. आरक्षित मुद्रा (आरएम)	39,20,298	9.8	14.2	12.3
II. मुद्रा आपूर्ति (एम3)	2,04,89,597	8.7	12.3	8.7
III. एम3 के प्रमुख घटक				
III.1. जनता के पास उपलब्ध मुद्रा	30,37,622	14.0	17.7	10.2
III.2. समग्र जमाराशियां	1,73,99,596	8.0	11.3	8.4
IV. एम3 के प्रमुख स्रोत				
IV.1. सरकार को निवल बैंक ऋण	62,04,211	14.2	13.2	8.2
IV.2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	1,26,10,042	6.3	5.7	9.0
IV.3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	48,50,355	22.4	21.4	6.3
V. एफसीएनआर (बी) का निवल एम ₃	2,03,60,720	8.7	12.6	8.9
VI. मुद्रा गुणक*	5.2	5.0	4.8	3.8

* कॉलम 3,4 और 5 का डेटा वृद्धिशील मुद्रा गुणक को दर्शाता है।

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: आरबीआई

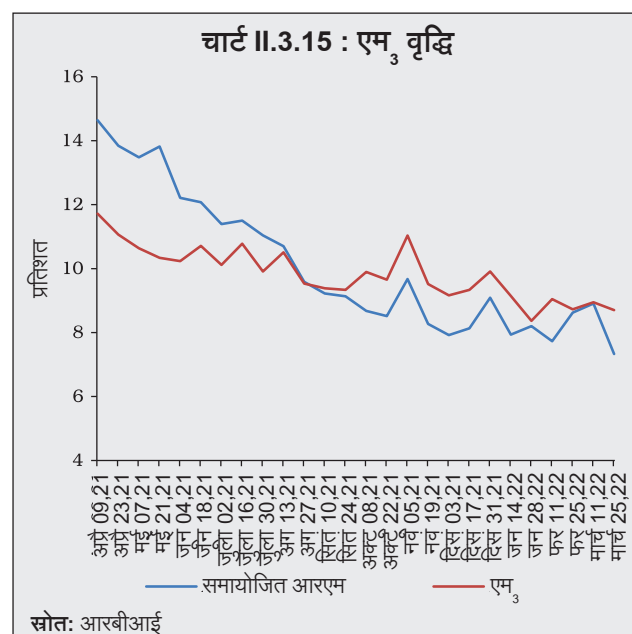
II.3.15 दूसरी ओर कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के मध्य सुरक्षित आश्रय की तलाश में एक वर्ष पूर्व बैंकों ने एसएलआर पोर्टफोलियो के संवर्धन से अलग सरकार को दिया गया निवल बैंक ऋण एक वर्ष पूर्व के 13.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 में 8.2 प्रतिशत कम हो गया (सारणी II.3.1)।

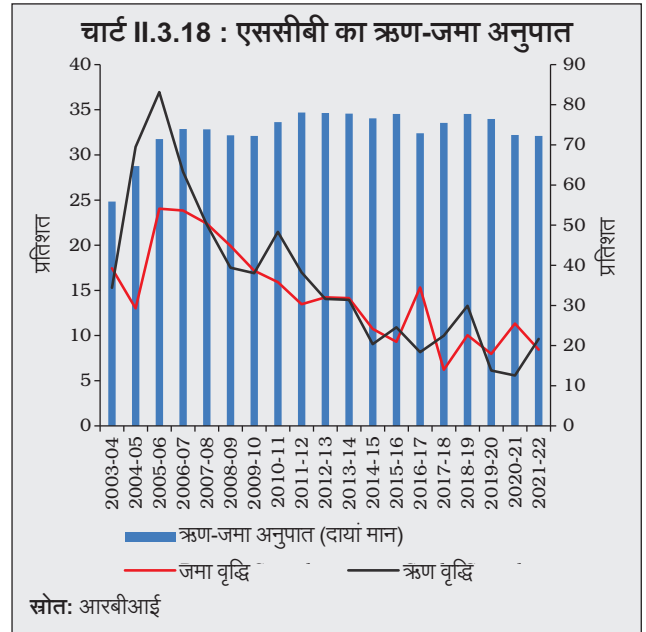
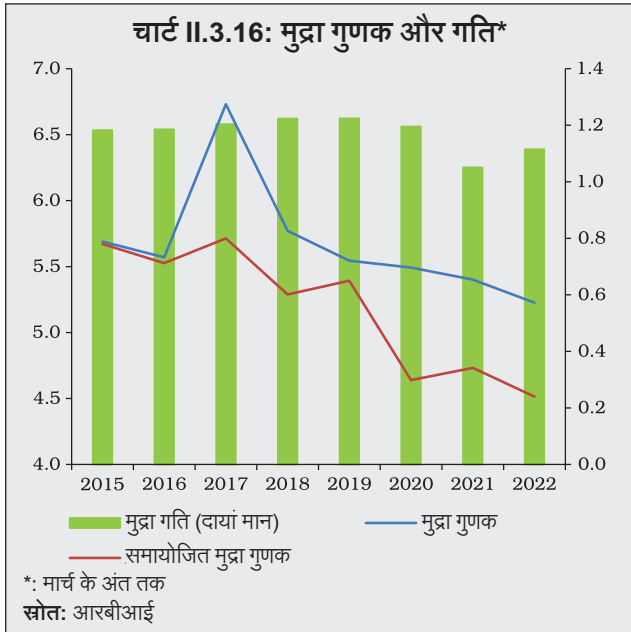
मुख्य मौद्रिक अनुपात

II.3.16 वर्ष 2021-22 में मुद्रा गुणक 5.2 रहा जो उसके 5.7 के दशकीय औसत(2012-21) से कम है। रिवर्स रेपो के लिए समायोजित किए जाने पर - जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से अधिक सार्थक और केंद्रीय बैंक में धारित बैंकों की जमाओं के समान है- मुद्रा गुणक और घटकर 4.5 रह गया। वर्ष 2021-22 में कमजोर मुद्रा गुणक के साथ आरएम वृद्धि में मंदी (सीआरआर बढ़ोत्तरी के प्रथम दौर के प्रभाव हेतु समायोजित) पिछले वर्ष की तुलना में एम₃ की धीमी वृद्धि दिखाता है (चार्ट II.3.15 और II.3.16)।

II.3.17 वर्ष 2021-22 में मुद्रा-जमा अनुपात 17.5 प्रतिशत रहा जो 15.3 प्रतिशत के अपने दशकीय औसत (2012-21) से अधिक था। इसका स्तर मार्च 2021 की समाप्ति की तुलना में समान रहा जो महामारी से संबंधित अनिश्चितता के कारण

जनता की अधिमानता में परिवर्तन होते हुए उन्हें नकदी जो कि अत्यधिक तरल आस्ति है, को प्राथमिकता देता है उसमें वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी नहीं हुई। आरक्षित निधि- जमा अनुपात 4.2 प्रतिशत था (एक वर्ष पूर्व 3.6 प्रतिशत) जो वर्ष 2021-22 के दौरान सीआरआर में बढ़त के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट II.3.17)।

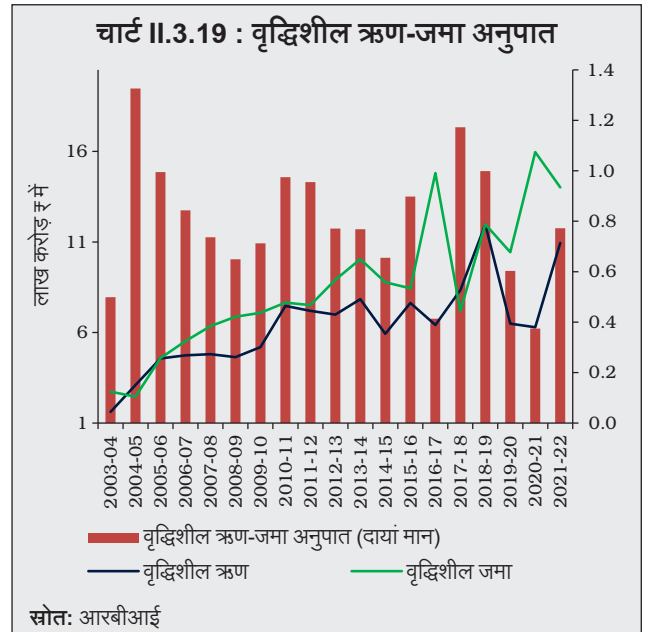
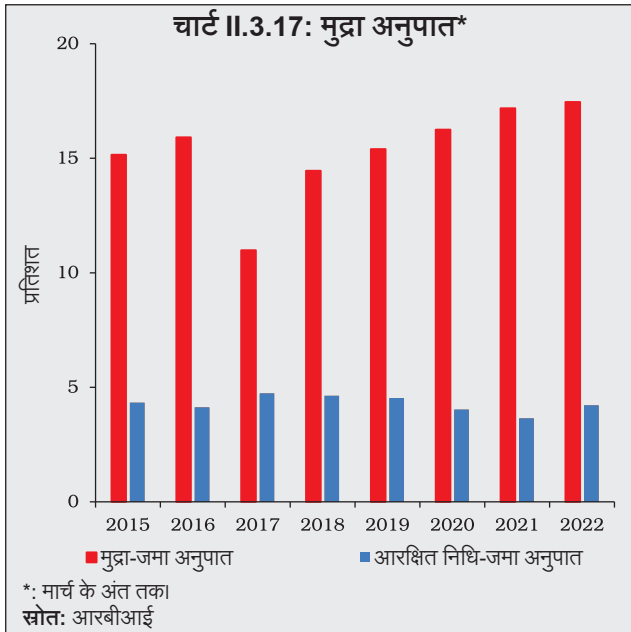


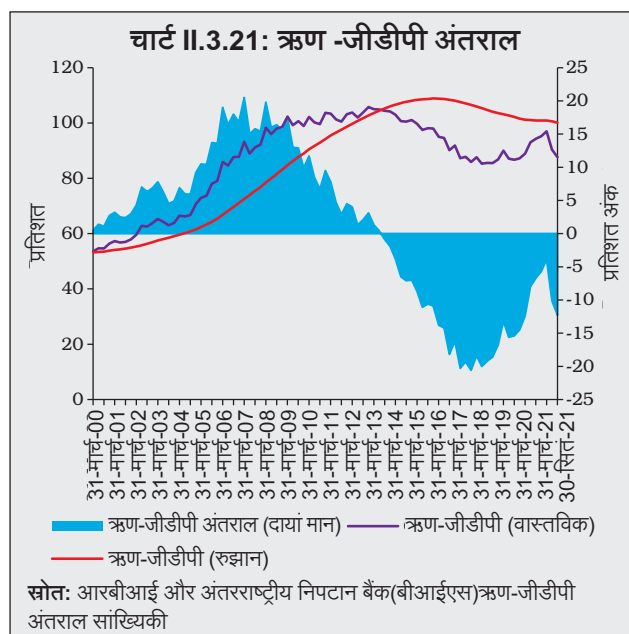
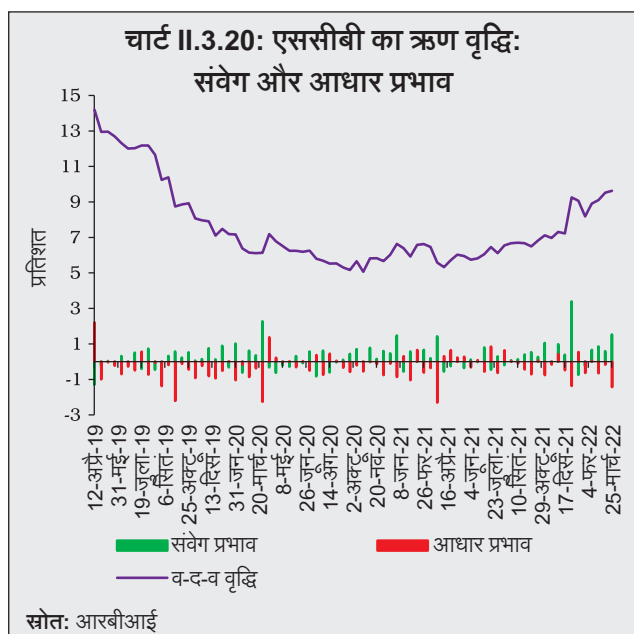


4. क्रेडिट

II.3.18 वर्तमान नीति निर्धारण के अनुसार सीआरआर और एसएलआर क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में लगभग 78 प्रतिशत जमाराशियां ऋण देने के लिए उपलब्ध थीं। वर्ष 2021-22 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों

(एससीबी) का ऋण-जमा अनुपात मार्च 2021 (72.4 प्रतिशत) की समाप्ति के स्तर पर 72.2 प्रतिशत से संयमित रहा, जिससे व्यापक रूप से क्रेडिट विस्तार ने जमा संग्रहण के साथ 2019-20 और 2020-21 की अवधि को पीछे छोड़ते हुए अपनी गति जारी रखी (चार्ट II.3.18 और चार्ट II.3.19)।





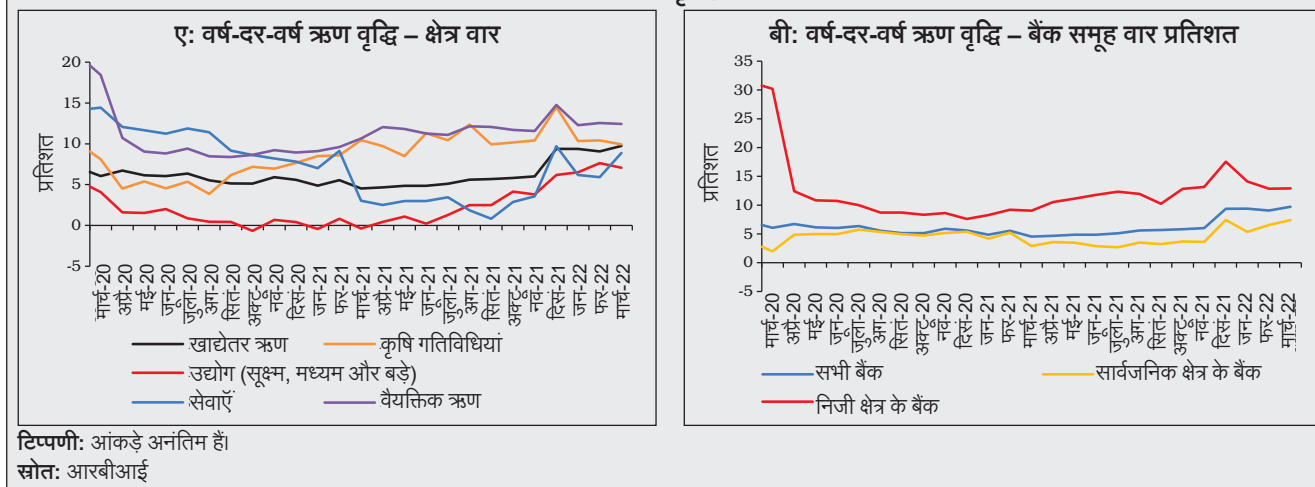
II.3.19 वर्ष 2021-22 में एससीबी ऋण में वर्ष-दर-वर्ष की मंद पड़ी गति बहाल हुई। बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 विवरणी में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार एससीबी में ऋण उठाव(ऑफटेक) की गति अगस्त 2021 के अंत से सकारात्मक बनी रही और वर्ष 2021-22 के लिए एक वर्ष पूर्व के 5.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.6 प्रतिशत बनी रही (चार्ट II.3.20)। तथापि ऋण - जीडीपी अंतराल अधिक बना रहा जो अर्थव्यवस्था में ऋण मांग में सतत मंदी को दर्शाता है(चार्ट II.3.21)।

II.3.20 वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में गिरावट रहने के उपरांत वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि कायम रखने हेतु किए गए सतत प्रयास के साथ ही अर्थव्यवस्था में ऋण मांग की स्थिति सुधार के लिए सरकार के उठाए कदम विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उठाव(ऑफटेक)को मिली

गति को प्रतिबिंबित करता है। बैंक ऋण²² क्षेत्रवार अभिनियोजन के आंकड़ों के अनुसार कृषि और अनुषंगी गतिविधियां मार्च 2021 के 10.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 में 9.9 प्रतिशत से बढ़ीं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी सरकारी ब्याज सहायता योजना के लगातार समर्थन से आघात सह कृषि क्षेत्र में बैंक ऋण वृद्धि सुदृढ़ बनी रही। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के उपरांत उद्योगों की ऋण वृद्धि में लगातार सुधार हुआ और मार्च 2022 में इसकी गति 7.1 प्रतिशत तक हो गई। विशेष रूप से मध्यम उद्योगों में एक वर्ष पूर्व के 34.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 में 71.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के ऋण में एक वर्ष पूर्व के 3.9 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में दर्ज की गई ऋण मांग मुख्यतः भारत सरकार और रिज़र्व बैंक की नीतियों से इस क्षेत्र को संभालने हेतु किए गए उपायों के कारण है। बड़े उद्योग में ऋण

²² बैंक ऋण आंकड़ों के क्षेत्रगत विनियोजन में, सकल बैंक ऋण और खाद्येतर ऋण पाक्षिक आधार पर खंड 42 विवरणी पर आधारित हैं जिसमें सभी एससीबी शामिल हैं, जबकि क्षेत्रगत खाद्येतर ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी)विवरणों पर आधारित हैं, जिसमें सभी एससीबी द्वारा कुल खाद्येतर ऋण विस्तार में से 94 प्रतिशत चुनिंदा बैंकों का है और माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है।

चार्ट II.3.22: खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि का क्षेत्रवार अभिनियोजन



वृद्धि दिसंबर 2021 तक संकुचन की स्थिति में रहने के उपरांत जनवरी 2022 से सकारात्मक होकर मार्च 2022 में 0.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.3.22 ए और सारणी II.3.2)

II.3.21 जहां तक उद्योगों के उप- क्षेत्रों में ऋण का सरोकार है, इंजीनियरी पेय पदार्थ और तंबाकू, रसायन और रसायन

उत्पादों, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, इंफ्रास्ट्रक्चर, चमड़े और चमड़े के उत्पादों, खनन और उत्खनन, पेट्रोलियम, कोयला उत्पादों और परमाणु ईंधन, वस्त्र, रबर, प्लास्टिक और इनके उत्पादों, वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरणों के ऋणों में मार्च 2022 में वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर तीव्र वृद्धि दर्ज की

सारणी II.3.2: चुनिंदा क्षेत्रों को ऋण अभिनियोजन

क्षेत्र	25 मार्च 2022 के अनुसार बकाया (कोड़ ₹ में)	वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि (प्रतिशत)		
		2019-20*	2020-21#	2021-22##
1	2	3	4	5
खाद्येतर ऋण	1,18,35,628	6.1	4.5	9.7
1. कृषि और अनुषंगी गतिविधियाँ	14,66,514	8.1	10.5	9.9
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	31,71,909	4.1	-0.4	7.1
2.1. सूक्ष्म और लघु	4,95,281	4.5	3.9	21.5
2.2. मध्यम	2,42,269	3.4	34.5	71.4
2.3. बड़े	24,34,359	4.1	-2.5	0.9
(i) इंफ्रास्ट्रक्चर	12,02,694	2.7	1.6	9.3
(ए) ऊर्जा	6,09,773	0.3	-0.3	7.2
(बी) दूरसंचार	1,37,381	29.4	-21.3	18.6
(सी) सड़क	2,70,806	3.6	27.6	17.0
(ii) रसायन और रासायनिक उत्पाद	2,14,141	10.2	-6.8	8.7
(iii) मूल धातु और धातु उत्पाद	2,96,427	-6.3	-6.4	-9.2
(iv) खाद्य प्रसंस्करण	1,73,530	-1.3	8.2	10.9
(v) वस्त्र	2,25,096	-3.6	5.0	10.1
3. सेवाएँ	30,36,122	14.4	3.0	8.9
4. वैयक्तिक ऋण	33,74,876	18.4	10.7	12.4

* मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 # मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 ## मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत: आरबीआई

गई हालांकि रत्न और आभूषण, कागज और कागज के उत्पादों तथा लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों की ऋण वृद्धि कम हो गई। इसी अवधि के दौरान मूल धातु और धात्विक उत्पादों, सीमेंट और सीमेंट उत्पादों, कांच और कांच के सामान के बैंक ऋण में संकुचन दर्ज किया गया।

II.3.22 वर्ष 2021-22 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उद्योग क्षेत्र का प्रमुख घटक है, के ऋण वृद्धि में सुधार हुआ। मार्च-2022 में इस क्षेत्र ने ऋण वृद्धि में पिछले वर्ष के 1.6 प्रतिशत की तुलना में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि मुख्यतः सड़क निर्माण, पावर और दूरसंचार क्षेत्र से संचालित है।

II.3.23 वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में सेवा क्षेत्र के ऋण वृद्धि में बढ़त आई और मार्च 2022 में एक वर्ष पूर्व के 3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 8.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। ऋण वृद्धि में यह तेजी मुख्यतः उप-क्षेत्रों जैसे एनबीएफसी और व्यापार के कारण है, जो कुल सेवा क्षेत्र ऋण का लगभग 58 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 के दौरान वैयक्तिक ऋण खंडों में बैंक ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रही यह प्राथमिक रूप से इस क्षेत्र के बड़े घटक आवास तदोपरांत वाहन ऋण से संचालित हुई।

II.3.24 बैंक समूहों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि मार्च 2022 में 7.4 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 2.9 प्रतिशत) तक सुधरने से पूर्व यह नवंबर 2021 तक 4 प्रतिशत थी जो वैयक्तिक ऋण से संचालित थी। निजी क्षेत्र के बैंकों में ऋण विस्तार एक वर्ष पूर्व 9 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 तक सुधरकर 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.3.22बी)।

5. निष्कर्ष

II.3.25 सारांश के रूप में कहें तो, वर्ष के दौरान कुल प्रमुख मौद्रिक और ऋण राशियां रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाई गई समायोजनकारी मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप रहीं। समग्र रूप से वित्तीय स्थिति, अस्थिर वैश्विक परिवेश और विचलन मौद्रिक नीति रुख, भू-राजनीतिक तनाव और लगातार आपूर्ति बाधाओं

के उपरांत भी रिकवरी के लिए सहायक रहीं। महामारी पूर्व के वर्षों की तुलना में सीआईसी में एहतियाती मुद्रा मांग में कमी और सामान्य मौसमी पैटर्न पुनः देखा गया। आर्थिक गतिविधि के साथ-साथ ऋण वृद्धि की गति भी तेज हुई। इसके अतिरिक्त घरेलू आर्थिक गतिविधि में व्यापक आधार पर वापसी से ऋण मांग को स्थिरता मिलेगी। सरकार द्वारा उठाए गए कदम जैसे पीएलआई योजना और ईसीएलजीएस सहायता का बढ़ाया जाना ऋण वृद्धि के लाभकारी प्रभाव हैं। इससे उधारकर्ताओं द्वारा वैश्विक स्पिलओवर से सामना कर रहे जोखिम प्रभाव और कोविड-19 लहर की पुनरावृत्ति की अनिश्चितता की स्थिति को सीमित करने में सहायक होगा।

II.4 वित्तीय बाजार

II.4.1 वैश्विक वित्तीय बाजार, जो आमतौर पर वर्ष 2021 के अधिकांश भाग के दौरान उत्साहवर्धक बने रहे, कई केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति समायोजन की वापसी की शुरुआत की प्रत्याशा में वर्ष 2022 की पहली तिमाही में अस्थिर हो गए। जोखिम के रुख में अचानक और बड़े बदलाव के कारण अस्थिरता बढ़ी और यूक्रेन-रूस संघर्ष के बढ़ने के साथ-साथ आस्तियों की कीमतों में उछाल और पुनर्मूल्यांकन के कारण वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव आया।

II.4.2 वर्ष के शुरुआती दौर में, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चलनिधि की प्रचुरता और समायोजनकारी मौद्रिक नीतियों के कारण वित्तीय आस्ति की कीमतें अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुँच गयी थीं और इसे प्रोत्साहन पैकेजों तथा कभी-कभार शांति को भंग करने वाले उथल-पुथल के दौर सहित कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील ने भी बल दिया क्योंकि मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव हुए और इनका उद्देश्य ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के कारण उत्पन्न चलनिधि संबंधी आशंकाओं को दूर करना था। ऊर्जा-कीमतों में बढ़ोतरी और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में लगातार व्यवधानों ने बाजार के रुख को अस्थिर कर दिया। उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में इक्विटी

बाजारों ने हालत में सुधार होने पर स्पिलओवर और सुरक्षा तथा जोखिम दोनों की ही ओर सामयिक पलायन का अनुभव किया। सुरक्षित निवेश स्थल की मांग से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। इन घटनाक्रमों की प्रतिक्रिया में वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल भी बढ़ गए। मार्च 2022 में तेल समेत पण्य कीमतें पिछले चौदह वर्षों के अपने उच्चतम स्तर को छूने के साथ कच्चे तेल की कीमतों के साथ तेजी से बढ़ीं, क्योंकि भू-राजनीतिक तनाव, उथल-पुथल के ये दौर तथा बाजार के विचलित रुख एक साथ आ गए।

11.4.3 भारत में, सुलभ चलनिधि की स्थितियों के बीच वित्तीय बाजार जीवंत बने रहे, हालांकि अप्रैल-मई 2021 के दौरान महामारी की दूसरी लहर ने रुख को प्रभावित किया। बड़े पैमाने पर वैक्सिन रोलआउट और आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान के विश्वास से वैश्विक समकक्षों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इक्विटी बाजार ने वर्ष 2021-22 में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है। मौद्रिक और राजकोषीय उपायों से प्राप्त निरंतर समर्थन से घरेलू इक्विटी एवं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) और अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) को बल मिला और इसने बॉन्ड प्रतिफल में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए निवेशक-उत्साह को पुनः जीवित किया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, मजबूत कॉर्पोरेट अर्जन की सहायता से गैर-विघटनकारी तरीके से बाजार से पर्याप्त संसाधन जुटाए गए। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में नीतिगत रुख को सामान्य बनाए जाने की घोषणाओं और ओमिग्रॉन के तेजी से प्रसार के बाद वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में निवेशक सतर्क हो गए। वर्ष 2021-22 में सेंसेक्स ने वैश्विक समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न चलनिधि उपायों के साथ चलनिधि स्थितियों को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया। मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के बीच दुनिया के केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्य होने की प्रत्याशा के साथ-साथ अमेरिकी राजकोषीय

प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) प्रतिफल पर दबाव बढ़ गया। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह ने वर्ष के दौरान भारतीय रुपये के कमजोर होने में योगदान दिया।

11.4.4 मुद्रा बाजार के विकास का विवरण उप-खंड 2 में दिया गया है। सरकारी-प्रतिभूति प्रतिफल की चर्चा उप-खंड 3 में की गई है। उप-खंड 4 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में विकास को प्रस्तुत करता है। उप-खंड 5 घरेलू इक्विटी बाजार में विकास की रूपरेखा तैयार करता है, जिसके बाद उप-खंड 6 में विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव पर चर्चा की गई है। अंतिम उप-खंड कुछ दूरदेशी परिप्रेक्ष्य के साथ निष्कर्ष स्वरूप टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

2. मुद्रा बाजार

11.4.5 अप्रैल-मई 2021 में महामारी की दूसरी भयानक लहर से उत्पन्न तबाही के बावजूद, वर्ष 2021-22 के दौरान मुद्रा बाजार स्थिर रहा, क्योंकि रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि²³ बनाए रखी है।

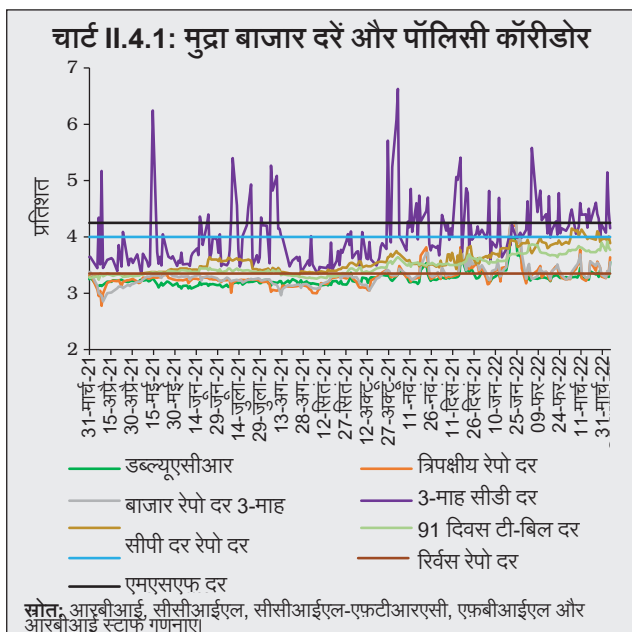
11.4.6 असुरक्षित मांग मुद्रा बाजार में भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - आमतौर पर पॉलिसी कॉरिडोर के मानक के नीचे कारोबार किया जाता है, यानी स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो, वर्ष के दौरान सिस्टम में पर्याप्त तरलता को दर्शाता है (चार्ट 11.4.1)। नीति दर पर डब्ल्यूएसीआर का औसत प्रसार वर्ष 2021-22 में (-) 75 आधार अंक (बीपीएस) तक बढ़ गया, जो वर्ष 2020-21 में (-) 63 बीपीएस था।

11.4.7 वर्ष 2020-21 में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए अग्रसक्रिय चलनिधि उपायों के कारण, डब्ल्यूएसीआर की भिन्नता के गुणांक²⁴ द्वारा मापी गई मांग मुद्रा खंड में अस्थिरता 8.34 से काफी कम होकर 4.05 तक आ गई।

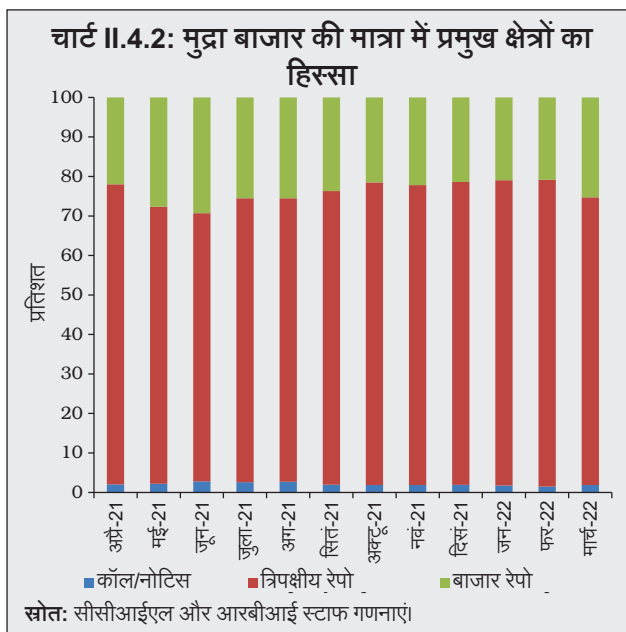
²³ चलनिधि प्रबंधन परिचालन से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय III में शामिल है।

²⁴ भिन्नता के गुणांक को मानक विचलन और माध्य के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

चार्ट II.4.1: मुद्रा बाजार दरें और पॉलिसी कॉरीडोर



चार्ट II.4.2: मुद्रा बाजार की मात्रा में प्रमुख क्षेत्रों का हिस्सा

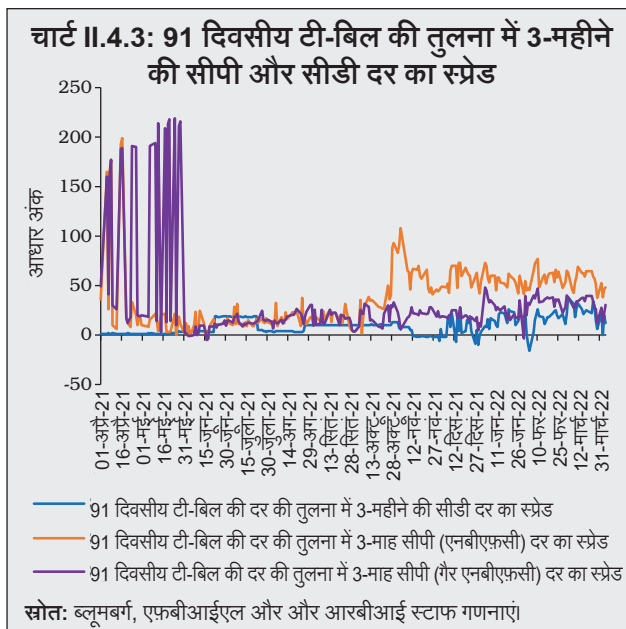


II.4.8 मुद्रा बाजार में औसत दैनिक वॉल्यूम (मांग मुद्रा, त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो को एक साथ लेकर, शनिवार को छोड़कर) वर्ष 2021-22 के दौरान 35 प्रतिशत बढ़कर ₹4,55,224 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2020-21 में ₹3,36,371 करोड़ थी। त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो खंड में भी वॉल्यूम बढ़े और कुल मुद्रा बाजार के वॉल्यूम (कॉल/ त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो) का क्रमशः 74 प्रतिशत और 24 प्रतिशत हो गए जो कि वर्ष 2020-21 में क्रमशः 69 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थे। मांग मुद्रा खंड में, वर्ष के दौरान औसत दैनिक वॉल्यूम 18 प्रतिशत घटकर ₹9,060 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2020-21 में ₹10,993 करोड़ था, यह पिछले वर्ष के 3 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी से घटकर 2 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.4.2)।

II.4.9 दीर्घकालिक मुद्रा बाजार लिखतों पर ब्याज दरें, अर्थात् 91-दिवसीय खजाना बिल (टी-बिल), जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) आमतौर पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अल्पकालिक (मांग, त्रिपक्षीय रेपो और मार्केट रेपो) दरों के साथ तालमेल में दिखती हैं। वर्ष के दौरान टी-बिल दरों पर सीडी दरों का औसत दैनिक प्रसार वर्ष 2020-21 में 16 बीपीएस से घटकर 9 बीपीएस हो गया (चार्ट II.4.3)। 91-

दिवसीय टी-बिल दरों पर 3 महीने के सीपी (एनबीएफसी) दरों का औसत दैनिक प्रसार वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान 16 बीपीएस से बढ़कर वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 56 बीपीएस हो गया। प्राथमिक सीपी बाजार में भारत औसत छूट दरें, जो सितंबर 2021 के मध्य में कम होकर 3.51 प्रतिशत हो गई थीं, बाद में, मार्च 2022 के अंत में लगभग 96 बीपीएस से

चार्ट II.4.3: 91 दिवसीय टी-बिल की तुलना में 3-महीने की सीपी और सीडी दर का स्प्रेड



बढ़कर 4.47 प्रतिशत तक पहुंच गईं। दरों का दृढ़ीकरण, रिजर्व बैंक द्वारा परिवर्ती दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) संचालन और एनबीएफसी कंपनियों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) की सदस्यता लेने के लिए सीपी के माध्यम से लिए गए उधार द्वारा चलनिधि अवशोषण में वृद्धि के कारण हुआ। 3 महीने की सीपी (एनबीएफसी) दर सितंबर 2021 के अंत में 3.48 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2022 के अंत में 4.25 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान 3 महीने की सीपी (गेर-एनबीएफसी) दर 3.48 प्रतिशत से बढ़कर 4.08 प्रतिशत हो गई।

II.4.10 प्राथमिक बाजार में, नई सीडी का निर्गमन वर्ष 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹2.33 लाख करोड़ हो गया, जो वर्ष 2020-21 में ₹1.31 लाख करोड़ था। प्राथमिक बाजार में सीपी का नया निर्गमन वर्ष 2021-22 में बढ़कर ₹20.19 लाख करोड़ हो गया, जो वर्ष 2020-21 में ₹17.41 लाख करोड़ था।

3. सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार

II.4.11 वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान, मौद्रिक नीति के उदार रुख, जी-एसएपी 1.0 के तहत परिचालन और विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) की प्रतिक्रिया स्वरूप बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में नरमी आई। जीएसटी मुआवजा उपकर की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सरकारी उधारी की आशंका और मई 2021 के लिए उम्मीद से अधिक सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट ने बाजार के रुख को क्षणिक मंदी प्रदान की। समग्र रूप से, तिमाही के दौरान 10 साल की जेनेरिक सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल 12 बीपीएस की गिरावट के साथ 6.05 प्रतिशत पर बंद हुआ, जो 5.96-6.19 प्रतिशत (इंट्रा-डे आधार पर) के दायरे में था।

II.4.12 वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान, 10 साल का जेनेरिक प्रतिफल 17 बीपीएस बढ़कर 6.22 प्रतिशत पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, 6 अगस्त 2021 को वीआरआरआर परिचालनों की मात्रा में चरणबद्ध वृद्धि की

घोषणा और अगस्त 2021 की बैठक में एमपीसी के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के ऊर्ध्वगामी संशोधन ने अगस्त 2021 में प्रतिफल को 6.26 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। सितंबर 2021 की पहली छमाही में, हालांकि, पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह के फिर से शुरू होने, अप्रैल-जुलाई के लिए केंद्र सरकार के अपेक्षित राजकोषीय घाटे से कम और अगस्त 2021 के लिए एक नरम सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट के साथ प्रतिफल में नरमी आई। सितंबर 2021 के अंतिम दिनों में, जी-एसएपी 2.0 के साथ अल्पकालिक प्रतिभूतियों की ओएमओ बिक्री की घोषणा, वीआरआरआर नीलामियों में उच्च कट-ऑफ, अन्य केंद्रीय बैंकों से तेजी के संकेत और कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि ने प्रतिफल पर दबाव बढ़ाने में योगदान दिया।

II.4.13 अक्टूबर 2021 के दौरान अमेरिकी राजकोषीय प्रतिफल और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और जी-एसएपी नीलामी में ठहराव के साथ सहानुभूति में 10 साल का प्रतिफल बढ़ गया। साप्ताहिक प्राथमिक नीलामी और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच, दिसंबर 2021 में 10 साल का प्रतिफल और बढ़ गया तथा 31 दिसंबर 2021 को 6.45 प्रतिशत पर बंद हुआ। कुल मिलाकर, 10-वर्षीय जेनेरिक सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में 23 बीपीएस तक बढ़ गया।

II.4.14 अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याशित समग्र उधारी से अधिक उधारी के मद्देनजर, वर्ष 2021-22 चौथी तिमाही में 10-वर्षीय सामान्य सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल में वृद्धि हो गई। भू-राजनीतिक संघर्ष के बढ़ने के बाद पण्य कीमतों में तेजी के बीच मार्च में प्रतिफल बढ़ा हुआ रहा। 31 मार्च 2022 को 10 वर्षीय सामान्य सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल 6.84 प्रतिशत पर बंद हुआ (चार्ट II.4.4)। कुल मिलाकर, 10 साल का प्रतिफल 67 बीपीएस से बढ़ गया, जिसमें साल के दौरान सॉवरेन यील्ड कर्व ऊपर की ओर बढ़ रहा था और सपाट हो गया था।



II.4.15 01 अप्रैल 2020 से पूर्णतया सुलभ मार्ग (एफएआर)²⁵ की शुरुआत के साथ, एफपीआई के पास सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए तीन मार्ग हैं, अर्थात् मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) के तहत निर्धारित निवेश सीमा के साथ सामान्य मार्ग, स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (वीआरआर) और एफएआर। वर्ष 2021-22 के लिए एमटीएफ के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश की सीमा ₹3,75,596 करोड़ निर्धारित की गई थी। एफएआर योजना के तहत शामिल प्रतिभूतियों की संख्या 12 प्रतिभूतियों (1 अप्रैल 2021 को ₹11,79,423 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) से बढ़कर 17 प्रतिभूतियों (31 मार्च 2022 तक ₹17,58,043 करोड़ के बकाया स्टॉक के साथ) तक हो गई। वर्ष 2021-22 के दौरान, एफपीआई ने सामान्य मार्ग के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹15,048 करोड़ की निवल बिक्री दर्ज की। हालांकि, एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान एफएआर रुट के तहत ₹13,275 करोड़ का निवेश किया। एफपीआई ने वीआरआर के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹4,370 करोड़ का भी निवेश किया, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट बॉन्ड

के लिए ₹1,50,000 करोड़ की संयुक्त निवेश सीमा है (1 अप्रैल 2022 से लागू ₹2,50,000 करोड़ तक की वृद्धि)। एफपीआई ने इसी अवधि के दौरान राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के ₹30 करोड़ की शुद्ध राशि खरीदी और कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान एमटीएफ, एफएआर और वीआरआर खंडों में सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल में ₹ 2,627 करोड़ का निवेश किया।

4. कॉर्पोरेट ऋण बाजार

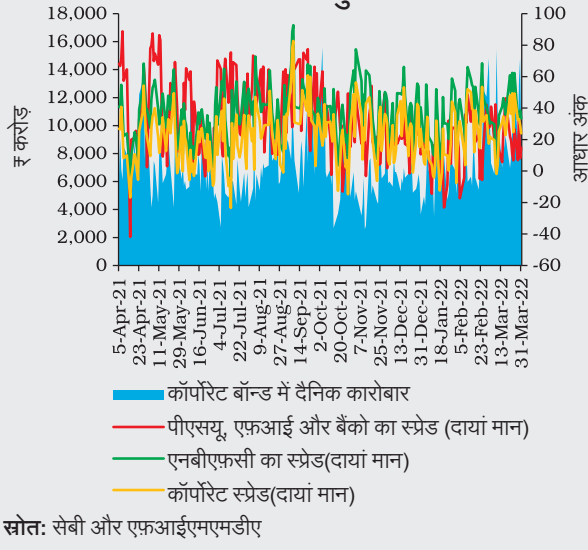
II.4.16 क्रेडिट स्प्रेड में संकुचन साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में वित्तीय स्थिति निभावकारी रही। वर्ष 2021-22 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थानों (एफआई) और बैंकों, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट पेपर के एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल क्रमशः 3 बीपीएस, 29 बीपीएस और 32 बीपीएस तक बढ़ गया। मार्च 2022 में एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉन्ड पर औसत उपज पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 5.84 प्रतिशत, एनबीएफसी के लिए 5.98 प्रतिशत और कॉर्पोरेट्स के लिए 5.88 प्रतिशत थी।

II.4.17 वर्ष 2021-22 के दौरान, मासिक औसत जोखिम प्रीमियम या एए-रेटेड 3-वर्षीय बांड (3-वर्ष जी-सेक से अधिक) पर 60 बीपीएस से घटकर पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 23 बीपीएस, एनबीएफसी के लिए 48 बीपीएस से 37 बीपीएस और कॉर्पोरेट्स के लिए 35 बीपीएस से 26 बीपीएस हो गया। स्प्रेड का संकुचन सभी रेटिंग सेगमेंट में दिखाई दिया। वर्ष 2021-22 के दौरान औसत दैनिक कारोबार पिछले वर्ष के ₹7,675 करोड़ से घटकर ₹7,358 करोड़ हो गया (चार्ट II.4.5)।

II.4.18 वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में प्राथमिक कॉर्पोरेट बांड निर्गमों में कमी देखी गई, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई। कुल मिलाकर, प्राथमिक कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गमन वर्ष 2021-22 के दौरान 23.4 प्रतिशत घटकर ₹6 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹7.8 लाख करोड़ था। निजी प्लेसमेंट

²⁵ एफएआर के तहत, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ श्रेणियों को घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के साथ, बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया।

चार्ट II.4.5: कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में एए-रेटेड 3-वर्षीय प्रतिफल स्प्रेड और कुल कारोबार



कॉर्पोरेट्स के लिए पसंदीदा विकल्प बना रहा, जो बॉण्ड बाजार के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों का 98.1 प्रतिशत होता है। बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड 11.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹40.2 लाख करोड़ हो गए, यानी मार्च 2022 के अंत में जीडीपी का 17.0 प्रतिशत। कॉर्पोरेट बॉण्ड में एफपीआई द्वारा निवेश मार्च 2021 के अंत के ₹1.3 लाख करोड़ से घटकर

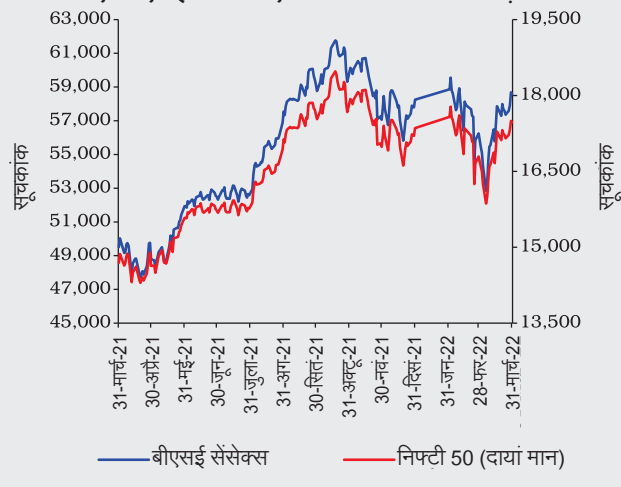
मार्च 2022 के अंत में ₹1.2 लाख करोड़ हो गया। परिणामस्वरूप, अनुमोदित सीमा का एफपीआई द्वारा उपयोग मार्च 2022 के अंत में घटकर 19.9 प्रतिशत रह गया, जो मार्च 2021 के अंत में 24.5 प्रतिशत था।

5. इक्विटी बाजार

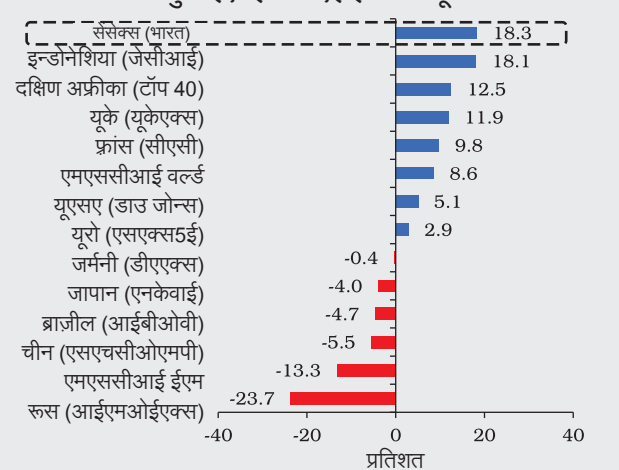
II.4.19 वर्ष 2020-21 में आई भारी तेजी के रुख को जारी रखते हुए, वर्ष 2021-22 में भारतीय इक्विटी बाजारों में तेजड़ियों का दबदबा बना रहा। हालांकि, ईई में नीति सामान्यीकरण से जुड़ी चिंताओं, प्रणालीगत ईएमई में देश विशिष्ट कारकों, ओमिक्रॉन के प्रसार और भू-राजनीतिक तनावों पर चिंताओं के बीच वैश्विक संकेतों पर बाजार का रुख अस्थिर रहा। फिर भी, 31 मार्च 2022 को बीएसई सेंसेक्स 18.3 प्रतिशत बढ़कर 58,569 पर बंद हुआ, जिसने कई वैश्विक समकक्षों को पीछे छोड़ दिया, जबकि निफ्टी-50 18.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 17,465 पर बंद हुआ (चार्ट II.4.6 ए और बी)। वर्ष 2021-22 में, बीएसई सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 29.2 प्रतिशत से बढ़कर 264.1 लाख करोड़ रुपये हो गया। फरवरी 2022 में 32 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, भारत VIX, जो निफ्टी-50 के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, मार्च 2021 के अंत में गिरकर फिर से 20.6 प्रतिशत के स्तर पर वापस आ गया।

चार्ट II.4.6: इक्विटी बाजार

ए. बीएसई सेंसेक्स एवं निफ्टी 50 में उतार चढ़ाव



बी. 222-102 में प्रमुख ईएमई और ईई इक्विटी सूचकांकों पर रिटर्न



11.4.20 कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि, एफपीआई द्वारा कम दाम पर बिक्री, विनिर्माण पीएमआई में 7 महीने के निचले स्तर तक गिरावट और देश के कुछ भागों में फिर से लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के कारण इक्विटी बाजारों ने मामूली नुकसान के साथ वर्ष की शुरुआत की। हालांकि, वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में मजबूत कॉर्पोरेट अर्जन और तेजी से वैक्सीन रोल-आउट तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के बीच वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों ने तिमाही के अंत में निवेशकों के रुख को तेजी की ओर प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि बढ़ाने के उपायों की एक श्रृंखला और कॉर्पोरेट परिणामों को उत्साहित करने की घोषणाओं के साथ मई 2021 में बाजार में फिर से तेजी आई। घरेलू इक्विटी में तेजी के साथ, बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अपने इतिहास में पहली बार 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।

11.4.21 जून 2021 के दौरान अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे पुनः खुलने और व्यावसायिक गतिविधि में तेजी आने के साथ सेंसेक्स नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मुद्रास्फीति पर चिंताओं और प्रणालीगत केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन के लिए आसन्न टेपरिंग से बाजार का रुख प्रभावित हुआ। जुलाई 2021 में तेज अस्थिरता के साथ, विभिन्न देशों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर चिंताओं पर नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बाद बाजार में महीने के अंत में नुकसान बढ़ गया। एफपीआई द्वारा निरंतर बिक्री ने भी घरेलू इक्विटी पर दबाव डाला। इक्विटी बाजार तेजी ने अगस्त 2021 में वापसी की और बेंचमार्क सूचकांकों को रिकॉर्ड ऊंचाई पर धकेल दिया तथा इसे ऑटोमोबाइल बिक्री में सुधार, मजबूत जीएसटी संग्रह, वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में आए मजबूत कॉर्पोरेट अर्जन परिणाम, नरम सीपीआई मुद्रास्फीति प्रिंट और जुलाई में भारत के विनिर्माण पीएमआई में 55.3 तक विस्तार द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ।

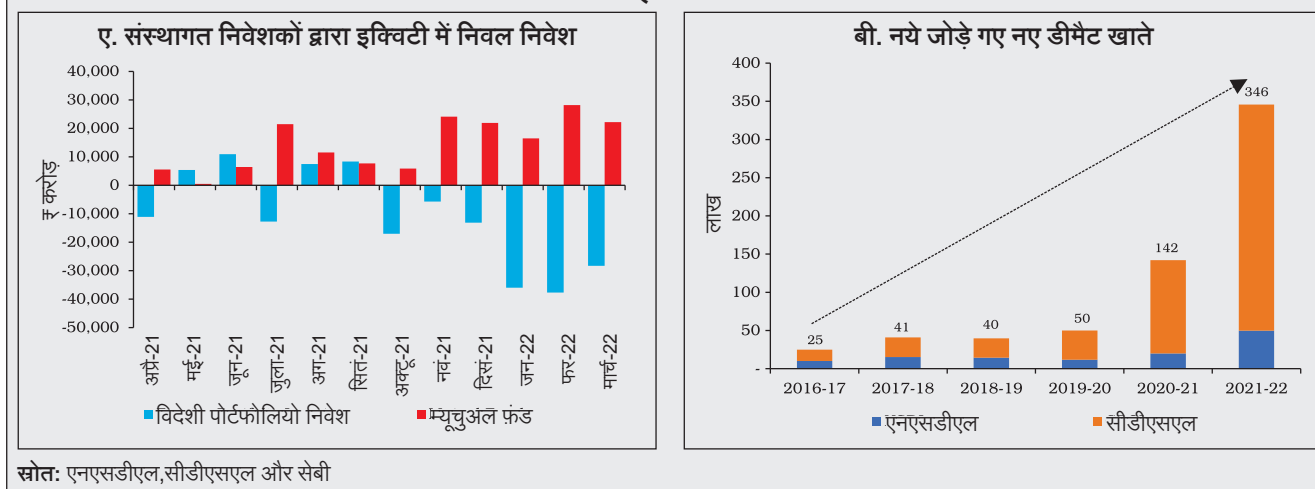
11.4.22 वैश्विक इक्विटी में कम दाम में बिक्री के बावजूद, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादन-सहबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के विस्तार की घोषणाओं से उत्साहित

घरेलू इक्विटी बाजार ने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना और दूरसंचार क्षेत्र के लिए किए गए राहत के उपायों से लाभ दर्ज किया। उसके बाद घरेलू इक्विटी बाजारों में भी, उनके वैश्विक समकक्षों की ही तरह, उतार-चढ़ाव के दौर देखने को मिले क्योंकि प्रणालीगत ईएमई और कॉर्पोरेट ऋण संकट में चल रहे नियामक कठोर नीतियों के संयोजन ने संभावित स्पिलओवर पर वैश्विक निवेशकों के बीच चिंता उत्पन्न की। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के संकेत, त्योहार के महीनों से पहले मजबूत मांग परिदृश्य और निरंतर उदार मौद्रिक नीति रुख से उत्साहित होकर अक्टूबर 2021 की पहली छमाही के दौरान बाजार नई ऊंचाई पर चढ़ गया। हालांकि, वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के मिश्रित कॉर्पोरेट अर्जन परिणामों और विस्तारित मूल्यांकन पर चिंताओं के बाद दूसरी छमाही में, त्वरित मुनाफा वसूली के कारण उछाल क्षणिक साबित हुआ।

11.4.23 नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में यूएस फेड द्वारा की गई गिरावट की घोषणाओं से घरेलू इक्विटी बाजार अप्रभावित रहा। हालांकि, इस सकारात्मक शुरुआत के बावजूद, इक्विटी क्षेत्र ने महीने के अंत में तेज गिरावट दर्ज की, जिसे ओमिक्रॉन के पता चलने से जुड़ी रिपोर्टों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा प्रतिबंधों के नए दौर के लागू होने से उत्प्रेरण मिला। दिसंबर 2021 की पहली छमाही में गिरावट का यह दौर गहरा गया क्योंकि एफपीआई ने भारतीय इक्विटी को ऑफलोड करना जारी रखा और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक सख्ती आसन्न लगने लगी थी। हालांकि, मजबूत जीएसटी संग्रह, नवंबर के लिए विनिर्माण पीएमआई में विस्तार और मौद्रिक नीति निर्धारण में रिज़र्व बैंक की यथास्थिति ने बाजार को राहत प्रदान की।

11.4.24 बढ़ी हुई अस्थिरता के बीच, घरेलू इक्विटी में बिकवाली जनवरी 2022 में मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ फेड द्वारा प्रारंभिक ब्याज दर में वृद्धि के संकेत ने निवेशकों के उत्साह को कम कर दिया। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद,

चार्ट II.4.7: इक्विटी में निवेश



भारतीय इक्विटी बाजार ने फरवरी 2022 में बजट घोषणाओं और रिजर्व बैंक की उदार मौद्रिक नीति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि, बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि ने निवेशकों के उत्साह पर भारी असर डाला। यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद महीने की दूसरी छमाही में घरेलू शेयरों में तेज बिकवाली देखी गई। मार्च में राज्य विधानसभाओं के चुनावी परिणामों और सकारात्मक वैश्विक संकेतों की घोषणाओं के बाद उत्साह में कुछ सुधार हुआ, लेकिन रूस-यूक्रेन शांति वार्ता, कमोडिटी की कीमतों में अस्थिरता और चीन में नए सिरे से लॉकडाउन को लेकर चिंता बनी रही।

II.4.25 पिछले वर्ष में 2.8 लाख करोड़ के निवल अंतर्वाह की तुलना में 1.3 लाख करोड़ के निवल बहिर्गमन के साथ एफपीआई वर्ष 2021-22 में 12 महीनों में से आठ महीनों तक निवल विक्रेता बने रहे। दूसरी ओर, म्यूचुअल फंड ने वर्ष 2021-22 में भारतीय इक्विटी बाजार में ₹1.7 लाख करोड़ का भारी निवेश किया (चार्ट II.4.7.ए)।

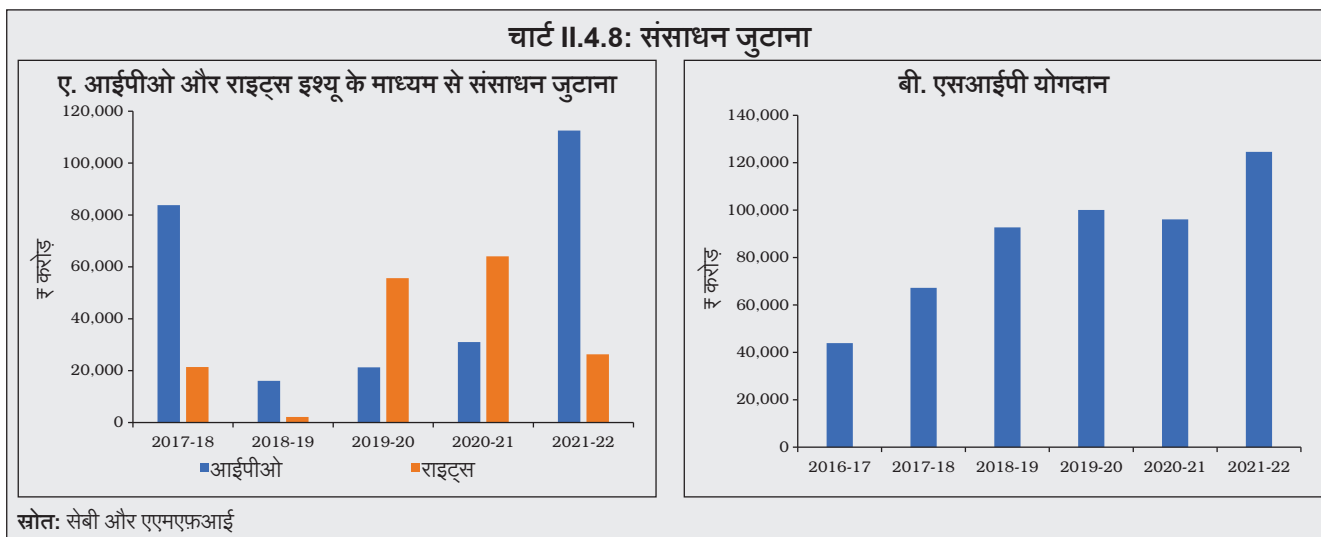
II.4.26 इक्विटी में खुदरा निवेशकों की प्रत्यक्ष सहभागिता में वृद्धि जारी रही, वर्ष 2021-22 के दौरान 3.46 करोड़ डीमैट खाते खोले गए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1.42 करोड़ डीमैट खाते खोले गए थे (चार्ट II.4.7.बी)। वर्ष 2021-22 के दौरान हर

महीने औसतन 28.8 लाख डीमैट खाते खोले गए, जो पिछले साल के 11.8 लाख प्रति माह और वर्ष 2019-20 के प्रति माह 4.2 लाख डीमैट खातों से अधिक है।

प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाना

II.4.27 इक्विटी बाजार के प्राथमिक खंड में, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (आईपीओ), अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्तावों (एफपीओ) और अधिकार निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन पिछले वर्ष के ₹1.1 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 26.1 प्रतिशत से बढ़कर ₹1.39 लाख करोड़ हो गए। (चार्ट II.4.8.ए और परिशिष्ट सारणी 5)। 121 आईपीओ / एफपीओ निर्गमों के माध्यम से ₹ 1.13 लाख करोड़ जुटाए गए, जिनमें से ₹958 करोड़ की राशि के 70 निर्गमों को बीएसई और एनएसई के छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया गया। पिछले वर्ष के दौरान ₹64,059 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राइट्स निर्गमों के माध्यम से जुटाए गए संसाधन घटकर ₹26,327 करोड़ रह गए। वर्ष 2021-22 के दौरान अधिमानी आबंटन और अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से संसाधन जुटाना घटकर ₹ 92,135 करोड़ हो गए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 1,19,678 करोड़ थी।

चार्ट II.4.8: संसाधन जुटाना



II.4.28 वर्ष 2021-22 के दौरान ₹2.5 लाख करोड़ की कीमत के म्यूच्युअल फंड द्वारा जुटाए गए निवल संसाधनों में से, सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) के योगदान में सकारात्मक वृद्धि देखी गई- जो कि बढ़ती खुदरा भागीदारी और घरेलू बचत के वित्तीयकरण का संकेत देती है (चार्ट II.4.8.बी)। पिछले वर्ष के ₹39,327 करोड़ के निवल मोचन के मुकाबले वर्ष 2021-22 में इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में ₹1,54,094 करोड़ के निवल संसाधन जुटाए गए। इक्विटी-उन्मुख म्यूच्युअल फंड की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2022 के अंत में 37.2 प्रतिशत बढ़कर ₹ 13.7 लाख करोड़ हो गईं, जो मार्च 2021 के अंत में ₹10 लाख करोड़ थीं।

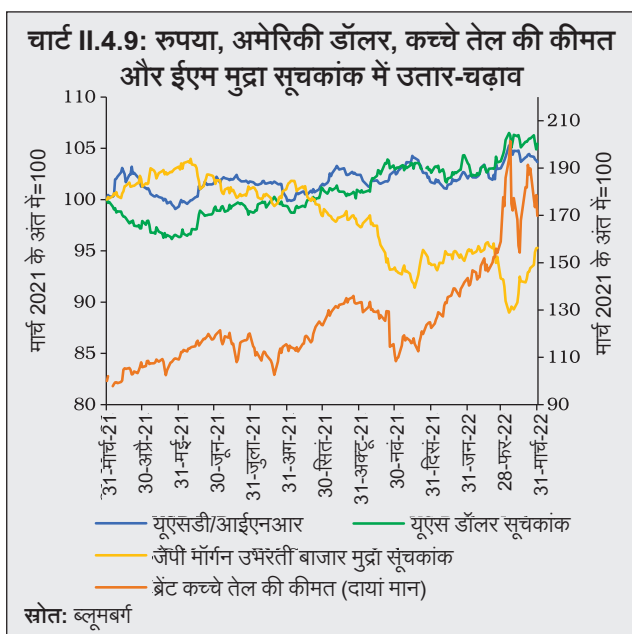
6. विदेशी मुद्रा बाजार

II.4.29 विदेशी मुद्रा बाजार में, पिछले वर्ष की तुलना में अंतर-बैंक और व्यापारी दोनों संविभागों में कारोबार में तेजी आई।

II.4.30 वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान कोविड-19 संक्रमण में भारी वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में निरंतर तेजी के बीच भारतीय रुपया 1.64 प्रतिशत कमजोर हुआ। तिमाही के दौरान कमजोर डॉलर और चालू खाता अधिशेष 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ने रुपये के लिए गिरावट को कम किया। टीकाकरण की गति में तेजी और भारतीय कॉरपोरेट्स द्वारा आईपीओ में मजबूत विदेशी प्रवाह ने भारतीय रुपये को वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में अधिकांश एशियाई समकक्षों से

बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली सुधार और उदीयमान बाजार मुद्राओं में आई थोड़े समय की तेजी से रुपये को भी समर्थन मिला।

I.4.31 भारतीय रुपया फिर से वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के दौरान दबाव में आ गया क्योंकि अमेरिकी डॉलर की कीमतों में वृद्धि हुई, यूएस अल्पावधि प्रतिफल में तेजी दर्ज की गयी, क्योंकि व्यापारियों ने सख्त एफओएमसी स्टेटमेंट्स (वर्ष 2022 के लिए तेज टेपर और दर वृद्धि निर्धारण) का लाभ उठाया। तिमाही के दौरान, सभी ईएमई मुद्राओं पर दबाव बढ़ गया। भारतीय रुपया 16 दिसंबर, 2021 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अंतर दिवसीय व्यापार में ₹76.32 प्रति अमेरिकी डॉलर के निचले स्तर को छू गया क्योंकि बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व टेपर की तेजी के लिए तैयार थे और अमेरिका तथा बाकी एई के बीच नीतिगत विचलन के लिए तैयार थे। दिसंबर 2021 के उत्तरार्ध में डॉलर में कमजोरी दर्ज की गयी तथा रुपया तेजी से ठीक हुआ और 31 दिसंबर, 2021 को ₹74.33 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ, जो वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही की तुलना में 0.13 प्रतिशत कमजोर हो गया। वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में रुपये पर दबाव बना रहा क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में वृद्धि की प्रत्याशा से अमेरिकी प्रतिफल में वृद्धि दर्ज की गयी, साथ ही बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण सुरक्षित निवेश स्थल की मांग के बीच अमेरिकी



डॉलर सूचकांक 100 के निशान की ओर बढ़ गया। तिमाही के दौरान घरेलू इक्विटी बाजारों से एफपीआई के बहिर्वाह और पण्यों की कीमतों में व्यापक आधार पर तेजी का असर भी रुपये पर पड़ा। नतीजतन, भारतीय रुपया 7 मार्च, 2022 को अंतर दिवसीय व्यापार में 76.98 प्रति अमेरिकी डॉलर के नए न्यूनतम स्तर को छू गया, अधिकांश ईएमई मुद्राएं इस तिमाही के दौरान दबाव में रहीं। कुल मिलाकर, भारतीय रुपया वर्ष 2021-22 में 3.53 प्रतिशत के शुद्ध मूल्यहास के साथ 31 मार्च, 2022 को ₹75.79 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ (चार्ट II.4.9)।

II.4.32 औसत आधार पर, वर्ष 2021-22 (वर्ष-दर-वर्ष) में 40-मुद्रा सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, इस अवधि के दौरान 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उच्च घरेलू मुद्रास्फीति को दर्शाती है।

II.4.33 वर्ष 2021-22 के दौरान दीर्घकालिक फॉरवर्ड प्रीमियम नियंत्रित बने रहे। जहां वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही

के दौरान आईपीओ से संबंधित रुपये की मांग जैसे कारकों के कारण अल्पकालिक फॉरवर्ड प्रीमियम में कुछ गिरावट देखी गई, वहीं बाद की तिमाहियों में वे प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति बेहतर हो जाने से उनमें स्थिरता आई।

7. निष्कर्ष

II.4.34 कुल मिलाकर, वित्तीय बाजार, आगे चलकर, काफी अनिश्चितता और कड़ी वैश्विक वित्तीय स्थितियों का सामना करेंगे। वैश्विक प्रभाव विसरण के जोखिम के कारण, संवृद्धि संबंधी चिंताओं के बीच मुद्रास्फीति से जुड़ी आशंकाओं ने उदीयमान बाजार की मुद्राओं के जोखिमों को बढ़ा दिया है।

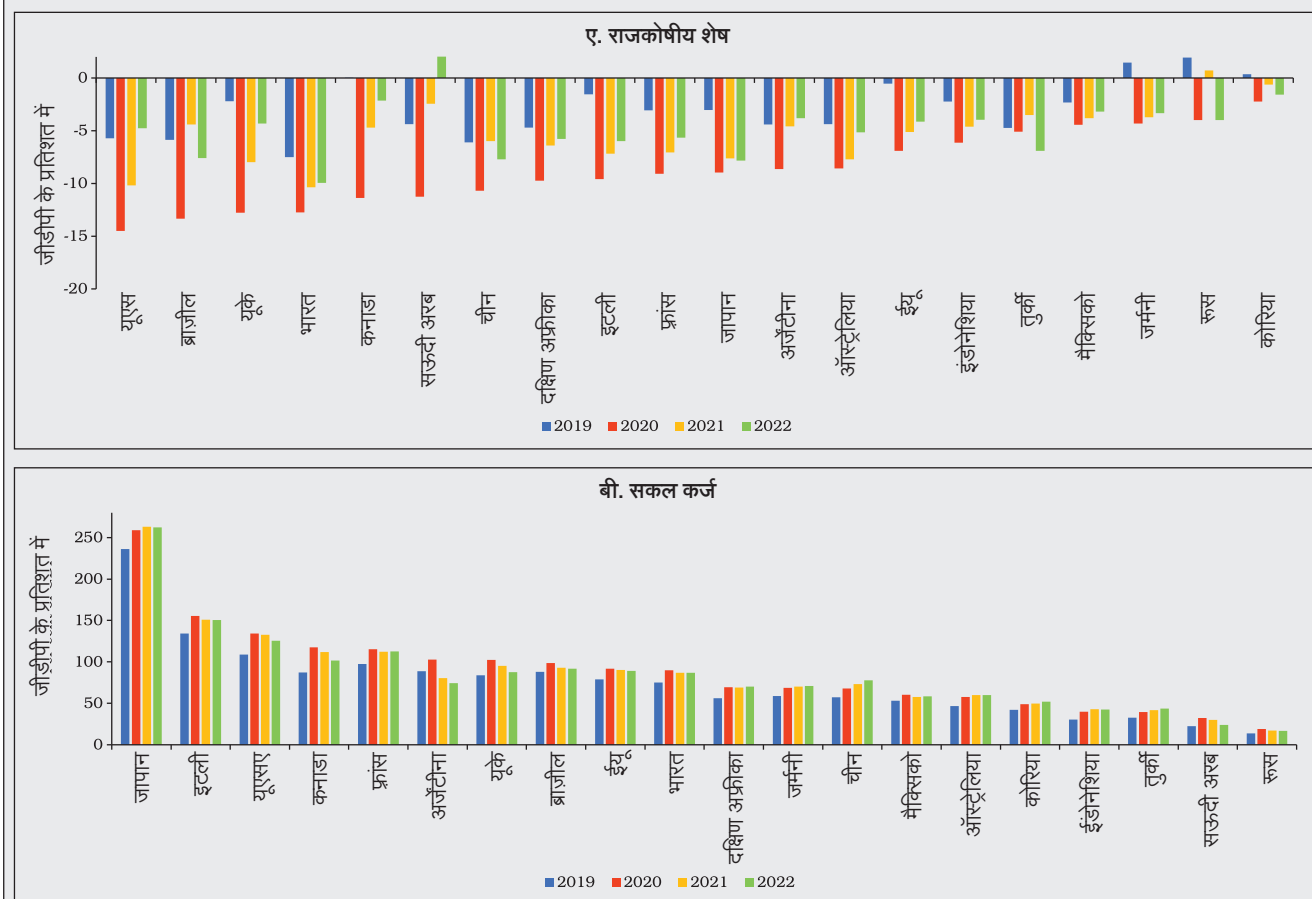
II.5 सरकारी वित्त

II.5.1 वर्ष 2022 में, अधिकांश जी-20 देशों में राजकोषीय घाटा कम रहने का अनुमान है, लेकिन यह मोटे तौर पर महामारी-पूर्व के स्तर से ऊपर रहेगा (चार्ट II.5.1ए)। यद्यपि अनुमानित राजकोषीय समायोजन योजनाओं से मध्यम अवधि में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में लोक ऋण-जीडीपी अनुपात कम होने की उम्मीद है, तथापि उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के लिए औसत सरकारी कर्ज-जीडीपी अनुपात, जो मुख्य रूप से चीन द्वारा संचालित हो रहा है, वृद्धिशील बना हुआ है।²⁶ वर्ष 2022 में भारत का सकल ऋण नियंत्रित दायरे में बने रहने अनुमान है, लेकिन यह समकक्ष ईएमई (ब्राजील को छोड़कर) से अधिक रहेगा [चार्ट II.5.1बी]।

II.5.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 और 3 क्रमशः 2021-22 और 2022-23 में केंद्र सरकार के वित्त की स्थिति प्रस्तुत करते हैं। उप-खंड 4 और 5, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान राज्य सरकार के वित्त में विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। सामान्य सरकारी वित्त पर उप-खंड 6 में चर्चा की गई है। अंतिम खंड समापन टिप्पणियों और कुछ नीतिगत दृष्टिकोणों को निर्धारित करता है।

²⁶ आईएमएफ (2022), फिस्कल मॉनिटर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वॉशिंगटन डी.सी., अप्रैल

चार्ट II.5.1: जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय शेष और सकल कर्ज



यूएसए: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका

यूके: यूनाइटेड किंगडम

ईयू: यूरोपियन यूनियन

टिप्पणी: अन्य देशों के साथ तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के लिए भारत का डेटा विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ), आईएमएफ से प्राप्त किया गया है। तथापि, यह केन्द्रीय बजट संबंधी दस्तावेजों या रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से भिन्न हो सकता है क्योंकि भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन पद्धतियों और परंपराओं में भिन्नता है।

स्रोत: वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अप्रैल 2022।

2. वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति

II.5.3 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर, सरकार ने वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान ₹6.3 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने के उपाय, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार, कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए

ऋण गारंटी योजना, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान और राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के माध्यम से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देना जैसे उपाय शामिल हैं। इन उपायों के अनुपूरक के तौर पर वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए आबंटन में वृद्धि जैसे अतिरिक्त व्यय किए गए, जैसा कि अनुदान की अनुपूरक मांग (एसडीजी) में उल्लिखित है²⁷ परिणामस्वरूप, कुल व्यय ने बजट अनुमानों में (राजस्व व्यय के तहत ₹2.4 लाख करोड़ और

²⁷ एसडीजी के पहले और दूसरे बैच के आधार पर बजट अनुमानों की तुलना में प्रस्तावित वृद्धि ₹3,22,918 करोड़ थी। अनुदान के लिए तीसरी और आखिरी अनुपूरक मांग (14 मार्च 2022 को घोषित) में वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों (आरई) के अलावा ₹1.07 लाख करोड़ का अतिरिक्त शुद्ध नकद व्यय शामिल है।

पूँजीगत व्यय के तहत ₹48,475 करोड़ के विचलन के साथ) ₹2.9 लाख करोड़ की वृद्धि हो गई। हालांकि, अतिरिक्त खर्च की भरपाई उच्च कर और गैर-कर राजस्व से की गई, जिससे सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) में 0.03 प्रतिशत बिन्दुओं की कमी आई जिसके बजट में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान (बीई) व्यक्त किया गया था।²⁸

11.5.4 सकल कर राजस्व में वर्ष 2021-22 आरई (वर्ष 2019-20 के दौरान 25.2 प्रतिशत) में 24.1 प्रतिशत की वर्ष-

सारणी 11.5.1: कर में उछाल

	औसत कर उछाल (2010-11 से 2018-19 तक)	2021-22 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5
1. सकल कर राजस्व	1.11	1.33	1.24	1.05
2. प्रत्यक्ष कर	1.03	1.79	1.66	1.49
(i) कोर्पोरेशन कर	0.92	1.80	2.00	1.47
(ii) आय कर	1.27	1.81	1.37	1.57
3. अप्रत्यक्ष कर	1.25	0.91	0.88	0.62
(i) जीएसटी	-	1.78	1.19	1.71
(ii) सीमा शुल्क	0.31	1.71	2.07	1.39
(iii) उत्पाद शुल्क	0.91	-0.57	0.03	-1.64

जीएसटी: वस्तु एवं सेवा कर - : उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: कर उछाल को सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। 2021-22 (आरई) की गणनाएं 2020-21 (आरई) के आधार पर की गयी हैं।

स्रोत: विभिन्न वर्षों के यूनियन बजट दस्तावेजों पर आधारित आरबीआई स्टाफ गणनाएं

दर-वर्ष वृद्धि के साथ, महामारी की स्थिति में भी कर राजस्व में उछाल रहा (सारणी 11.5.1)। रिजर्व बैंक द्वारा बजट से अधिक अधिशेष हस्तांतरण द्वारा सहायता प्राप्त कर, गैर-कर राजस्व भी बजट अनुमान से ₹70,763 करोड़ अधिक हो गया। हालांकि, विनिवेश प्राप्ति बीई से ₹97,000 करोड़ कम हो गईं।

3. वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के वित्त

11.5.5 वर्ष 2022-23 के लिए, संघीय बजट ने वृद्धि में तेजी लाने और चल रही आर्थिक बहाली को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए पूँजीगत व्यय पर ध्यान देने के साथ राजकोषीय विवेक को संतुलित करने की इच्छा प्रकट की है। जीएफडी का बजट सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है²⁹, जो कि वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे जीएफडी प्राप्त करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2021-22 (आरई) से 29 आधार अंकों की कमी लाई जानी है।³⁰ इस गिरावट को हासिल करने के लिए राजस्व व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 12.4 प्रतिशत तक सीमित करने की योजना है, क्योंकि पूँजीगत व्यय का सकल घरेलू उत्पाद के 2.9 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर तक बढ़ने का अनुमान है और प्राप्ति के अधिक न रहने की आशंका है (सारणी 11.5.2)।

11.5.6 पूँजीगत व्यय के तहत, प्रधान मंत्री गति शक्ति³¹ से संबंधित पूँजी निवेश के लिए उपयोग किए जाने वाले 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹1 लाख करोड़ के प्रावधान, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और

²⁸ बजट 2021-22 ने वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी को ₹2,22,87,379 करोड़ (जीएफडी-जीडीपी अनुपात 6.76 प्रतिशत) रखा था। इसका पहले अग्रिम अनुमानों और संघीय बजट 2022-23 में 2,32,14,703 करोड़ रुपये में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार जीएफडी-जीडीपी अनुपात 6.85 प्रतिशत था। दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) [28 फरवरी 2022 को जारी] के अनुसार, 2021-22 के लिए सांकेतिक जीडीपी बढ़कर ₹ 2,36,43,875 करोड़ है, जिसका अर्थ है कि जीएफडी-जीडीपी अनुपात 6.73 प्रतिशत है। किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध जीडीपी आंकड़े का उपयोग करने के सिद्धांत के अनुसार, वर्ष 2021-22 (आरई) के लिए सांकेतिक जीडीपी एसएई के अनुसार है। इस परिप्रेक्ष्य में, इस खंड में दिए गए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय संकेतक, संघीय बजट दस्तावेजों में रिपोर्ट किए गए संकेतकों से भिन्न हो सकते हैं।

²⁹ वर्ष 2021-22 (आरई) के लिए अनुमानित सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद ₹2,32,14,703 करोड़ में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए वर्ष 2022-23 (बीई) के लिए ₹2,58,00,000 करोड़ के सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया गया है।

³⁰ संघीय बजट वर्ष 2021-22 ने वर्ष 2025-26 तक की अवधि में काफी स्थिर गिरावट के साथ जीएफडी को सांकेतिक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम करने की सरकार की मंशा की घोषणा की थी।

³¹ गति शक्ति - एक डिजिटल प्लेटफॉर्म - बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाएगा।

सारणी II.5.2: केंद्र सरकार का राजकोषीय कार्य निष्पादन

(जीडीपी की तुलना में प्रतिशत)

मद	2004-08	2008-10	2010-15	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. गैर कर्ज प्राप्तियाँ	11.0	9.7	9.5	9.2	9.1	9.4	9.1	8.8	8.7	8.5	8.9	9.2	8.9
II. सकल कर राजस्व (ए+बी)	10.7	10.4	10.2	10.0	10.6	11.1	11.2	11.0	10.0	10.2	9.9	10.6	10.7
a) प्रत्यक्ष कर	5.1	6.0	5.7	5.6	5.4	5.5	5.9	6.0	5.2	4.8	5.0	5.3	5.5
b) अप्रत्यक्ष कर	5.6	4.4	4.5	4.4	5.2	5.6	5.4	5.0	4.8	5.5	5.0	5.4	5.2
III. निवल कर राजस्व	7.9	7.6	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	7.0	6.8	7.2	6.9	7.5	7.5
IV. गैर कर राजस्व	2.2	1.8	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.2	1.6	1.0	1.1	1.3	1.0
V. गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियाँ	0.9	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3
VI. कुल व्यय	14.5	16.1	14.4	13.3	13.0	12.8	12.5	12.2	13.4	17.7	15.6	15.9	15.3
VII. राजस्व व्यय	12.1	14.4	12.6	11.8	11.2	11.0	11.0	10.6	11.7	15.6	13.1	13.4	12.4
VIII. पूंजीगत व्यय	2.4	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.5	1.6	1.7	2.2	2.5	2.5	2.9
IX. राजस्व घाटा	2.0	5.0	3.5	2.9	2.5	2.1	2.6	2.4	3.3	7.3	5.1	4.6	3.8
X. सकल राजकोषीय घाटा	3.5	6.3	4.9	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	4.7	9.2	6.8	6.7	6.4

बीई: बजट अनुमान आरई: संशोधित अनुमान

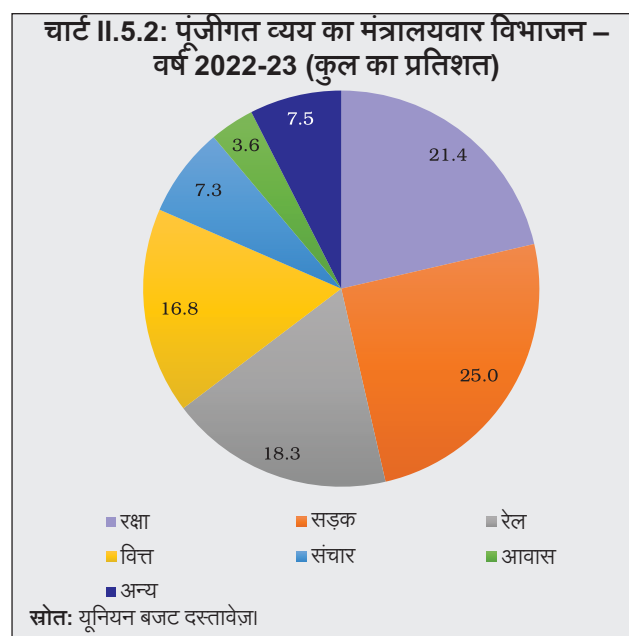
टिप्पणी: किसी भी वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध जीडीपी डेटा का उपयोग करने के सिद्धांत के अनुसार, 2021-22 (आरई) के लिए उपयोग की जाने वाली जीडीपी एसएई, 2021-22 के अनुसार है।

स्रोत: यूनियन बजट दस्तावेज़।

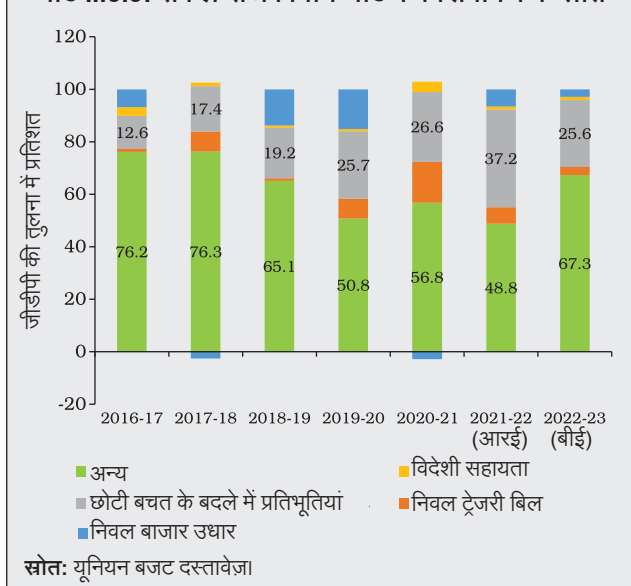
अन्य उत्पादक पूंजी निवेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पूरक वित्त पोषण के साथ राज्यों के ऋण और अग्रिमों को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। बुनियादी ढांचे के खर्च में भारी वृद्धि के बाद पूंजीगत परिव्यय, अर्थात्, पूंजीगत व्यय रहित ऋण और अग्रिम, को भी वर्ष 2022-23 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्ष 2021-22 (आरई) में 73.3 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा, बजट किया गया है। कुल पूंजीगत व्यय का लगभग दो-तिहाई (64.7 प्रतिशत) रक्षा; सड़क; और रेलवे मंत्रालयों द्वारा वहन किया जाना है (चार्ट II.5.2)। पूंजीगत परिव्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात (आरईसीओ) में लगातार दूसरे वर्ष सुधार के लिए दशकीय औसत 7.8 के सापेक्ष 5.2 करने का बजट किया गया है। प्राप्तियों की बात करें तो, राजस्व पूर्वानुमान रुढ़िवादी सांकेतिक जीडीपी अनुमानों पर आधारित है और विनिवेश लक्ष्य ₹65,000 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों में लगभग ₹66,000 करोड़ की औसत प्राप्ति के करीब है।

II.5.7 वर्ष 2022-23 के संघीय बजट प्रस्तावों में, लगभग 36.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्ष 2021-22 (आरई) में

चार्ट II.5.2: पूंजीगत व्यय का मंत्रालयवार विभाजन – वर्ष 2022-23 (कुल का प्रतिशत)



चार्ट II.5.3: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत



₹10.47 करोड़ के मुकाबले ₹14.31 लाख करोड़ (28 जनवरी 2022 को किए गए स्विच ऑपरेशन के लिए समायोजित) की

सकल बाजार उधारी शामिल है।³² महामारी-पूर्व प्रवृत्ति में वापसी को चिह्नित करते हुए, निवल बाजार उधार को वर्ष 2022-23 में जीएफडी के 67.3 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए बजट किया गया है, जो वर्ष 2021-22 (आरई) में 48.8 प्रतिशत से अधिक है, जिसमें ट्रेजरी बिल, छोटी बचत और और नकद शेष का दायित्व कम है (चार्ट II.5.3)। समग्र बाजार उधारी के एक हिस्से के रूप में, सरकार जलवायु परिवर्तन संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने का भी इरादा रखती है।

4. वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त

II.5.8 राज्य सरकार के वित्त में सुधार को वर्ष 2021-22 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात के साथ वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों में 4.7 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए बजट किया गया था (सारणी II.5.3 और परिशिष्ट सारणी 6)।

II.5.9 अप्रैल-फरवरी वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध 26 राज्यों के अनंतिम खातों (पीए)³³ के आंकड़ों से संकेत मिलता

सारणी II.5.3: राज्यों की राजकोषीय स्थिति

(₹ लाख करोड़)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)
1	2	3	4	5	6
I. राजस्व प्राप्तियाँ	23.2 (13.6)	26.2 (13.9)	26.7 (13.3)	27.9 (14.1)	34.5 (14.6)
II. पूंजी प्राप्तियाँ	0.4 (0.2)	0.4 (0.2)	0.6 (0.3)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
III. राजस्व व्यय	23.4 (13.7)	26.4 (14.0)	27.9 (13.9)	31.9 (16.1)	35.7 (15.1)
IV. पूंजीगत व्यय	4.3 (2.5)	4.9 (2.6)	4.6 (2.3)	5.5 (2.8)	7.2 (3.1)
ए. पूंजीगत परिव्यय	3.9 (2.3)	4.4 (2.3)	4.2 (2.1)	5.0 (2.5)	6.7 (2.8)
बी. राज्यों द्वारा ऋण और अग्रिम	0.4 (0.2)	0.5 (0.2)	0.4 (0.2)	0.5 (0.2)	0.5 (0.2)
V. राजकोषीय घाटा/अधिशेष	4.1 (2.4)	4.6 (2.4)	5.3 (2.6)	9.3 (4.7)	8.2 (3.5)
VI. राजस्व घाटा/अधिशेष	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1.2 (0.6)	3.9 (2.0)	1.2 (0.5)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हैं।
स्रोत: राज्य सरकारों और सीएजी के बजट दस्तावेज़।

³² केंद्र सरकार की बाजार उधारी में वर्ष 2021-22 (आरई) में ₹1,59,000 करोड़ की उधारी शामिल नहीं है, जो राज्यों को जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले बैंक-टू-बैंक आधार पर ऋण के रूप में दी गई।

³³ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की वेबसाइट।

है कि उनकी समेकित जीएफडी एक साल पहले की तुलना में 31.5 प्रतिशत कम थी, जिसका मुख्य कारण था राजस्व प्राप्ति में उच्च वृद्धि (वर्ष 2020-21 में 8.6 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में 30.5 प्रतिशत)। दिनांक 3 नवंबर 2021 को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी के केंद्र के कदम के बाद, अधिकांश राज्यों ने अपने मूल्य वर्धित कर (वैट) को पेट्रोल के लिए ₹1.8 से ₹10.0 प्रति लीटर और डीजल के लिए ₹2.0 से ₹7.0 प्रति लीटर की सीमा में घटा दिया। जीएसटी मुआवजे के एवज में केंद्रीय हस्तांतरण द्वारा सन्निहित राजस्व हानि अधिक थी - केंद्र ने राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण के रूप में वर्ष 2021-22 में ₹1.59 लाख करोड़ (15 जुलाई को ₹0.75 लाख करोड़; 7 अक्टूबर को 0.40 लाख करोड़ और 28 अक्टूबर को ₹0.44 लाख करोड़) जारी किए। इन ऋणों के अलावा, केंद्र ने 60,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया है। कर न्यागमन की नियमित किस्त के अलावा, केंद्र ने नवंबर 2021 और जनवरी 2022 में कर न्यागमन की दो अग्रिम किस्तें जारी कीं।

II.5.10 महामारी की दूसरी लहर और संबंधित राज्य-विशिष्ट प्रतिबंधों के बावजूद, पूंजी परिव्यय मजबूत रहा, जबकि उच्च राजस्व व्यय ने आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने में मदद की। पूंजीगत व्यय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में तेरह राज्यों को ₹32,412 करोड़ (वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही तक) की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति मिली। केंद्र द्वारा 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना' के तहत परिव्यय को वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान में ₹ 10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 15,000 करोड़ कर दिया गया है।

5. वर्ष 2022-23 में राज्य वित्त

II.5.11 20 राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार, उनके संयुक्त जीएफडी का बजट 2022-23 में उनके समेकित जीएसडीपी का 3.2 प्रतिशत पर रखा गया है, जो कि वर्ष 2021-22 (आरई) में 3.7 प्रतिशत था, हालांकि राज्यों के बीच काफी भिन्नता है। राज्यों की राजकोषीय स्थिति में समेकन को पूरी तरह से राजस्व खाते के लिए जिम्मेदार ठहराया जा

सारणी II.5.4: राज्य सरकार वित्त 2022-23*: प्रमुख संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

मद	2020-21	2021-22 (बीई)	2021-22 (आरई)	2022-23 (बीई)
1	2	3	4	5
राजस्व घाटा	2.0	0.7	1.1	0.6
सकल राजकोषीय घाटा	4.1	3.7	3.7	3.2
प्राथमिक घाटा	2.2	1.7	1.9	1.5

*: *डेटा बीस राज्यों से संबन्धित है जिन्होंने 2022-23 के लिए अपना अंतिम बजट प्रस्तुत किया है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़

सकता है क्योंकि राजस्व प्राप्ति में वृद्धि को राजस्व व्यय की तुलना में काफी अधिक स्तर पर बजट किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में 55 आधार अंकों का संकुचन हुआ है।

II.5.12 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र ने राज्यों को वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी है, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के सुधारों से बंधे होंगे। संघीय बजट वर्ष 2022-23 में, केंद्र ने कर न्यागमन को वर्ष 2021-22 के उच्च आधार के शीर्ष पर 9.6 प्रतिशत की वृद्धि का बजट दिया है। वर्ष 2022-23 के लिए, 15 वें वित्त आयोग का बजट अनुदान वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9 प्रतिशत कम है, जो कि मुख्य रूप से राज्यों के राजस्व घाटे में बढ़ोतरी के अनुमान से हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटे के अनुदान में कमी के कारण है। जैसा कि पहले कहा गया है, समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को सामान्य उधार के अलावा 50 साल के ब्याज मुक्त ऋणों में 1 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

6. सामान्य सरकारी वित्त

II.5.13 वर्ष 2021-22 के लिए उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, सामान्य सरकारी घाटा और ऋण कम होकर क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 9 प्रतिशत और 85 प्रतिशत तक हो गया है, जो वर्ष 2020-21 (आरई) में क्रमशः 13.3 प्रतिशत

और 89.4 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर पर थे (परिशिष्ट सारणी 7)।

7. निष्कर्ष

II.5.14 राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए, बजट ने अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से बाहर निकालने के लिए निवेश आधारित वृद्धि रणनीति पर भरोसा किया है। वर्ष 2022-23 में, व्यय की गुणवत्ता में सुधार करते हुए नये तुले राजकोषीय समेकन की परिकल्पना की गई है। भविष्य में, राजकोषीय और वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए और सार्वजनिक वित्त में विश्वसनीयता का निर्माण करते हुए, ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय समेकन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

II.6 बाह्य क्षेत्र

II.6.1 वर्ष के दौरान भारत का बाह्य क्षेत्र आघात-सह बना रहा। यद्यपि घरेलू आर्थिक सुधारों ने आयात मांग को बढ़ा दिया, कुल मिलाकर व्यापार के समक्ष उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों और सोने के सुरक्षित निवेश स्थल (सेफ हेवन) की मांग ने वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही में पण्य वस्तुओं के व्यापार घाटे को बढ़ाया। फिर भी, सेवाओं के मजबूत निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रभुत्व वाले मजबूत पूंजी प्रवाह ने चालू खाता शेष पर दबाव कम कर दिया, जो वर्ष के उत्तरार्ध में अधिशेष से घाटे में आ गया। बाहरी निधीयन की जरूरत सामान्य रहने के साथ, वर्ष के दौरान आरक्षित वृद्धि ने वैश्विक स्पिलओवर का सामना करने में आघात सहनीयता बनाई।

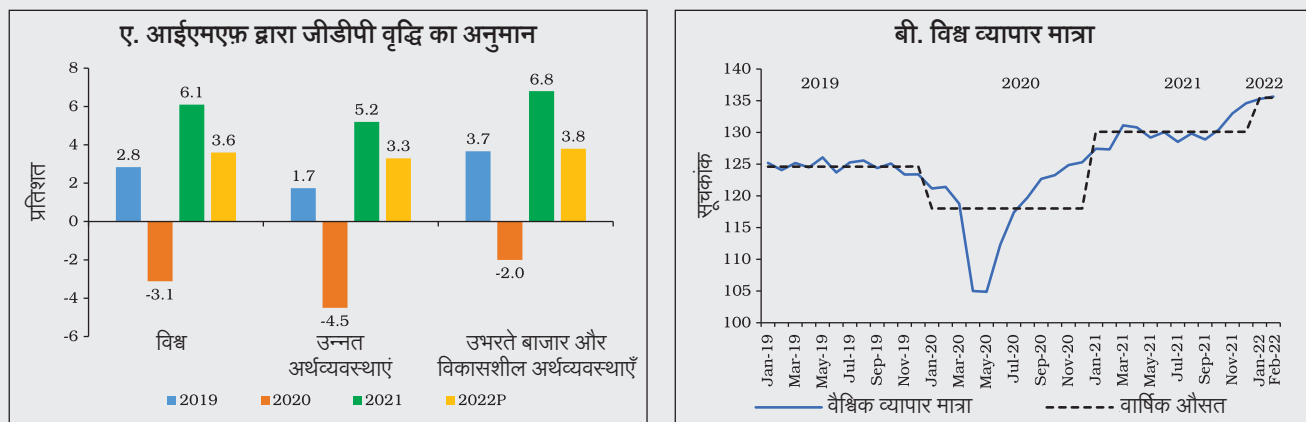
II.6.2 इस पृष्ठभूमि में, उप-खंड 2 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है जिनके परिप्रेक्ष्य में बाह्य संतुलन में ये बदलाव हुए। इसके बाद क्रमशः उप-खंड 3 और 4 में पण्य वस्तुओं का व्यापार और अदृश्य मदों पर चर्चा की जाती है। उप-खंड 5 पूंजी प्रवाह का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बाह्य सुभेद्यता संकेतकों का आकलन उप-खंड 6 में दिया गया है, जिसके बाद निष्कर्ष निकाला गया है।

2. वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां

II.6.3 वैश्विक आर्थिक गतिविधि ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही में, यद्यपि असमान रूप से, तेजी प्राप्त की, लेकिन वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में अपनी गति खो दी क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में बढ़ते संक्रमण और आपूर्ति की कमी ने अपना प्रभाव दिखाया। आपूर्ति शृंखला और लॉजिस्टिक्स व्यवधानों के साथ-साथ पण्य कीमतों के दबावों में अंतरराष्ट्रीय उछाल ने वैश्विक आर्थिक सुधार में अधोगामी जोखिम पैदा किए। यद्यपि वैश्विक संवृद्धि वर्ष 2020 में (-) 3.1 प्रतिशत से वर्ष 2021 में 6.1 प्रतिशत तक बढ़ गई, आईएमएफ ने अप्रैल 2022 में अपने वैश्विक संवृद्धि अनुमान को संशोधित कर जनवरी 2022 में 4.4 प्रतिशत से घटाकर 3.6 प्रतिशत कर दिया (चार्ट III 6.1ए)। फरवरी 2022 के अंत में, वित्तीय बाजार में उथल-पुथल के नए दौर, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में समकालिक उतार-चढ़ाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्टैगफ्लेशन के खतरे में डाल दिया और आपूर्ति बाधाओं एवं विघटन के खतरे तीव्र हो गए।

II.6.4 वर्ष 2021 के दौरान विश्व पण्य व्यापार, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत वृद्धि, आपूर्ति में व्यवधान और उच्च माल ढुलाई दरों के बावजूद, मूल्य के संदर्भ में 26.0 प्रतिशत की वृद्धि और मात्रा के संदर्भ में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए महामारी-पूर्व स्तर पर पहुंच गया (चार्ट II.6.1बी)। इस प्रकार, महामारी के दौरान विश्व व्यापार में संकुचन कम गंभीर प्रतीत होता है, और पहले के आघातों जैसे जीएफसी (चार्ट II.6.2) की तुलना में रिकवरी बहुत तेज (यूएनसीटीएडी) रही है। अंकटाड (यूएनसीटीएडी) के फरवरी 2022 के वैश्विक व्यापार अद्यतन के अनुसार, वैश्विक व्यापार का मूल्य वर्ष 2021 में 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सेवाओं में व्यापार, हालांकि, पण्य व्यापार से पिछड़ गया जिसका मुख्य कारण यात्रा और पर्यटन क्षेत्र था, जो महामारी के कारण लगे यात्रा प्रतिबंधों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था।

चार्ट II.6.1: वास्तविक जीडीपी और विश्व व्यापार मात्रा



पी: पूर्वानुमान
स्रोत: आईएमएफ़ और सीपीबी नीदरलैंड

II.6.5 एफडीआई प्रवाह वर्ष 2021 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) के प्रभुत्व के कारण फिर से बढ़त हुई। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पोर्टफोलियो प्रवाह के दृष्टिकोण में नगद मुद्रा जारी करने में मजबूत बढ़त के साथ सुधार हुआ, जबकि स्थानीय मुद्रा ऋण प्रवाह कमजोर रहा। वर्ष 2021 के अंत में, परिसंपत्ति खरीद टेपर के क्रमावेशन के लिए नीति सामान्यीकरण के इरादे, बढ़े हुए मुद्रास्फीति जोखिम, अस्थिरता के नए दौर के कारण बढ़ी अनिश्चितताओं ने वैश्विक वित्तीय बाजार

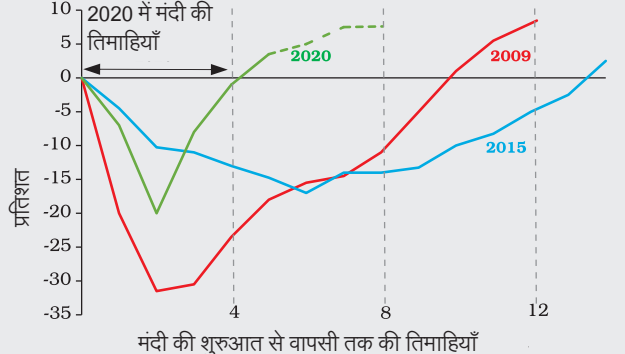
की स्थिति को अस्थिर कर दिया और सुरक्षित निवेश स्थान की तलाश में पोर्टफोलियो प्रवाह को एक परिसंपत्ति के रूप में ईएमई से पलायन को उत्प्रेरित किया।

3. पण्य व्यापार

II.6.6 वर्ष 2021-22 भारत के पण्य व्यापार के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष साबित हुआ। निर्यात और आयात दोनों ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गए। वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आए व्यवधानों को दूर करते हुए, निर्यात में व्यापक वसूली ने नए बाजारों और उत्पाद श्रेणियों में विस्तार किया। वर्ष 2021-22 के दौरान, अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में भारत के पण्य निर्यात और आयात में क्रमशः महामारी-पूर्व के स्तर पर 33.9 प्रतिशत और 28.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मात्रा के लिहाज से निर्यात में इसी आधार पर 16.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही से आयात महामारी-पूर्व के स्तर को पार कर गया (सारणी II.6.1)।

II.6.7 अलग-अलग स्तरों पर, निर्यात में वृद्धि इंजीनियरिंग सामानों, पेट्रोलियम उत्पादों, रसायनों, कृषि उत्पादों, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक सामानों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स तथा रत्नों और आभूषणों द्वारा संचालित थी। अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान हुए नुकसान को पलटते हुए परिधानों जैसी श्रम-प्रधान

चार्ट II.6.2: प्रत्येक व्यापार मंदी की शुरुआत से वैश्विक व्यापार में संचयी परिवर्तन



टिप्पणी: 1. रेखाएं बताती हैं कि पिछली दो मंदियों की तुलना में 2020 में व्यापार में तेजी से सुधार हुआ (तिमाहियों की संख्या कम)।
2. 2009 की व्यापार मंदी वैश्विक वित्तीय संकट के कारण हुई थी (जीएफसी) और 2015 की मंदी पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तन और पण्य कीमतों में गिरावट के परिणामस्वरूप हुई। 2020 में मंदी कोविड-19 महामारी से प्रेरित थी।

स्रोत: यूएनसीटीएडी

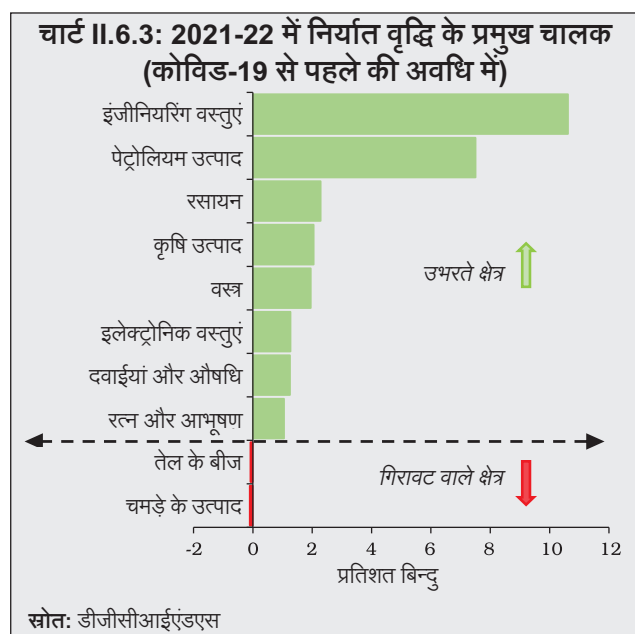
सारणी II.6.1: भारत का पण्य वस्तु व्यापार

	मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर \$ में			वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) प्रतिशत में			प्री-कोविड अवधि में वृद्धि
	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22
1	2	3	4	5	6	7	8
निर्यात							
पहली तिमाही	80.9	51.3	95.5	-1.4	-36.6	86.1	18.1
दूसरी तिमाही	78.2	74.1	102.7	-3.9	-5.3	38.6	31.3
तीसरी तिमाही	79.1	75.8	106.8	-1.9	-4.2	41.0	35.1
चौथी तिमाही	75.1	90.4	116.8	-12.7	20.4	29.2	55.6
वार्षिक	313.3	291.6	421.9	-5.1	-6.9	44.7	34.7
आयात							
पहली तिमाही	130.1	61.3	127.0	1.1	-52.9	107.3	-2.4
दूसरी तिमाही	118.0	88.3	147.5	-11.3	-25.2	67.1	25.0
तीसरी तिमाही	116.1	110.8	166.9	-11.2	-4.6	50.6	43.7
चौथी तिमाही	110.5	131.7	170.7	-9.2	19.1	29.6	54.4
वार्षिक	474.7	392.0	612.0	-7.7	-17.4	56.1	28.9
व्यापार शेष							
पहली तिमाही	-49.2	-9.9	-31.4				
दूसरी तिमाही	-39.7	-14.1	-44.8				
तीसरी तिमाही	-37.1	-35.1	-60.1				
चौथी तिमाही	-35.4	-41.2	-53.9				
वार्षिक	-161.4	-100.4	-190.1				

टिप्पणी: तिमाही आंकड़ों का योग वार्षिक योग से भिन्न हो सकता है।

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

निर्यात श्रेणियों ने भी सकारात्मक योगदान दिया। हालांकि, चमड़े के उत्पादों और तिलहनों में मामूली गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.6.3)।



II.6.8 पिछले दशक में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी से निर्यात समूह में अंतर-अस्थायी बदलाव आया है (आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, 2020-21)। इसके विपरीत, रत्न और आभूषण और रेडीमेड कपड़ों के शेरों में गिरावट आई है (चार्ट II.6.4)।

II.6.9 इंजीनियरिंग सामान, जो भारत के कुल निर्यात का एक-चौथाई हिस्सा हैं, ने वर्ष 2021-22 में अपने महामारी-पूर्व स्तरों से लगभग 42 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की। अप्रैल-फरवरी 2021-22 के दौरान लोहे और स्टील के निर्यात ने कुल इंजीनियरिंग निर्यात की वृद्धि में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दिया, जो कि बढ़ती वैश्विक कीमतों, मजबूत वैश्विक मांग और चीन द्वारा उत्पादन में कटौती से लाभान्वित हुआ (चार्ट II.6.5)। सरकार ने विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लिए उत्पादन-लिंक प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की घोषणा की है (बॉक्स II.6.1)।

मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) [ओईसीडी, 2020] के माध्यम से सेवाओं, कच्चे माल, भागों और घटकों में लेनदेन शामिल है। भारत का जीवीसी एकीकरण, जैसा कि जीवीसी भागीदारी सूचकांक द्वारा मापा गया है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) देशों (सकल निर्यात का 45.9 प्रतिशत) के सापेक्ष कुल निर्यात से 34.0 प्रतिशत कम रहा है। शिपिंग कनेक्टिविटी, अधिक जीवीसी भागीदारी, उच्च एफडीआई प्रवाह, और कम टैरिफ दरें इस घटना को चला रही हैं (चार्ट 1a और 1b)।

2000-2019 की अवधि के लिए 40 प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाला एक अंतर-देशीय पैनेल रिग्रेशन फ्रेमवर्क, देश के विनिर्माण निर्यात के साथ वर्ष t (एमईएक्सपी _{t}) में निर्भर चर के रूप में और जीवीसी भागीदारी सूचकांक (जीवीसी _{t}) और शिपिंग कनेक्टिविटी इंडेक्स (शिपिंग _{t}) के रूप में और टैरिफ स्तर (टैरिफ _{t}), शोध और विकास (आरएंडडी _{t}) खर्च, बुनियादी ढांचे और एफडीआई अंतर्वाह के रूप में नीचे दिए गए फॉर्म में नियंत्रण चर के रूप में पता चलता है कि जीवीसी भागीदारी सभी विशिष्टताओं (तालिका 1) में विनिर्माण निर्यात के लिए निर्यात प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

$$MEExp_{it} = \beta_1 GVC_{it} + \beta_2 Tariff_{it} + \beta_3 Shipping_{it} + \mu Other\ controls_{it} + \epsilon_t$$

(यूएनसीटीएडी, 2018)

शिपिंग कनेक्टिविटी इंडेक्स का निर्यात पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उच्च प्रशुल्क स्तर इनपुट लागत संरचना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इन परिणामों से पता चलता है कि भले ही उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लक्ष्य जीवीसी में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है, उच्च टैरिफ दरें, विशेष रूप से मध्यवर्ती वस्तुओं पर, भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में बाधक हो सकती हैं। आसियान देशों में प्रथाओं की तर्ज पर आरएंडडी के लिए लंबी अवधि के कर प्रोत्साहन और उपयुक्त एफडीआई

सऊदी अरब भारत के पेट्रोलियम निर्यात के लिए पांचवें और सातवें सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बन गए हैं। गंतव्य और उत्पाद-वार विविधीकरण भारतीय रिफाइनरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को रेखांकित करता है, जो उच्च मूल्ययोजन और संकेंद्रण जोखिम में कमी को दर्शाता है (चार्ट II.6.6)।

II.6.11 भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों सहित कृषि निर्यात में लगातार दूसरे वर्ष अप्रैल-फरवरी 2021-22 में प्रभावशाली

सारणी 1: विनिर्माण निर्यात प्रदर्शन पर लॉजिस्टिक्स और जीवीसी का प्रभाव
(आश्रित चर: विनिर्माण निर्यात)

व्याख्यात्मक चर	गुणांक		
	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3
1	2	3	4
जीवीसी _{t}	0.0128*** (0.00346)	0.0114*** (0.00325)	
लॉग (शिपिंग _{t})	0.0911* (0.0468)		0.0984** (0.0475)
लॉग (आर एंड डी _{t})	0.147*** (0.0474)	0.233*** (0.0429)	0.139*** (0.0481)
लॉग (बिजली _{t})	1.898*** (0.332)	1.914*** (0.327)	1.642*** (0.330)
टैरिफ दर _{t}	-0.0162* (0.00830)	-0.0177** (0.00818)	-0.0127 (0.00838)
एफडीआई _{t}	0.000582** (0.000255)	0.000562** (0.000245)	0.000644** (0.000258)
स्थिर	15.26*** (1.580)	15.50*** (1.543)	16.99*** (1.533)
गणनाएं	446	511	446
आर ²	0.53	0.52	0.51

***: 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण। ** 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण है।

* 10 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण।

टिप्पणी: कोष्ठक में मानक त्रुटियाँ।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणनाएं।

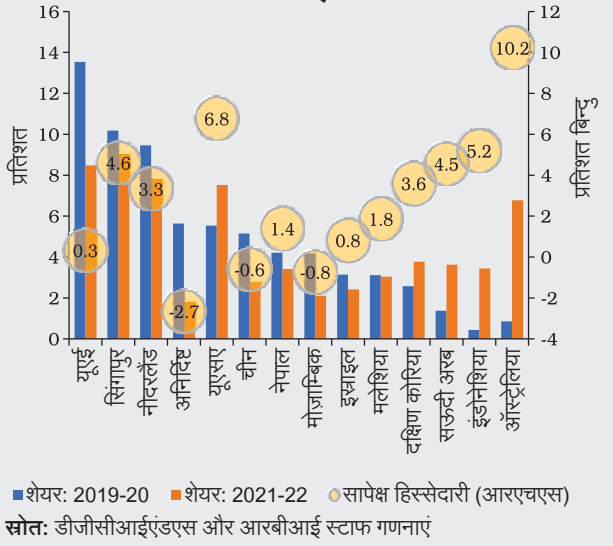
नीतियां भारत के विनिर्माण निर्यात में तकनीकी प्रतिस्पर्धा और निर्यात-उन्मुखीकरण ला सकती हैं।

सन्दर्भ:

1. ओसाकवे, पी.एन. और जीन-मार्क किलोलियो (2018), 'व्हाट ड्राइवर्स एक्सपोर्ट डायवर्सिफिकेशन? न्यू एविडेन्स फ्रॉम ए पैनेल ऑफ डवलपिंग कंट्रीज, यूएनसीटीएडी शोध पत्र संख्या 3/2018, यूएनसीटीएडी।
2. ओईसीडी (2020), 'ट्रेड पॉलिसी इंप्लीकेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चैन', ओईसीडी ट्रेड पॉलिसी ब्रीफ।

वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-फरवरी 2021-22 में भारत के गेहूं के निर्यात में वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से प्रमुख वैश्विक निर्यातक देशों, जैसे कनाडा और रूस में बढ़ी हुई माल ढुलाई लागत और कम भंडारण से लाभान्वित हुई। वर्ष 2019-20 में चावल का निर्यात अपने स्तर से 1.5 गुना अधिक बढ़ा। चावल की अलग-अलग किस्मों के भीतर, गैर-बासमती किस्मों के निर्यात में विशेष रूप से बांग्लादेश, चीन और वियतनाम जैसे बाजारों में बढ़ती

चार्ट II.6.6: भारत के पेट्रोलियम निर्यात का गंतव्य-वार प्रोफाइल



कीमत प्रतिस्पर्धा से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है (चार्ट II.6.7 ए और चार्ट II.6.7 बी)।

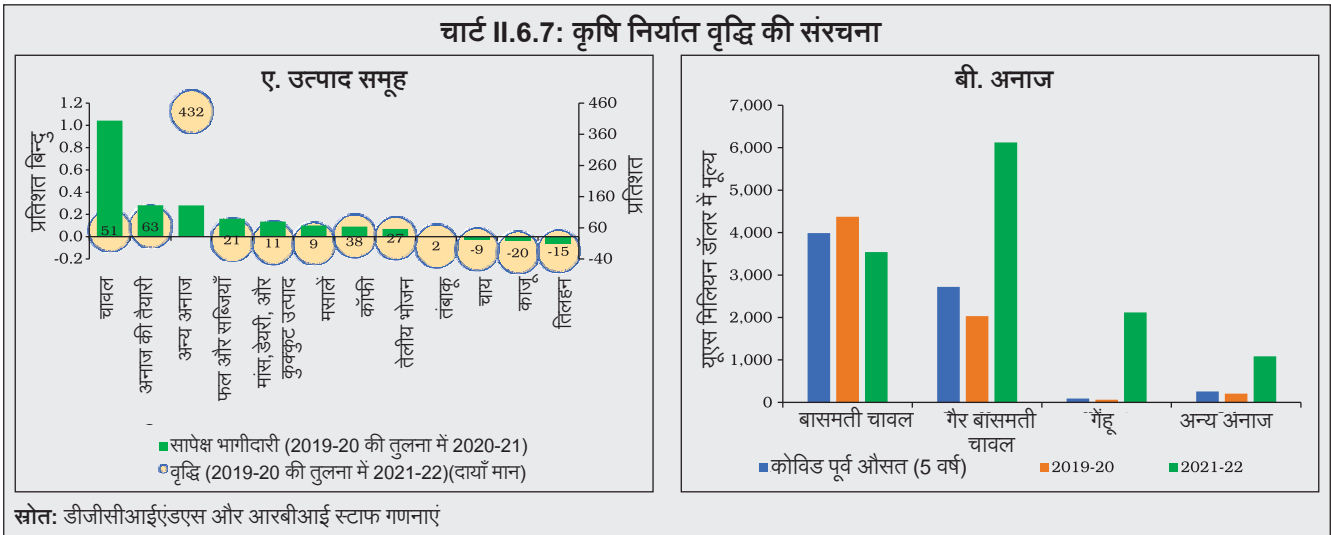
II.6.12 रत्न और आभूषण निर्यात, जिसमें जो पिछले चार वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति रही है, वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यह बहाली मोतियों और कीमती पत्थरों के निर्यात और भारतीय हीरों के सबसे बड़े निर्यात

बाजार, अमेरिका से मजबूत मांग से प्रेरित थी। दूसरी ओर, यूएई को निर्यात महामारी पूर्व स्तरों के लगभग 50 प्रतिशत पर बना हुआ है (चार्ट II.6.8ए और II.6.8बी)।

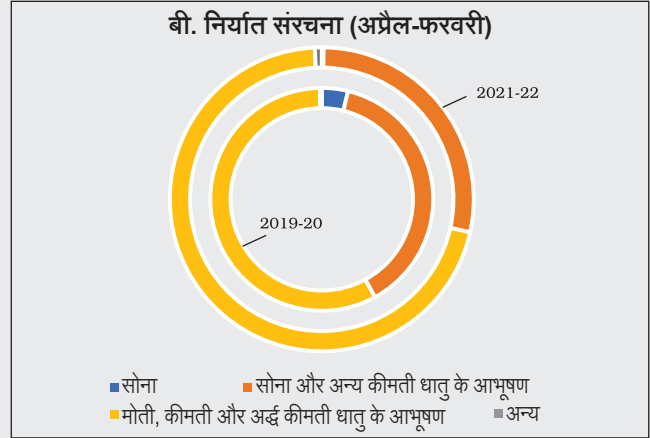
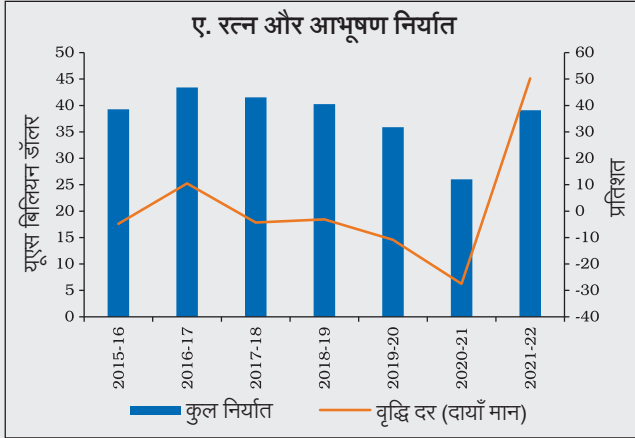
II.6.13 विश्व स्तर पर, सेमीकंडक्टरों की मांग का 11 प्रतिशत हिस्सा आटोमोटिव उद्योग से आता है। यद्यपि 2021-22 के दौरान भारत से ऑटोमोटिव निर्यात में 2019-20 (महामारी-पूर्व) की तुलना में 17.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि देखी गई, वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टरों की लगातार बनी रही कमी के कारण उत्पादन में कटौती की गई और कारखानों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा (चार्ट II.6.9ए और III 6.9 बी)।

II.6.14 वैश्विक व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रमुख बाधा पोत-परिवहन उद्योग में व्यवधान है, जो समुद्री लॉजिस्टिक्स को प्रभावित करता है। 34 अलग-अलग व्यापार लेन और 60 से अधिक मालवाहकों वाहक को कवर करने वाले जहाजों की समय-सारणी विश्वसनीयता महामारी- पूर्व समय (2019-20) में 76.5 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में औसतन 35.0 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप, जहाजों के आवागमन में वैश्विक औसत देरी महामारी से पहले 4.3 दिनों की तुलना में 2021-22 के दौरान 7.1 दिनों की थी। दी फ्रेटोस बाल्टिक ग्लोबल कंटेनर इंडेक्स, जो 12 वैश्विक व्यापार लेन में महासागर कंटेनर परिवहन

चार्ट II.6.7: कृषि निर्यात वृद्धि की संरचना



चार्ट II.6.8: रत्न और आभूषण निर्यात



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

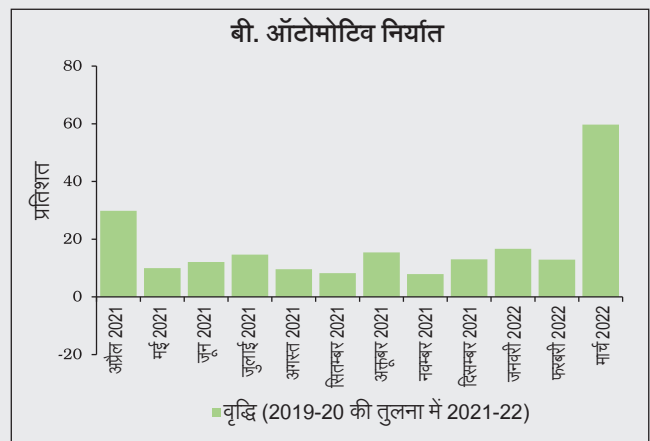
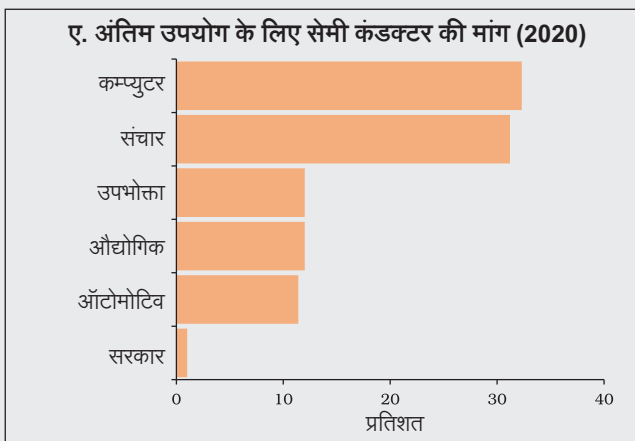
स्थान को दर्शाता है, अक्टूबर 2021 में अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और महामारी- पूर्व के स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है।

II.6.15 पण्य आयात में व्यापक आधार पर विस्तार देखा गया, जो मजबूत घरेलू मांग के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-पूर्व स्तरों को 28.9 प्रतिशत से पार करता हुआ 611.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। मात्रा के संदर्भ में, वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड-पूर्व स्तरों की तुलना में पण्य आयात में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अलग-अलग स्तर पर देखें तो पीओएल

आयात का प्रमुख घटक था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना थे (चार्ट II.6.10ए और II.6.10बी)।

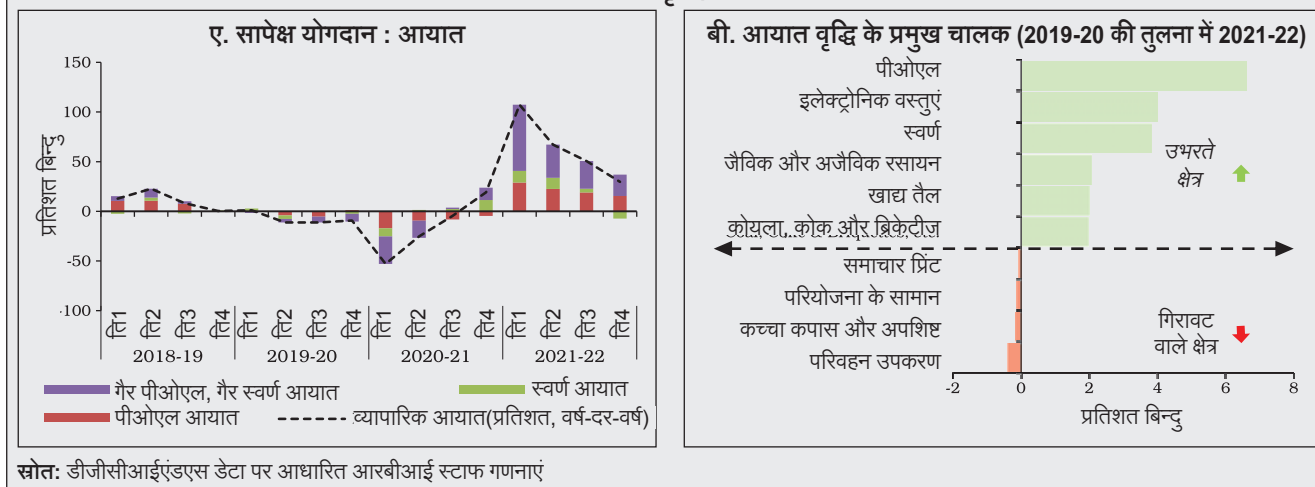
II.6.16 हाल ही में, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें, जिनमें रूस-यूक्रेन संकट के बीच अस्थिरता बनी रही, 31 मार्च 2022 को अपने हाल ही (8 मार्च 2022) के उच्च स्तर 128 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक कम हो गईं। साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दर में वृद्धि की उम्मीद और चीन में हाल ही में कोविड-19 के प्रकोप ने तेल की मांग को कम कर दिया। स्रोत-वार, इराक और सऊदी अरब

चार्ट II.6.9: ऑटोमोटिव सेक्टर पर सेमीकंडक्टर की कमी का प्रभाव



स्रोत: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन और सीईआईसी।

चार्ट II.6.10: आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान



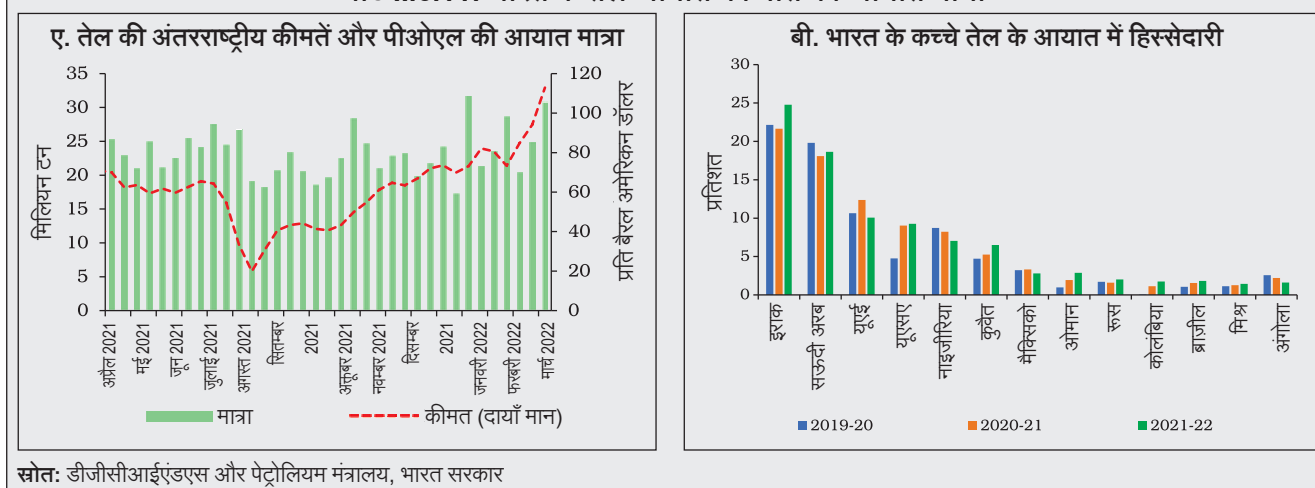
भारत के लिए कच्चे तेल के आयात का प्रमुख स्रोत बने रहे। पीओएल के लिए भारत की आयात टोकरी का विविधीकरण वर्ष 2021-22 के दौरान हुआ, जो आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने के लिए एक सोचे-समझे नीतिगत उपाय को दर्शाता है (चार्ट II.6.11ए और II.6.11बी)।

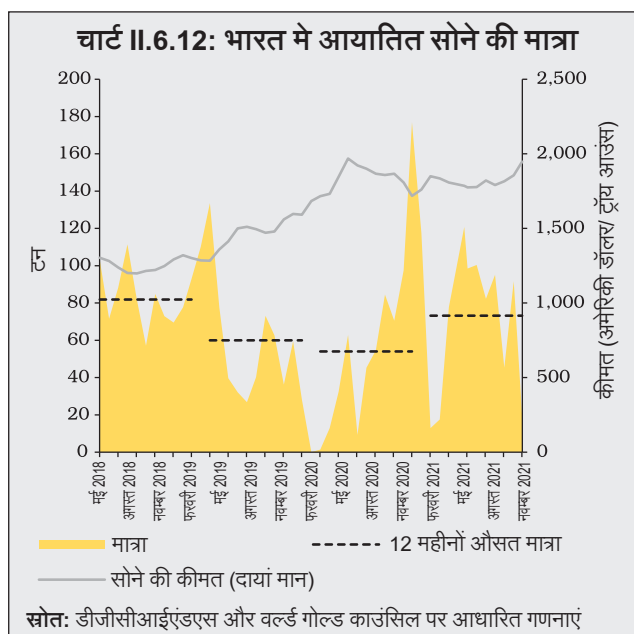
II.6.17 वर्ष 2021-22 में भारत का 46.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सोने का आयात कोविड-पूर्व स्तरों से अधिक हो गया। मात्रा के संदर्भ में, कोविड -19 मामलों में गिरावट, टीकाकरण अभियान में तेजी के बाद प्रतिबंधों में ढील और त्योहार/शादी की मांग के कारण जुलाई 2021 से मांग में वृद्धि हुई है (चार्ट

II.6.12)। यद्यपि जनवरी 2022 से बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति की आशंकाओं के बीच सोने के आयात में गिरावट आई। मार्च 2022 में सोने की कीमतों में गिरावट 1 प्रतिशत ही रही जो प्रति ट्रॉय आउंस 1,947 अमेरिकी डालर थी जो अगस्त 2020 में अब तक की रिकार्ड उंचाई प्रति ट्रॉय आउंस 1968 अमेरिकी डालर थी।

II.6.18 भारत अपने कुल सोने के आयात का लगभग 10 प्रतिशत यूई से आयात करता है, जिसके एक मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के सफल कार्यान्वयन के मद्देनजर बढ़ने की संभावना है।

चार्ट II.6.11: भारत के तेल आयात की गति की आयात मात्रा





II.6.19 गैर-तेल गैर-सोने के आयात में वर्ष 2021-22 में मजबूत वृद्धि देखी गई, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 47.1 प्रतिशत और महामारी-पूर्व स्तरों पर 28.0 प्रतिशत बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक सामानों, वनस्पति तेल, जैविक और अकार्बनिक रसायनों और कोयला, कोक तथा ब्रिकेट जैसे क्षेत्रों ने गैर-तेल गैर-सोने के आयात की वृद्धि में योगदान दिया।

II.6.20 भारत वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। आयात बिल वर्ष 2019-20 में 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान 19.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो आयात लागत में वृद्धि को दर्शाता है। संरचना-वार, पाम तेल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, और कुल खाद्य तेल में इसका हिस्सा 62.0 प्रतिशत है। मलेशिया³⁴ जैसे प्रमुख

पाम तेल आपूर्तिकर्ताओं में प्रवासी श्रमिकों की तंग स्थिति और इंडोनेशिया³⁵ में पाम तेल पर निर्यात लेवी में वृद्धि के कारण पाम तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उच्च बनी रहीं। भारत सरकार ने पाम तेल सहित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाया और मुद्रास्फीति के दबाव³⁶ को कम करने के लिए जमाखोरी से बचने के लिए स्टॉक सीमा लगाई।

II.6.21 मोती और कीमती पत्थरों का आयात, जिसमें 2020 के अंत में बहाली देखी गई थी उसमें वर्ष 2021 में और मजबूती देखने की मिली क्योंकि इस अवधि में रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्यात की मांग में तेजी आयी थी। वर्ष 2021-22 के दौरान 31.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मोती और कीमती पत्थरों के आयात में महामारी से पहले के स्तर पर 38.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का लगभग दो-तिहाई गैर-औद्योगिक हीरे (60 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला सबसे बड़ा घटक) द्वारा संचालित था। यूएई, यूएसए और बेलजियम आयात के प्रमुख स्रोत बने रहे (चार्ट II.6.13ए और II.6.13बी)।

II.6.22 वर्ष 2021-22 के दौरान महामारी-पूर्व के स्तर से भारत के उर्वरक आयात ने भी मूल्य की दृष्टि से वृद्धि (मूल्य के संदर्भ में 89.7 प्रतिशत तथा मात्रा के संदर्भ में 3.2 प्रतिशत) दर्ज की, जो उर्वरक की वैश्विक कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है। भारत के उर्वरक आयात का प्रमुख घटक यूरिया (40.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ) की वैश्विक कीमतों में, 2021-22 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 124.1 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि देखी गई।

II.6.23 पूंजीगत वस्तुओं का आयात, जो कि भारत के कुल आयात में एक-चौथाई से अधिक का योगदान देता है, महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान 15.6

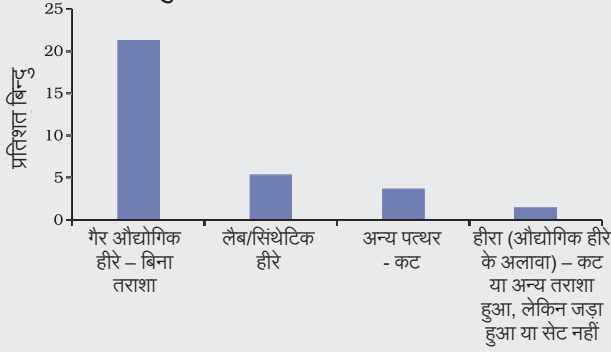
³⁴ तिलहन, तेल और मासिक कीमत की अद्यतन जानकारी, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र (दिसंबर 2021)।

³⁵ तिलहन: विश्व बाजार और व्यापार, संयुक्त राज्य कृषि विभाग (यूएसडीए) [दिसंबर 2021]।

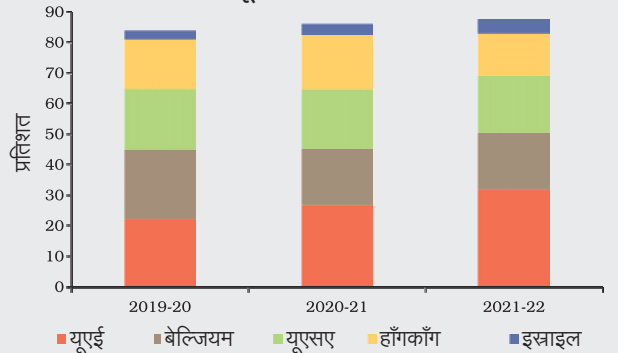
³⁶ उदाहरण के लिए 23 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कच्चे पाम/सोयाबीन/सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य; रिफाइंड सोयाबीन/सूरजमुखी तेल पर 32.5 प्रतिशत से 17.5 प्रतिशत तक; और रिफाइंड पाम तेल पर 17.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक कर दिया गया है। <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1808668>.

चार्ट II.6.13: मोती और कीमती पत्थर आयात

ए. आयात वृद्धि में सापेक्ष योगदान) अप्रैल-फरवरी 2019-20 की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2020-21



बी. आपूर्तिकर्ताओं का हिस्सा



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और एमओसीएंडआई के डेटा पर आधारित आरबीआई स्टाफ गणनाएं

प्रतिशत तक बढ़ा, जो निवेश की मांग में वृद्धि को दर्शाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा योगदान था (चार्ट II.6.14)।

II.6.24 इन गतिविधियों का प्रभाव यह रहा कि भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 190.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान 161.4 बिलियन

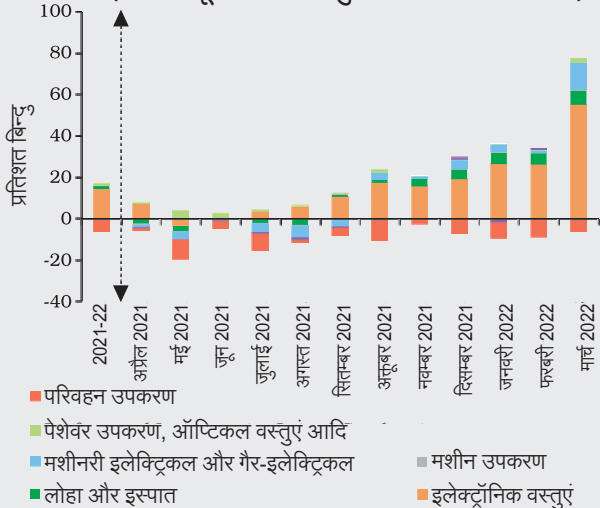
अमेरिकी डॉलर था, जिसमें तेल की कमी कुल घाटे का आधा हिस्सा थी (चार्ट II.6.15ए)। द्विपक्षीय आधार पर, चीन के साथ व्यापार घाटा और बढ़ा जबकि यूएसए और बांग्लादेश के साथ व्यापार अधिशेष में काफी विस्तार हुआ (चार्ट II.6.15बी)।

4. अदृश्य मर्दे

II.6.25 अप्रैल - दिसंबर 2021-22 के दौरान अदृश्य मर्दों से निवल प्राप्तियां, सीमा पार सेवाओं, आय और हस्तांतरण के लेन-देन में आघात-सहनीयता देखने को मिली है (चार्ट II.6.16)। जबकि वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के बाद से सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात की मांग क्रमिक रूप से बढ़ी है तथा विप्रेषण प्राप्तियां भी मजबूत बनी हुई हैं। इसके अलावा, निवल निवेश आय बहिर्वाह में वृद्धि के बाद प्राथमिक आय खाते पर निवल व्यय में मामूली वृद्धि हुई।

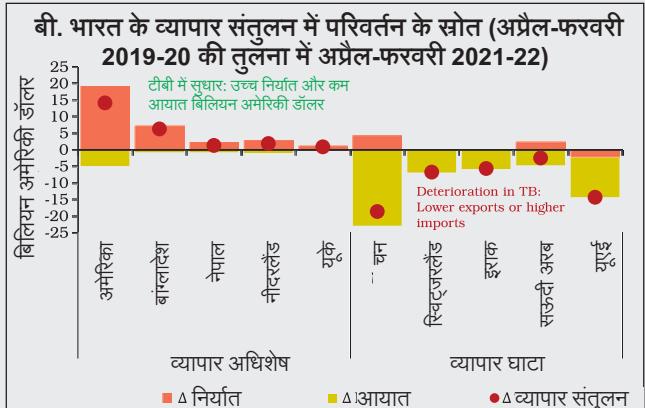
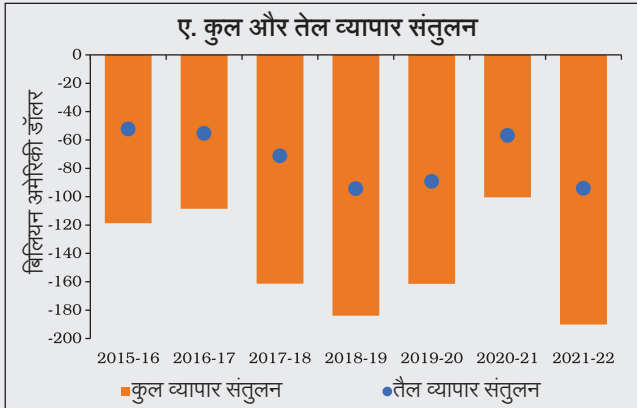
II.6.26 सेवाओं में वैश्विक व्यापार में सुधार के साथ-साथ, वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर निर्यात में, इसके बाद व्यापार और परिवहन सेवाओं में वृद्धि के कारण सेवा निर्यात आघात-सह रहा (चार्ट II.6.17)।

चार्ट II.6.14: पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि का सापेक्ष योगदान (कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में वर्ष 2021-22 में)



स्रोत: डीजीसीआईएंडएस पर आधारित गणनाएं

चार्ट II.6.15: भारत का पण्य व्यापार घाटा



टिप्पणी: एक सकारात्मक Δ का तात्पर्य कम आयात और इसका विपरीत भी सत्य।
स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आधारित आरबीआई स्टाफ गणनाएं

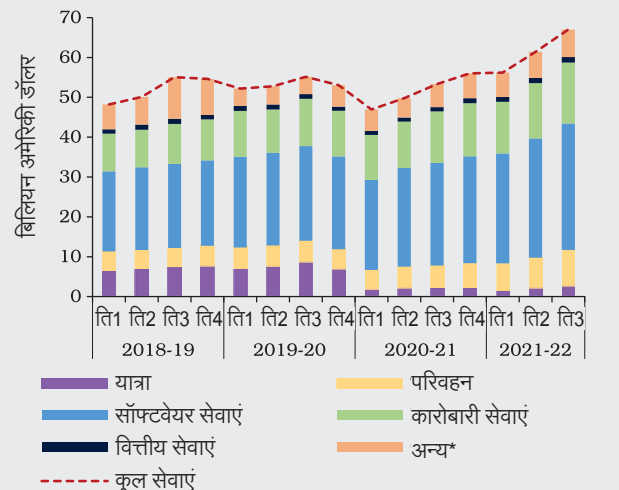
टीबी: व्यापार संतुलन

II.6.27 भारत के कुल सेवाओं के निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है। यात्रा और परिवहन सेवाएं, जो महामारी के कारण बहुत प्रभावित थीं, ने कम सुधार दिखाया (चार्ट II.6.18ए और II.6.18बी)।

II.6.28 वर्ष 2021-22 की पहली छमाही तक भारत को विप्रेषण महामारी-पूर्व के स्तर तक आ गया (चार्ट II.6.19ए)।

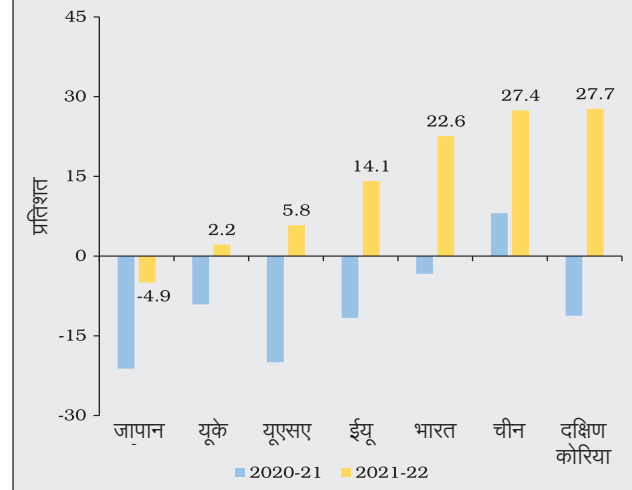
सितंबर 2021 में, रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपनी तेज भुगतान प्रणाली, जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस और पेनाओ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में 200 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की औसत लागत वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में 5.51 प्रतिशत (2019 की पहली तिमाही के बाद से उच्चतम)

चार्ट II.6.16: भारत के सेवा निर्यात की संरचना

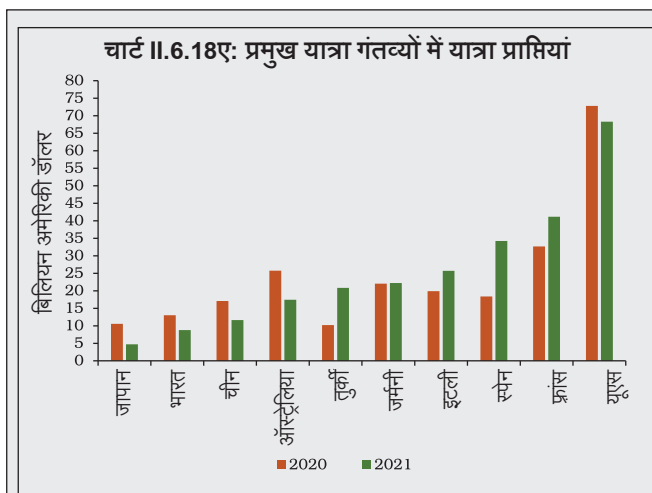


*: इसमें संचार सेवाएं शामिल हैं और सरकार कहीं शामिल नहीं है।
स्रोत: आरबीआई

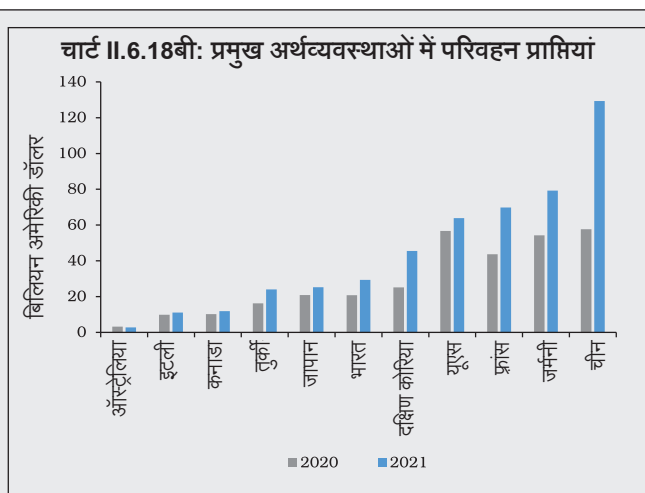
चार्ट II.6.17: देश-वार सेवाओं का निर्यात



*: 2021-22 के आंकड़े भारत को छोड़कर अप्रैल-फरवरी से संबंधित हैं। 2021-22 के लिए भारत से संबंधित आंकड़े पूरे वर्ष के लिए हैं, जिसमें जनवरी-मार्च 2022 के लिए अनंतिम आंकड़े भी शामिल हैं।
स्रोत: डब्ल्यूटीओ और आरबीआई



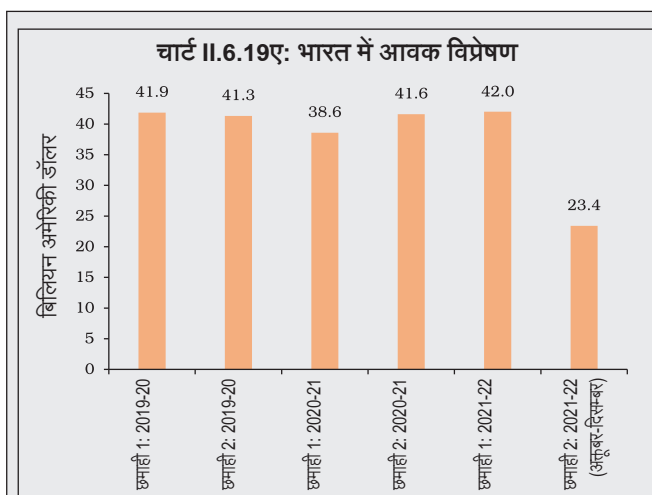
स्रोत: डब्ल्यूटीओ और आरबीआई



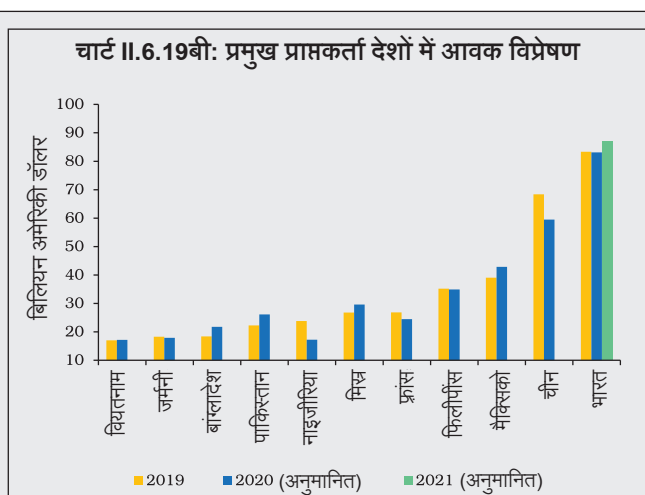
से घटकर वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 4.94 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान भारत वैश्विक विप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा (चार्ट II.6.19बी)।

II.6.29 आय लेखा के तहत, सीमा पार निवेश पर आय से संबंधित प्राप्ति और भुगतान और कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति जो घरेलू निवासी संस्थाएं शेष विश्व से अर्जित (या भुगतान) करती हैं, एक साल पहले की तुलना में अधिक थीं।

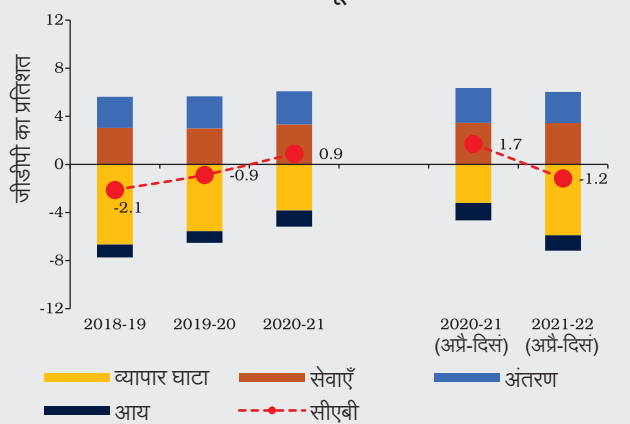
II.6.30 घरेलू मांग में सुधार और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, भारत के चालू खाते की शेष राशि में अप्रैल-दिसंबर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.2 प्रतिशत घाटा हुआ, जबकि एक साल पहले यह अधिशेष का 1.7 प्रतिशत था (चार्ट III 6.20ए)। वर्ष के भीतर देखें तो वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी के 0.9 प्रतिशत के अधिशेष के बाद वर्ष 2021-22 की दूसरी और तीसरी तिमाही में घाटा दर्ज किया गया। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, बढ़ते व्यापार घाटे और निवेश



स्रोत: आरबीआई और वर्ल्ड बैंक।

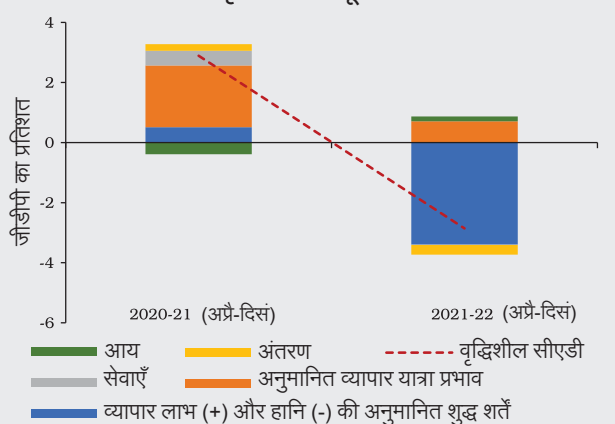


चार्ट II.6.20ए: भारत के चालू खाता घाटे की संरचना



स्रोत: आरबीआई और आईएमएफ।

चार्ट II.6.20बी: वृद्धिशील चालू खाता शेष के स्रोत



आय के निवल व्यय में वृद्धि के कारण व्यापार की नकारात्मक शुद्ध शर्तों ने अप्रैल-दिसंबर 2021-22 (चार्ट II.6.20बी) में चालू खाता घाटे में योगदान दिया।

II.6.31 कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और आपूर्ति शृंखला में आए व्यवधानों से प्रेरित वैश्विक मुद्रास्फिति में उछाल, भारत सहित अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख नीतिगत चुनौती के रूप में उभरा है, जिससे स्थानीय मुद्राओं के वास्तविक अधिमूल्यन के माध्यम से बाह्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संभवतः कम हो रही है।

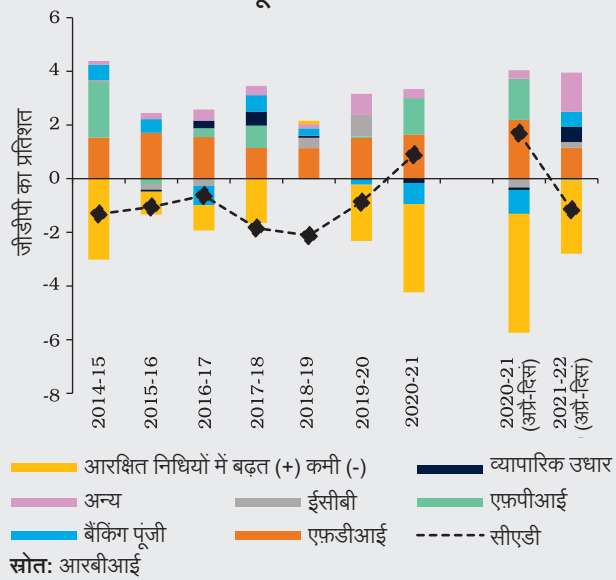
5. बाह्य वित्तपोषण

II.6.32 चालू खाते के घाटे के मध्यम स्तर को देखते हुए वर्ष 2021-22 में भारत की बाहरी वित्तीय जरूरतें मामूली थीं। वित्तीय प्रवाह के प्रमुख घटकों में, शुद्ध एफडीआई मजबूत रहा, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण अस्थिरता देखी गई। इसके अलावा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), व्यापार ऋण और बैंकिंग पूंजी के रूप में ऋणों में निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया। मजबूत शुद्ध पूंजी प्रवाह के बीच, अप्रैल-दिसंबर 2021 में भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में 63.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की

वृद्धि हुई (मूल्यांकन परिवर्तन को छोड़कर) [चार्ट II.6.21 और परिशिष्ट सारणी 8]।

II.6.33 पूंजी प्रवाह में वर्ष 2021-22 के दौरान एफडीआई का प्रभुत्व था, हालांकि इस अवधि के दौरान बाहरी एफडीआई में वृद्धि हुई थी (सारणी II.6.2)। वर्ष के दौरान, पेंशन फंड प्रबंधन कंपनियों, तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों और दूरसंचार

चार्ट II.6.21: चालू खाता घाटे का वित्तपोषण



स्रोत: आरबीआई

सारणी II.6.2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर \$)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
1. निवल एफडीआई (1.1-1.2)	30.7	43.0	44.0	39.3
1.1 निवल आवक एफडीआई (1.1.1-1.1.2)	43.3	56.0	54.9	55.0
1.1.1 सकल अंतर्वाह	62.0	74.4	82.0	83.6
1.1.2 प्रत्यावर्तन/ विनिवेश	18.7	18.4	27.0	28.6
1.2 निवल जावक एफडीआई	12.6	13.0	11.0	15.7

स्रोत: आरबीआई

सेवाओं सहित चुनिंदा क्षेत्रों में एफडीआई के लिए नीतिगत मानदंडों में और ढील दी गई। जबकि वर्ष 2021-22 में सकल आवक एफडीआई 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले के अपने स्तर के बराबर था, निवल एफडीआई (यानी, निवल आवक शून्य से निवल जावक) 39.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो एक साल पहले 44.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। शीर्ष एफडीआई निवेशक देश सिंगापुर, अमेरिका, मॉरीशस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड थे, जिन्होंने इस अवधि के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी का 76 प्रतिशत योगदान दिया (चार्ट II.6.22)। क्षेत्र-वार बात करें तो, कंप्यूटर सेवाओं, संचार सेवाओं और वित्तीय सेवाओं सहित

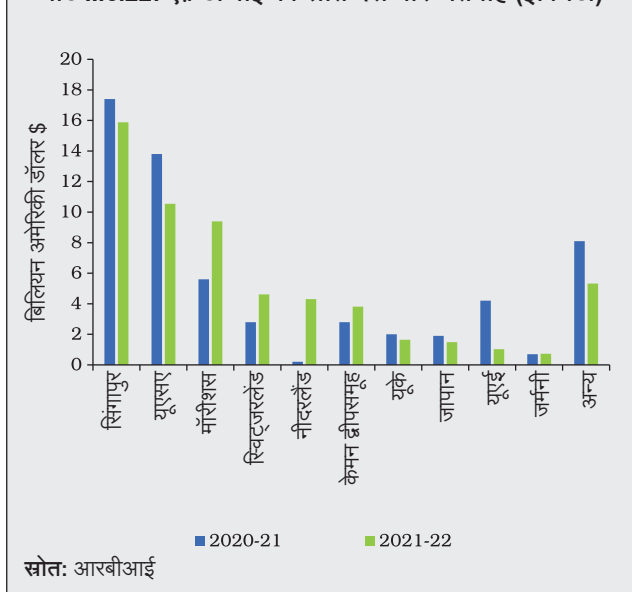
सेवा क्षेत्र वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में एफडीआई इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा था, इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र, खुदरा और थोक व्यापार, शिक्षा और अनुसंधान और विकास(आरएंडडी) का स्थान आता है। (परिशिष्ट सारणी 9)।

II.6.34 वर्ष के दौरान भारत से उच्च विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मुख्य रूप से सिंगापुर, यूएस, यूके, मॉरीशस, नीदरलैंड और फिलीपींस जैसे गंतव्यों के लिए था। वित्तीय, बीमा और व्यावसायिक सेवाएं, विनिर्माण, थोक और खुदरा व्यापार तथा रेस्तरां और होटल वर्ष के दौरान भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्र थे।

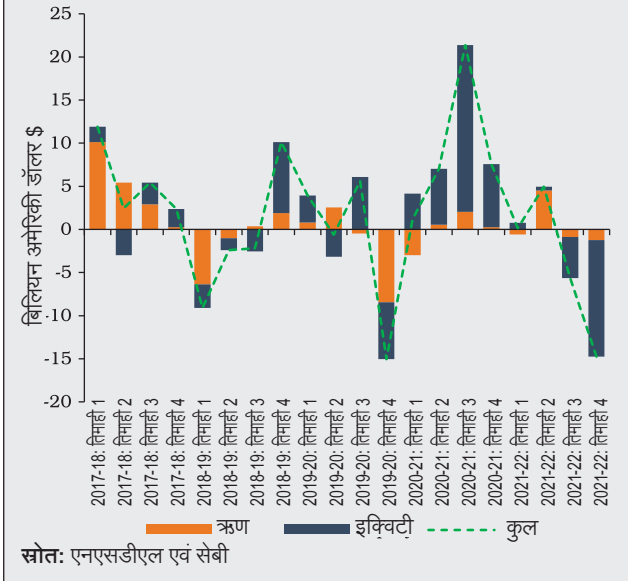
II.6.35 एफडीआई प्रवाह के विपरीत, निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड शुद्ध प्रवाह के बाद घट गया। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान शुद्ध खरीदारी करने के बाद, एफपीआई में दूसरी छमाही में, मुख्य रूप से इक्विटी सेगमेंट, से निकासी शुरू हो गई (चार्ट II.6.23)।

II.6.36 वर्ष 2021-22 के दौरान इक्विटी बाजार में एफपीआई के निवेश मार्ग के संदर्भ में, स्टॉक एक्सचेंज चैनल ने उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की। हालांकि, एफपीआई ने प्राथमिक बाजार खंड में अपनी निवेश रुचि को बनाए रखा (चार्ट II.6.24)। वास्तव में, एफपीआई द्वारा प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा अक्तूबर-नवंबर की अवधि के दौरान द्वितीयक से प्राथमिक बाजारों में बदल दिया गया था, जब अधिक मूल्य के प्रारंभिक सार्वजनिक

चार्ट II.6.22: एफडीआई का स्रोत देश-वार अंतर्वाह (इक्विटी)

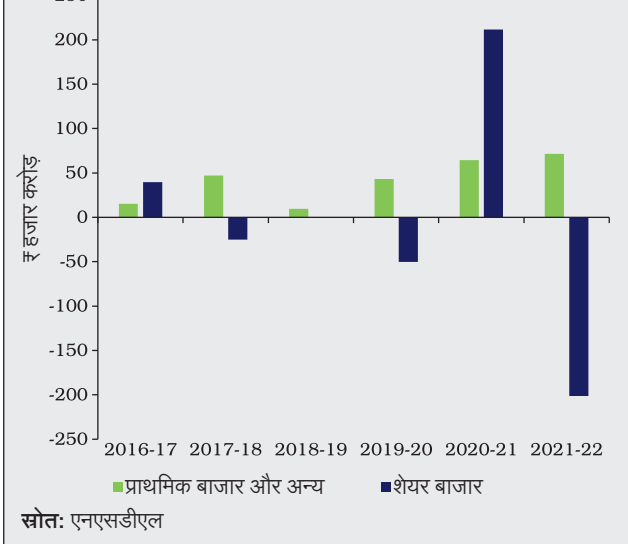


चार्ट II.6.23: भारत में निवल विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह



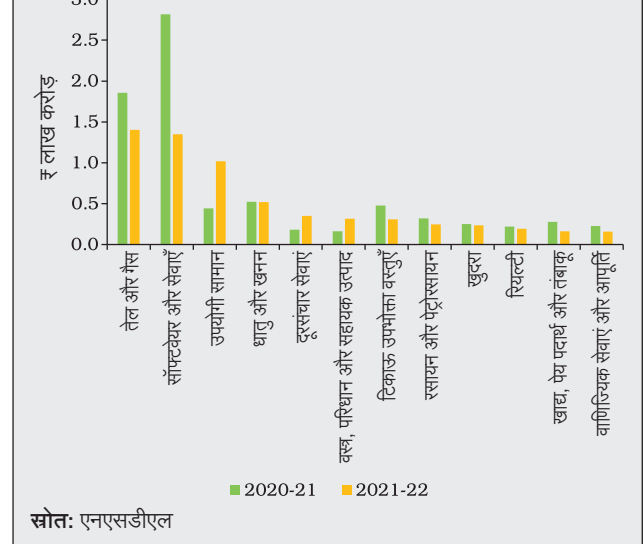
प्रस्ताव (आईपीओ) के मुद्दे पूंजी बाजार में आए थे। एफपीआई को मध्यावधि फ्रेमवर्क (एमटीएफ) या स्वैच्छिक अवधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आईएनवीआईटीएस) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों को हासिल करने की अनुमति दी गई।

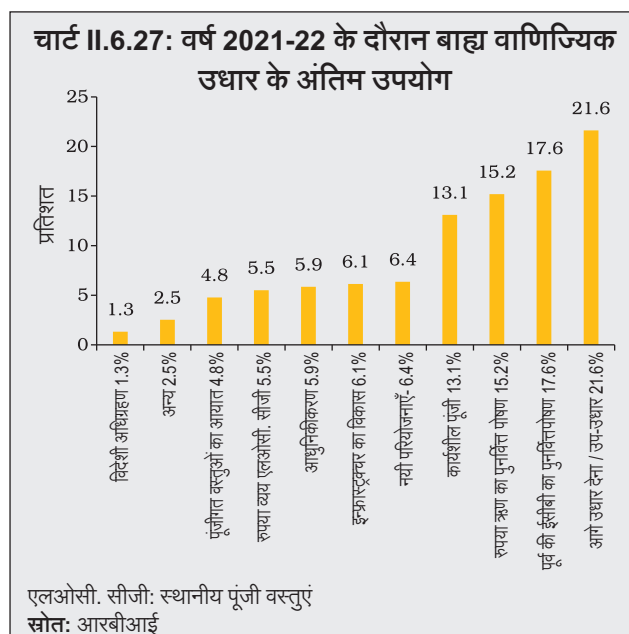
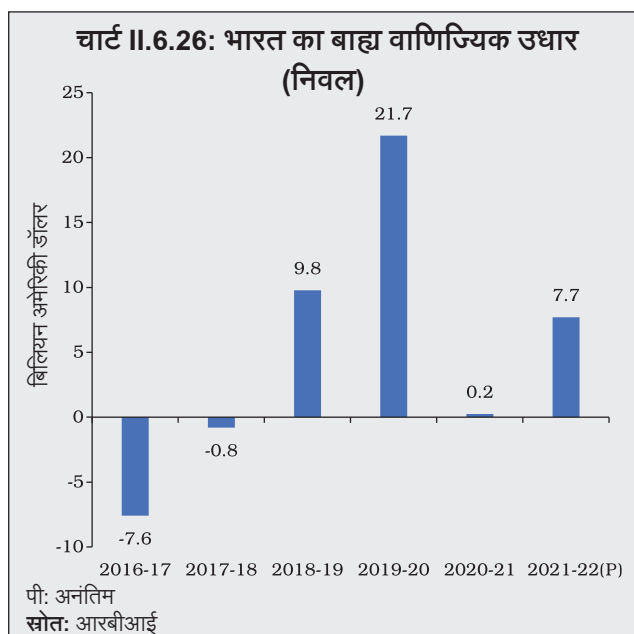
चार्ट II.6.24: इक्विटी मार्केट में निवेश मार्ग-वार एफपीआई



II.6.37 इक्विटी बाजार में एफपीआई प्रवाह का लगभग 74 प्रतिशत शीर्ष पांच क्षेत्रों, यथा तेल और गैस (22.3 प्रतिशत), सॉफ्टवेयर और सेवाएं (21.4 प्रतिशत), उपयोगी वस्तुएं (16.2 प्रतिशत), धातु और खनन (8.2 प्रतिशत) तथा दूरसंचार सेवाओं (5.5 प्रतिशत) में दर्ज किया गया। [चार्ट II.6.25]। वर्ष के दौरान ऋण बाजार में एफपीआई द्वारा निवल खरीद के मामूली स्तर के बावजूद, निवेश सीमा (सामान्य मार्ग) का कम उपयोग किया गया। 31 मार्च, 2022 तक, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में केवल 26.3 प्रतिशत सीमा का उपयोग किया गया (मार्च 2021 के अंत में 33.7 प्रतिशत), जबकि एसडीएल के लिए उपयोग दर एक प्रतिशत पर रही जो बेहद कम थी। इसके विपरीत, वीआरआर को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2022 से उसके लिए निवेश सीमा ₹1,00,000 करोड़ बढ़ाकर ₹2,50,000 करोड़ कर दी गई। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के कुल मूल्य में से फुली एक्सेसेबल रूट (एफएआर) के तहत बिना किसी प्रतिबंध के अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह से खोला गया, 31 मार्च, 2022 तक एफपीआई के पास 2.6 प्रतिशत हिस्सा था। कॉर्पोरेट बॉन्ड सेगमेंट में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट रेटिंग में कंपनियों के डाउनग्रेड और

चार्ट II.6.25: इक्विटी बाजार में एफपीआई के प्रमुख प्राप्तकर्ता क्षेत्र





अमेरिका में प्रतिफल दरों में वृद्धि के कारण एफपीआई का ब्याज कम रहा। कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई सीमा का लगभग 20.0 प्रतिशत (समग्र संदर्भ में) 31 मार्च, 2022 तक उपयोग में लाया गया था, जो मार्च 2021 के अंत की तुलना में 24.5 प्रतिशत कम था।

II.6.38 ईसीबी ने वर्ष 2021-22 के दौरान ईसीबी करारों की संख्या और करार की राशि दोनों के संदर्भ में वृद्धि दर्ज की (चार्ट II.6.26)। नीतिगत उपायों के संदर्भ में, सावधि जमा में अप्रयुक्त ईसीबी आय की पार्किंग के लिए छूट को 1 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, लिबोर को बंद करने तथा लिबोर और वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) के बीच क्रेडिट जोखिम और टर्म प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, नई विदेशी मुद्रा विदेशी उधारी और व्यापार ऋण लेनदेन के लिए समग्र लागत सीमा को बेंचमार्क दरों से क्रमशः 50 बीपीएस बढ़ाकर 500 बीपीएस और 300 बीपीएस कर दिया गया।

II.6.39 पहले के उधारों की अदायगी के अलावा, संवितरणों का उपयोग बड़े पैमाने पर उधारी/उप-उधारी, पहले के ईसीबी के पुनर्वित्त, रुपया के ऋणों के पुनर्वित्त, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, नई परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था (चार्ट II.6.27)। ईसीबी की बात

करें तो रुपये में मूल्यवर्धित ऋण और रुपये मूल्यवर्धित बांड (आरडीबी) की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 के दौरान कुल करार राशि का 8.4 प्रतिशत थी, जबकि एक साल पहले यह 6.0 प्रतिशत था। इसके अलावा, हेज किए गए विदेशी मुद्रा ऋणों की हिस्सेदारी वर्ष के दौरान 51.6 प्रतिशत रही, जो वर्ष 2020-21 के दौरान 51.3 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है।

II.6.40 आयात में सुधार के अनुरूप ही वर्ष के दौरान अल्पावधि व्यापार ऋण में भी वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर 2021-22 में अल्पावधि ऋण का निवल अंतर्वाह 13.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि एक साल पहले यह बहिर्वाह 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। लगभग 35 प्रतिशत व्यापार ऋण कच्चे तेल, सोना, कोयला और तांबे के आयात के लिए जुटाया गया था।

II.6.41 अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमाराशियां, जो कुल बकाया अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों का लगभग 72 प्रतिशत थीं, ने वर्ष 2021-22 के दौरान 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अंतर्वाह देखा जो कि एक साल पहले के 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी कम है (सारणी II.6.3)। एफसीएनआर (बी) खातों से मोचन और एनआरई

सारणी: II.6.3: अनिवासी जमाखातों के अंतर्गत प्रवाह

(बिलियन अमेरिकी डॉलर \$)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5
1. अनिवासी बाह्य (रूपया) खाता	7.3	5.6	8.8	3.3
2. अनिवासी सामान्य खाता	1.9	2.0	2.3	3.5
3. विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) खाता	1.1	1.1	-3.8	-3.6
अनिवासी जमाराशियाँ (1+2+3)	10.4	8.6	7.4	3.2

स्रोत: आरबीआई

जमाराशियों में तेजी से आई कमी अनिवासी जमाराशियों की निवल अभिवृद्धि में हुई गिरावट में योगदान दिया। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और ब्रिटेन के गैर-निवासियों द्वारा रखी गई जमाराशियों में बड़े पैमाने पर मोचन की सूचना प्राप्त हुई थी।

6. सुभेद्यता के संकेतक

II.6.42 भारत का विदेशी ऋण (जीडीपी के अनुपात के रूप में) अधिकांश उभरते बाजार समकक्षों की तुलना में कम रहा। मुख्य रूप से अगस्त 2021 में आईएमएफ द्वारा सामान्य विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) आबंटन के बाद, विदेशी ऋण ने मार्च 2021 के अंत की तुलना में दिसंबर 2021 के अंत में 41.2

बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी, 7.2 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की; हालांकि, जीडीपी के अनुपात के रूप में, यह इसी अवधि के दौरान 21.1 प्रतिशत से घटकर 20.0 प्रतिशत हो गया (सारणी II.6.4)। 36.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वाणिज्यिक उधार विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके बाद अनिवासी जमा (23.1 प्रतिशत) और अल्पावधि व्यापार ऋण (18.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ने आरक्षित पर्याप्तता संकेतकों में सुधार को प्रेरित किया। यह बाहरी जोखिमों और स्पिलओवर को कम करने के लिए अच्छा संकेत है। मार्च 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित 10 महीने के आयात का कवर प्रदान किया।

सारणी II.6.4 : बाह्य क्षेत्र की संवेदनशीलता के संकेतक (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत, जब तक अन्यथा इंगित नहीं किया गया हो)

संकेतक	2013	2020	2021	दिसं-अंत 2021
1	2	3	4	5
1. जीडीपी अनुपात की तुलना में बाह्य कर्ज	22.4	20.9	21.2	20.0
2. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	23.6	19.1	17.6	18.6
3. कुल कर्ज की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	42.1	42.4	44.1	44.4
4. कुल कर्ज की तुलना में रियायती कर्ज का अनुपात	11.1	8.8	9.0	8.2
5. कुल कर्ज की तुलना में आरक्षित निधियों का अनुपात	71.3	85.6	100.6	103.0
6. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज (मूल परिपक्वता) का अनुपात	33.1	22.4	17.5	18.1
7. आरक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का अनुपात	59.0	49.6	43.8	43.1
8. आयात का आरक्षित कवर (महीनों में) *	7.0	12.0	17.4	13.1
9. कर्ज चुकौती अनुपात (चालू प्रामियों की तुलना में कर्ज चुकौती)	5.9	6.5	8.2	4.9
10. विदेशी कर्ज (बिलियन अमेरिकी डॉलर \$)	409.4	558.3	573.7	614.9
11. निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (एनआईआईपी) (बिलियन अमेरिकी डॉलर \$)	-326.7	-375.4	-355.3	-357.9
12. एनआईआईपी/जीडीपी अनुपात	-17.8	-14.1	-13.2	-11.7
13. सीएबी/जीडीपी अनुपात	-4.8	-0.9	0.9	-1.2

*: भुगतान संतुलन के आंकड़ों में प्रकाशित नवीनतम चार तिमाहियों के व्यापारिक सामानों के आयात पर आधारित

टिप्पणी: कॉलम 5 में सीएबी/जीडीपी अनुपात अप्रैल-दिसंबर 2021 से संबंधित है।

स्रोत: आरबीआई और भारत सरकार

II.6.43 मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 607.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसे अगस्त 2021 में आईएमएफ के सामान्य एसडीआर आबंटन से भारत को एसडीआर 12.57 बिलियन प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 में भारत का आरक्षित निधि संग्रहण (मूल्यांकन परिवर्तन को लेकर) 30.3 बिलियन अमेरिकी डालर था।

7. निष्कर्ष

II.6.44 आने वाले समय में, भारत के बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों से भरे रहने की संभावना है। उत्तरार्द्ध के अंतर्गत, निर्यात, जिसने विषम व्यापार वातावरण में आघात-सहनीयता दिखाई है, को और मजबूती मिल सकती है क्योंकि बाहरी मांग और कीमतों की स्थिति भू-

राजनीतिक तनाव के कम होने के साथ अनुकूल हो सकती है। वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घरेलू नीतिगत उपायों को भी महत्त्व दिया गया है। अधोगामी जोखिम प्रमुख एई और ईएमई में विकास की संभावित धीमी गति, ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और तनावपूर्ण भू-राजनीतिक वातावरण में आपूर्ति-पक्ष व्यवधानों से उत्पन्न होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति की वजह से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सख्त मौद्रिक नीति भी उभरते बाजारों में वित्तीय स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। फिर भी, बाह्य सुभेद्यता संकेतक मजबूती की ओर इशारा करते हैं और घरेलू समष्टि-आर्थिक बुनियादी बातों को मजबूत करने से अर्थव्यवस्था को संभावित प्रतिकूल समष्टि वैश्विक - वित्तीय आघातों से निपटने में मदद मिलेगी।